ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 17 | सितंबर 2023 / Issue 01 | मूल्य : ₹ 70

dhyeyaias.com

दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में शांति सुरक्षा के लिए मजबूत होते भारत-श्रीलंका संबंध

डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणा वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना विकास में एक क्रांतिकारी कदम

औपनिवेशिक कानूनों आईपीसी व सीआरपीसी की जगह लाए गए नए कानूनों के मायने

लैंगिक रूढ़िवादिता प्रदर्शित करने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला

महिला सशक्तीकरण में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन

भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की रणनीति और पहल

भारत में पनबिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ते कदमः संभावनाएं और चुनौतियां

मुख्य परीक्षा विशेषः केस स्टडी

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्राय: सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंतत: वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही केस स्टडी खंड के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम PMI (Pre + Mains + Interview) की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

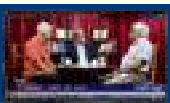

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

पहला पन्ना

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग : दीपक त्रिपाठी
: ऋषिका, प्रमोद
: प्रत्यूषा, पूर्णाशी
: रत्नेश, अर्पित
: तपस्या, अर्शदीप
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : नितिन अस्थना
: शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं डेवलेपमेंट : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
सोशल मीडिया सहयोग : केशरी पाण्डेय
: जीवन ज्योति
मार्केटिंग सहयोग : रवीश, प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-18

1. डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणा वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना विकास में एक क्रांतिकारी कदम
2. दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में शांति सुरक्षा के लिए मजबूत होते भारत-श्रीलंका संबंध
3. महिला सशक्तीकरण में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन
4. औपनिवेशिक कानूनों आईपीसी व सीआरपीसी की जगह लाए गए नए कानूनों के मायने
5. लैंगिक रूढ़िवादिता प्रदर्शित करने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला
6. भारत में पनबिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ते कदम: संभावनाएं और चुनौतियां
7. भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की रणनीति और पहल

राष्ट्रीय 19-23
अंतर्राष्ट्रीय 24-28
पर्यावरण 29-32
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 33-37
आर्थिकी 38-42
विविध 43-47
मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न ..48
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 49-52
समसामयिक घटनाएं एक नजर में 53
ब्रेन-बूस्टर 54-60
मुख्य परीक्षा विशेष: केस स्टडी 61-66
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 67-70

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

आगामी अंक में

- अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जी-20 की भूमिका, चुनौतियां और संभावनाएं
- इसरो का आदित्य मिशन: भारत के स्पेस प्रोग्राम का अगला पड़ाव
- पूर्वोत्तर भारत में ड्रग्स तस्करी को रोकने में असम राइफल्स की अभूतपूर्व भूमिका
- भारत के संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में 'वन नेशन वन इलेक्शन' का औचित्य
- युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति: चुनौतियां और समाधान
- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियां
- पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती साख

डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणा: वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास में एक क्रांतिकारी कदम

``डिजिटल प्रौद्योगिकियां दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में जीवन, समाज और व्यवसायों के स्वरूप को बदल रही हैं। हम एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर हैं जहां सभी देश प्रौद्योगिकी के एकीकरण के साथ अपनी स्वास्थ्य सेवा वितरण को संरेखित कर रहे हैं। सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क, 15–16 दिसंबर 2015) ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में विभिन्न देशों की सरकारों के प्रौद्योगिकी–सक्षम सफलताओं पर प्रकाश डाला। डिजिटल स्वास्थ्य की असीम क्षमता सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति को तेज कर सकती है।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने गुजरात के गांधीनगर में जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस की उपस्थिति में 'डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल- एक डब्ल्यूएचओ प्रबंधित नेटवर्क' लॉन्च किया।

डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (GIDH):

- जीआईडीएच डब्ल्यूएचओ प्रबंधित एक नेटवर्क है जो डिजिटल स्वास्थ्य तक समान पहुंच को बढ़ावा देगा। यह चार मूलभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
  - डिजिटल स्वास्थ्य 2020-2025 पर वैश्विक रणनीति के साथ प्रयासों को संरेखित करना।
  - मानक-आधारित और इंटरऑपरेबल सिस्टम के लिए गुणवत्ता-सुनिश्चित तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - डिजिटल परिवर्तन उपकरणों के उपयोग की सुविधा प्रदान करना।
  - पारस्परिक जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- जीआईडीएच का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रयासों और निवेश को समेकित करना है जिससे एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। इस पहल का उद्देश्य सभी देशों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने तथा रोगियों को जन-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करना है।

डब्ल्यूएचओ और डिजिटल स्वास्थ्य:

- डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल डब्ल्यूएचओ की वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य रणनीति 2020-2025 का भी समर्थन करेगी। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति को 2020 में सदस्य राज्यों द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन की दिशा में एक रोडमैप को परिभाषित करते हुए कार्यों और लक्ष्यों को संरेखित करने के तरीके के रूप में समर्थन दिया गया था।
- WHO स्वास्थ्य और कल्याण की वैश्विक प्राप्ति में तेजी लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा स्वास्थ्य नवाचार की शक्ति का उपयोग कर रहा है। WHO के डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार को अपनाने तथा स्केल-अप को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - **नवीनतम डेटा, अनुसंधान और साक्ष्य का प्रयोग करना:** इसका मतलब इंटरऑपरेबिलिटी और डेटा साझाकरण के लिए मानकों को बढ़ावा देना तथा डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन का समर्थन करना है जो सूचित निर्णय लेने में योगदान करते हैं।
  - नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्त्व के विषयों पर शीर्ष विशेषज्ञ लोगों को एक साथ लाकर वैज्ञानिक समुदायों के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना।
  - नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ देश की जरूरतों का व्यवस्थित रूप से आंकलन करना और उन्हें जोड़ना। डब्ल्यूएचओ देश की जरूरतों पर आधारित नवाचारों की पहचान करने, बढ़ावा देने, सह-विकास पर एक सक्रिय तथा व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाता है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 2020 में अपनाई गई डिजिटल स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक रणनीति, नवाचार और डिजिटल स्वास्थ्य में नवीनतम विकास को जोड़ने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती है तथा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए इन उपकरणों को कार्यवाही में डालती है।
- डिजिटल स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक रणनीति का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और सभी के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि को प्राप्त करने में देशों का समर्थन करना है।

डिजिटल स्वास्थ्य पर विश्व बैंक की रिपोर्ट:

- जीआईडीएच का शुभारंभ विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट 'स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल को सभी के लिए अनलॉक करना' के विमोचन के साथ हुआ। यह रिपोर्ट डिजिटल स्वास्थ्य कार्यान्वयन को किकस्टार्ट करने में देशों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट में एक नए डिजिटल-इन-हेल्थ दृष्टिकोण का आह्वान किया गया है जहां बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन तथा स्वास्थ्य सेवा वितरण के हर पहलू में डिजिटल तकनीक और डेटा को शामिल किया जाता है। इसके अलावा साक्ष्य-आधारित डिजिटल निवेश सरकारों को स्वास्थ्य प्रणाली की लागत का 15% तक बचाने में मदद कर सकता है।

डिजिटल स्वास्थ्य:

- डिजिटल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, प्रयोग करने योग्य चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा उपकरण के रूप में सॉफ्टवेयर (एसएएमडी), व्यक्तिगत चिकित्सा, मोबाइल स्वास्थ्य (एमहेल्थ), टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ सहित विभिन्न प्रकार की डिजिटल स्वास्थ्य

प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित उपयोगों के लिए कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर और सेंसर का उपयोग करती हैं। यह स्वास्थ्य प्रणालियों को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान किया जा सके।

डिजिटल स्वास्थ्य की प्रासंगिकता:

बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हेतु डिजिटल स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण है। स्वास्थ्य डेटा का उचित व सुरक्षित उपयोग करने और रोगी की गोपनीयता के लिए उचित कानूनी तथा तकनीकी सुरक्षा उपाय सूचित सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति हेतु अधिक रणनीतिक स्वास्थ्य वित्तपोषण मॉडल का समर्थन कर सकते हैं।

- यह मानक-आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के निर्माण का समर्थन कर सकता है।
- वास्तविक समय के सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को सक्षम बना सकता है।
- नैदानिक निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से देखभाल की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
- रोगियों द्वारा स्वास्थ्य के आत्म-प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा।
- डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों को समय बचाने, सटीकता और दक्षता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों में एआई का उपयोग मानव निर्णय लेने में वृद्धि कर सकता है।
- रोगी के रिकॉर्ड का विश्लेषण करके, चिकित्सा सॉफ्टवेयर रोगी के स्वास्थ्य की विसंगतियों का पता लगाकर स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों को संभावित दवा की त्रुटि के बारे में सूचित कर सकता है।
- डिजिटल स्वास्थ्य में बीमारी को रोकने तथा स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने की क्षमता है जिससे रोगियों को पुरानी स्थितियों की निगरानी और प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।
- डिजिटल हेल्थकेयर के सबसे बड़े लाभों में से एक टेलीमेडिसिन है। इसे बड़े पैमाने पर अपनाने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रोगी (जो स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहे) अब सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सकते हैं। नवीन तकनीक की मदद से वे अब ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं।

भारत में डिजिटल स्वास्थ्य:

- भारत डिजिटल समाधान और नवाचार को बढ़ावा देकर डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा और क्षमताएं जैसे कि मोबाइल ऐप, टेलीमेडिसिन, स्थान या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ा सकते हैं।
- नीति आयोग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक (Stack) तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट पर हाल ही में जारी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा, व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड वाले एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी की अवधारणा की गई है।
- भारत ने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य समाधानों तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक पहलों के रूप में को-विन, ई-संजीवनी और आरोग्य सेतु एप्लिकेशन लांच किया है। टेली-परामर्श प्लेटफॉर्म तथा ई-संजीवनी ने 100 मिलियन टेलीकंसल्टेशन को पार कर लिया। को-विन और आरोग्य सेतु के तहत वैक्सीन प्रबंधन अभियान ने 2.2 बिलियन से अधिक खुराक का प्रशासन हासिल किया। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ने 500 मिलियन नागरिकों को कैशलेस और पेपरलेस तरीके से मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाया। यह भारत में एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना करता है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है।

डिजिटल स्वास्थ्य की चुनौतियां:

- स्वास्थ्य सेवा के डिजिटल परिवर्तन ने कई चुनौतियों को बढ़ाया है जो रोगियों, चिकित्सा पेशेवरों, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रणालियों से एकत्र किए गए डेटा की भारी मात्रा के कारण डेटा इंटरऑपरेबिलिटी एक सतत चुनौती है।
- अतिरिक्त चुनौतियां रोगियों के बीच डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल तक असमान पहुंच, डेटा भंडारण, पहुंच, साझाकरण और स्वामित्व से संबंधित मुद्दों से संबंधित चिंताओं के रूप में हैं।
- अन्य चिंताएं प्रौद्योगिकी और नैतिकता से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए जब चिकित्सा रोबोट का उपयोग किया जाता है, तो सर्जरी के दौरान की गई गलतियों के लिए कौन जिम्मेदार है: अस्पताल, प्रौद्योगिकी डेवलपर या निर्माता, डॉक्टर जिसने रोबोट का उपयोग किया?
- भारत में ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में असमानता बहुत बड़ी है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का 75% से अधिक मेट्रोपॉलिटन शहरों में केंद्रित है, जहां कुल आबादी का केवल 27% रहता है, अतिरिक्त 73% भारतीय आबादी में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है।

निष्कर्ष:

डिजिटल स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में एक अच्छा विकल्प है जिसमें समग्र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों का समर्थन करने की क्षमता है। डिजिटल समाधान स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और लोगों को इस तरह से लाभान्वित करना चाहिए जो नैतिक, सुरक्षित, सुरक्षित, विश्वसनीय, न्यायसंगत और टिकाऊ हो। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं और एआई जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके स्वास्थ्य देखभाल में इक्विटी को बढ़ावा देगी। जीआईडीएच किसी को पीछे न छोड़ते हुए समावेशिता और एकीकरण सुनिश्चित करेगा।

दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में शांति सुरक्षा के लिए मजबूत होते भारत-श्रीलंका संबंध

भारत और श्रीलंका ने हाल ही में अपने राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इसके साथ ही भारतीय मूल के तमिल समुदाय ने श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे किए हैं। इस विशेष अवसर पर भारत से विविध मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की यात्रा की। श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी। भारत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में श्रीलंका को आधिकारिक तौर पर डोर्नियर-228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में श्रीलंका पर विशेष ध्यान देता है। हिंद महासागर में श्रीलंका को कई चुनौतियों से मुक्त कराने की दिशा में भारत समय-समय पर कार्य करता रहा है।

- भारत और श्रीलंका ने आर्थिक साझेदारी के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। इसके जरिए पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में दोनों ही देश आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही दोनों देशों ने इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हुई द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भरोसा दिया कि भारत संकट की इस घड़ी में आगे भी श्रीलंका को मदद करता रहेगा।
- भारत-श्रीलंका ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांकेसनथुराई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विसेज शुरू करने, चेन्नई-जाफना के बीच उड़ानों के फिर से शुरू होने का निर्णय किया है जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक अंतरसंपर्कों को अवश्य बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा सहयोग को लेकर भी भारत और श्रीलंका के बीच महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दोनों देश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जोड़ने के काम में तेजी लाने पर सहमत हुए जिसमें पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने का निर्णय लिया गया। इसकी संभावना को खोजने के लिए भारत-श्रीलंका ने फिजिबिलिटी स्टडी करने का भी निर्णय किया है। इसके अलावा लैंड ब्रिज की व्यवहार्यता की पड़ताल को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। दोनों देशों ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ETCA) पर जल्द ही बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। भारत का मानना है कि इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। दोनों देशों ने यह भी भरोसा जताया है कि श्रीलंका में UPI लॉन्च के लिए हुए समझौते से फिनटेक कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- श्रीलंका का चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता अभी नहीं है। इसका केवल भारत, पाकिस्तान और सिंगापुर के साथ ऐसा समझौता है। श्रीलंका, थाईलैंड और चीन जैसे देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता करने पर विचार कर रहा था, लेकिन अभी अपनी आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक संप्रभुता का आंकलन करते हुए ऐसे किसी निर्णय में जल्दीबाजी न दिखाने का निर्णय किया है। वर्ष 2019 में ही श्रीलंका ने अपनी मुक्त व्यापार समझौता नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया था।

भारत-श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक:

- भारत-श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यताओं के मध्य अंतर्संपर्क की दृष्टि से मजबूत आधार वाले रहे हैं। दोनों देशों के संबंध 2500 वर्ष से अधिक पुराने हैं। प्राचीन समय से ही दोनों देशों के मध्य धार्मिक, बौद्धिक और भाषाई अंतर्संपर्क होते रहे हैं। प्राचीन समय में मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र कुणाल और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। रामायण के विवरण भी दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। तमिलनाडु के तमिलों का श्रीलंका से संबंध भी दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख आधार रहा है।
- भारत और श्रीलंका के संबंधों को भौगोलिक कारकों ने महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। श्रीलंका की हिंद महासागर में सामरिक स्थिति ने भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई है। हिंद महासागर में श्रीलंका, भारत का निकटतम पड़ोसी है और श्रीलंका का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अधिक विस्तृत होने के चलते यह भारत के साथ नीली अर्थव्यवस्था अथवा महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- श्रीलंका का विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र मत्स्य संसाधन के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, वहीं श्रीलंका एशिया महाद्वीप और दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का हिस्सा है जो सार्क के प्रमुख सदस्य के रूप में दक्षिण एशिया की शांति, स्थिरता, सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है। तमिलनाडु से श्रीलंका की भौगोलिक नजदीकी और सांस्कृतिक संबंध ने दोनों देशों को वैदेशिक स्तर पर प्रभावित किया है।
- भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी की अवस्थिति, पाक जलडमरूमध्य, मंडपम, पंबन द्वीप, कच्चाथिवू द्वीप की स्थिति, तलैया मन्नार की स्थिति, रामेश्वरम, ऐडम्स ब्रिज जैसे स्थलों की अवस्थितियों ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। इन सभी स्थलों ने भारत और श्रीलंका के मध्य मछुआरों की समस्याओं को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाई है जिससे भारत-श्रीलंका के संबंधों पर समय-समय पर नकारात्मक असर पड़ा है।

दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता सहयोगः

- भारत की विदेश नीति में पड़ोसी प्रथम नीति का विशेष महत्त्व है। इसके साथ ही 'सागर' विजन भी भारतीय विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इन दोनों में श्रीलंका का एक प्रमुख स्थान है। भारत हिंद महासागर में अपनी द्वीपीय कूटनीतिक सफलता के लिए भी श्रीलंका के साथ अच्छे संबंधों को आवश्यक मानता है। दोनों देश सार्क संगठन के सदस्य हैं और सार्क के मंच पर आतंकवाद निरोधी सहयोग तथा तस्करी रोधी अभियानों पर सहयोग करते रहे हैं। जब से सार्क समिट का आयोजन होना बंद हुआ है, तब से दोनों देशों ने बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है।
- कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य के रूप में भी भारत और श्रीलंका दक्षिण एशिया के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में विविध सुरक्षा तथा व्यापारिक चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य देश हैं। 2022 में मॉरीशस को इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया है। इसमें विशेष बात यह है कि ये देश भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति, भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड की नीति, सागर विजन, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और द्वीपीय कूटनीति का अंग हैं। हिन्द महासागर में भारत के समुद्री व्यापारिक हितों के लिहाज से इनका काफी महत्त्व है। कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं: बांग्लादेश और सेशेल्स। कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सचिवालय श्रीलंका के कोलम्बो में स्थित है।
- 2011 में इसकी शुरुआत एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा की गई थी। यह हिन्द महासागर की सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने वाला मंच है। कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव निम्न क्षेत्रों में सहयोग करता है:
  - मेरीटाइम सेफ्टी
  - काउंटर टेररिज्म
  - कट्टरता विरोधी सहयोग यानी काउंटर रेडक्लाइजेशन
  - तस्करी और संगठित अपराधों से निपटना
  - साइबर सुरक्षा
  - मानवतावादी सहायता
  - आपदा राहत सहायता

दक्षिण एशिया में शांति सुरक्षा के लिए तमिल मुद्दे का समाधान आवश्यकः

- श्रीलंका में तमिल और सिंहली भाषी के बीच विवाद ने लिट्टे जैसे संगठनों को जन्म दिया जिसका प्रभाव भारत सहित दक्षिण एशिया के अलगाववादी आंदोलनों पर पड़ा। श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव और राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच संबंधों का वह पहलू है जिससे बीच-बीच में कड़वाहट पैदा होता रहा है। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक स्वायत्तता की मांग काफी पुरानी है। इस मांग का हल निकालने के लिए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने दिसंबर 2022 में तमिल नेशनल अलायंस (TNA) के साथ बातचीत शुरू की थी। तमिल बहुल श्रीलंका के उत्तर और पूर्व के इलाकों में ये लोग पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं जिसका सिंहली समुदाय की ओर से विरोध होता रहा है। श्रीलंका में करीब 75 फीसदी सिंहली और 11 फीसदी श्रीलंकाई तमिल हैं।
- भारत हमेशा से श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने का हिमायती रहा है। इसके जरिए तमिल लोगों की मांग को पूरा करने के लिए प्रांतीय परिषदों को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है। इसे 1987 में शामिल किया गया था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। जब से रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने हैं, वे इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि 13वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने के उनके विचारों का प्रभावशाली बौद्ध धार्मिक नेताओं ने विरोध किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच हाल ही में इस मसले पर भी बातचीत हुई थी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भरोसा जताया था कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी तथा समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। भारत ने यह भी उम्मीद की है कि श्रीलंकाई सरकार तेरहवें संशोधन को लागू करने और प्रांतीय परिषद का चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। रानिल विक्रमसिंघे के दौरे पर भारत ने ऐलान किया है कि श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत के अलग-अलग प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। भारत ने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में योगदान देने का भी ऐलान किया है।
- इस तरह भारत का मानना है कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर व समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के रूप में, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की स्थिरता तथा विकास के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भारत ने लगातार आर्थिक संकट से निकलने में श्रीलंका को वित्तीय मदद, विकासात्मक सहायता तथा मानवतावादी सहायता प्रदान किया है।

महिला सशक्तीकरण में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन

स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने हमारे राष्ट्र की प्रगति की गाथा लिखने में महिलाओं द्वारा निभाई गई अपूरणीय भूमिका को नमन किया। दूरदर्शी उत्साह के साथ उन्होंने एक साहसिक महत्त्वाकांक्षा की शुरूआत की। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दो करोड़ 'लखपति दीदी' बनाना, सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकार भारत को आगे ले जाएगी और जी-20 ने भी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।

स्वयं सहायता समूह (SHG) क्या हैं?

- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समुदाय-आधारित संगठन होते हैं जो लोगों के एक छोटे समूह, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने संसाधनों को इकट्ठा करने और पारस्परिक समर्थन तथा आर्थिक उत्थान के लिए मिलकर काम करने के उद्देश्य से गठित किए जाते हैं। एसएचजी में आम तौर पर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से 10 से 20 सदस्य होते हैं जो आम चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं।
- सामाजिक विकास के बहु-आयामी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एसएचजी खाद्य, पोषण और स्वच्छता गतिविधियों में सेवाओं के लिए जागरूकता सृजन, व्यवहार परिवर्तन और मांग सृजन में गहन रूप से शामिल हैं। एसएचजी एक सहायक वातावरण बनाकर नेतृत्व, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। वे वित्त से परे महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, मानदंडों को चुनौती देते हैं और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देते हैं। अंततः एसएचजी समग्र महिला सशक्तीकरण को उत्प्रेरित करते हैं तथा व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को लाभान्वित करते हैं।
- उदाहरण के लिए केरल के एसएचजी नेटवर्क कुडुंबश्री ने माइक्रोफाइनेंस, माइक्रोएंटरप्राइज, सामाजिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य पहल सहित कई क्षेत्रों में COVID-19 के दौरान व्यापक सामुदायिक प्रतिक्रिया विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका:

- **सूक्ष्म वित्त और बचत:** एसएचजी के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक सदस्यों को नियमित रूप से छोटी राशि बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन बचतों का उपयोग सामूहिक रूप से विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों हेतु सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन:** एसएचजी अपने सदस्यों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित होती है। समूह के भीतर नियमित बचत और ऋण सुविधाओं के माध्यम से सदस्यों को संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना क्रेडिट तक पहुंच प्राप्त होती है।
- **क्षमता निर्माण:** एसएचजी प्रशिक्षण और कौशल विकास सत्रों के माध्यम से अपने सदस्यों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सदस्यों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों, वित्तीय प्रबंधन और अन्य प्रासंगिक कौशल के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है।
- **आय सृजन:** एसएचजी अपने सदस्यों को छोटे पैमाने पर कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और अधिक आय पैदा करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समूह के बचत पूल से ऋण सदस्यों को इन उद्यमों को शुरू करने या विस्तारित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
- **सशक्तीकरण:** एसएचजी महिलाओं को अपनी चिंताओं को आवाज देने, सामूहिक रूप से निर्णय लेने और उनके वित्त का प्रबंधन करने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाते हैं। इस बढ़ी हुई भागीदारी से सदस्यों के बीच आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार होता है।
- **सामाजिक सहायता:** आर्थिक लक्ष्यों के अलावा एसएचजी अपने सदस्यों को सामाजिक सहायता भी प्रदान करते हैं। वे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विकास जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने तथा संबोधित करने के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं।
- **सरकारी योजनाओं से जुड़ाव:** एसएचजी अक्सर अपने सदस्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, अनुदान और अन्य लाभों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं।

एसएचजी का समर्थन करने के लिए सरकार की पहल:

- **एनआरएलएम और आय लक्ष्य:** सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लिए प्रतिबद्ध है जिसका उद्देश्य 2024 तक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में प्रत्येक महिला की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये तक बढ़ाना है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और एसएचजी के भीतर पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **उद्यमिता की ओर बदलाव:** अनुदान-आधारित दृष्टिकोण से दूर जाते हुए सरकार एसएचजी का समर्थन करने के लिए ऋण प्रदान करने और बाजार पहुंच में सुधार करने की दिशा में बदलाव पर जोर दे रही है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।
- **विविध भूमिका निभाने के लिए सखियां:** एसएचजी को एक बहुमुखी भूमिका निभाने की कल्पना की जाती है। एसएचजी

में महिलाएं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बैंक सखियों, किसान सखियों और पशु सखियों जैसी भूमिकाओं में संलग्न हैं। इसका लक्ष्य कृषि, पशुपालन, बाजरा की खेती और बागवानी जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है जो नए अवसर प्रदान करता है।

- **मिशन 1 लाख, 2024:** सरकार महिला किसान उत्पादक कंपनियों और क्लस्टरों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 'मिशन 1 लाख, 2024' शुरू कर रही है। यह फ्लिपकार्ट और अमेजॅन जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि इन समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ा जा सके। सरकार की सहायता में कौशल उन्नयन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सहायता शामिल है।
- **ड्रोन की उड़ान:** पीएम ने कहा कि 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के संचालन और मरम्मत के लिए ऋण तथा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा 'ड्रोन की उड़ान' किया जाएगा।
- **लखपति दीदी पहल:** इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रदान करना और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है।

लखपति दीदी महिलाओं को कैसे सशक्त बना सकती हैं?

- **आर्थिक सशक्तीकरण:** 'लखपति दीदी' योजना के तहत, एसएचजी से संबंधित महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका लक्ष्य उन्हें 1 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय प्राप्त करने, उनकी आय को दोगुना करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करना है।
- **बाजार पहुंच:** यह पहल इन महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने का प्रयास करती है। अमेजॅन, फ्लिपकार्ट और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ-साथ गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के साथ साझेदारी स्थापित की जा रही है ताकि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उचित बाजार प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।
- **वर्तमान प्रभाव:** प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग 10 करोड़ महिलाएं पहले से ही महिला स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में 'बैंक के साथ दीदी' और 'आंगनवाड़ी के साथ दीदी' जैसी पहलों में उनकी सक्रिय भागीदारी सभी हितधारकों के लिए सकारात्मक परिणाम दिखाया है।
- **भविष्य के लिए दृष्टिकोण:** प्रधानमंत्री ने गांवों में 2 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने की कल्पना की है। वे ग्रामीण महिलाओं की अपार क्षमता को पहचानते हैं और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। एग्रीटेक को मजबूत करके और स्वयं सहायता समूहों के भीतर प्रशिक्षण प्रदान करके, उनका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास और समग्र विकास को उत्प्रेरित करना है।

एसएचजी के सामने चुनौतियां:

- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी प्रभावशीलता और स्थिरता को बाधित कर सकते हैं।
- **वित्तीय बाधाएं:** किफायती ऋण तक सीमित पहुंच और उच्च ब्याज दरें स्वयं सहायता समूहों की आय पैदा करने वाली गतिविधियों को निधि देने की क्षमता को सीमित करती हैं।
- **कौशल की कमी:** अपर्याप्त प्रशिक्षण और ज्ञान प्रभावी उद्यम प्रबंधन में बाधा डालते हैं तथा उद्यमों की सफलता को प्रभावित करते हैं।
- **बाजार की बाधाएं:** बाजार लिंकेज बेहतर न होना और विपणन रणनीतियों की कमी उत्पाद पहुंच तथा लाभप्रदता को प्रतिबंधित करती है।
- **संस्थागत समर्थन:** सरकारी निकायों और गैर-सरकारी संगठनों से असंगत मार्गदर्शन एसएचजी की बाधाओं को नेविगेट करने की क्षमता को बाधित करता है।
- **लैंगिक पूर्वाग्रह:** गहरे मानदंड एसएचजी के भीतर महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने को सीमित करते हैं।
- ये चुनौतियां वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बाजार पहुंच, हितधारक सहयोग और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली व्यापक नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

आगे की राह:

- महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह हमारे देश की रीढ़ हैं। उनकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक नीति कार्यान्वित की जानी चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका बनाए रख सकें, लेकिन एसएचजी के लिए नीतियां अभी भी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हैं। महिलाओं को पारंपरिक कदाचारों के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें व्यवसाय के सभी पहलुओं में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने से रोकते हैं।
- भारत में एसएचजी के लिए प्रभावी नीतियां बनाना महत्त्वपूर्ण है। नीति निर्माताओं को सूचित आधारभूत अध्ययनों पर भरोसा करना चाहिए, महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों से निपटना चाहिए और परियोजनाओं को धीरे-धीरे लागू करना चाहिए। हालांकि वित्तीय सहायता अपर्याप्त है तथा बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और मेंटरशिप महत्त्वपूर्ण हैं।
- सहयोग, निगरानी ढांचे और हितधारक भागीदारी सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। सीएसआर, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण और बैंक समर्थन विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। संस्थान नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि नीतियों को वित्तीय स्थिरता, क्षेत्रीय विकास और तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंततः एसएचजी को संस्थागत समर्थन और उनकी क्षमता की मान्यता की आवश्यकता होती है जो स्थायी प्रगति के लिए एक बहु-विषयक समिति और मेंटरशिप पहल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

औपनिवेशिक कानूनों आईपीसी व सीआरपीसी की जगह लाए गए नए कानूनों के मायने

वर्तमान केंद्र सरकार लंबे समय से इस बात पर विचार कर रही थी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के कानूनों को आज के समय में बनाए रखना उचित है या नहीं। इसीलिए समय-समय पर पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा समितियों का भी गठन किया गया क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए आपराधिक कानूनों की समीक्षा अधिक आवश्यक हो गई थी। भारतीय दंड संहिता जिसे अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था, वह उस समय की परिस्थितियों और चुनौतियों के लिहाज से बना था। उस दौर में अपराध और अपराधी अलग प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति, हिंसा, विद्रोह या दंगा करने वालों के लिए दंड देने का प्रावधान ब्रिटिशर्स ने किया। तब से लेकर अब तक हत्या, लूट, आगजनी, आपराधिक षड्यंत्र और आर्थिक अपराधों की प्रकृति में बड़ा अंतर देखा गया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की प्रकृति में भी बड़े स्तर पर बदलाव और गंभीरता देखी गई है। इसलिए नए सिरे से कानूनों को बनाने या उन्हें पुनर्परिभाषित करने की जरूरत महसूस की गई है।

- केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटिश गुलामी की निशानियों को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। इसी कड़ी में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड-1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (1898)-1973 तथा इंडियन एवीडेंस एक्ट-1872 कानूनों में केंद्र सरकार ने कई विसंगतियां देखी हैं जिसके चलते इन सभी कानूनों को खत्म करके इनके स्थान पर नए आपराधिक कानूनों को लाने का फैसला लिया गया है। इसीलिए हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 लोक सभा में प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। भारत सरकार का मानना है कि समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब जो तीन नए कानून बनाए जा रहे हैं, उनका मूल लक्ष्य भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना होगा। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को खत्म करने का अति महत्त्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
- केंद्र सरकार नए आपराधिक कानूनों के जरिए राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त करने वाला फैसला दूरगामी परिणाम वाला साबित होगा।

भारत में आपराधिक कानूनों को नए सिरे से प्रबंधित करने का प्रावधानः

ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे जिन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त करके अब केंद्र सरकार नए कानून लेकर आ रही है जिसके प्रस्तावित प्रावधान अग्रलिखित हैं:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (जो CrPC को रिप्लेस करेगी) में अब 533 धाराएं रहेंगी जिसमें 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है।
- भारतीय न्याय संहिता (जो IPC को रिप्लेस करेगी) में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी जिसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है।
- भारतीय साक्ष्य विधेयक (जो Evidence Act को रिप्लेस करेगा) में पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी जिसमें 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं।

- कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करके इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजे को कानूनी वैधता दी गई है। FIR से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है।
- इस कानून को न्यायोचित बनाने और उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से काम करने के लिए एक विशेष प्रावधान

किया गया है। इसमें नया प्रावधान यह है कि सर्च और जब्ती के समय वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया गया है जो केस का हिस्सा होगी जिससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

- 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी किया जा रहा है जिसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा। इसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
- पहली बार ई-FIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा।
- यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है, साथ ही यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपल्सरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपल्सरी होगा।

आरोप पत्र और आरोपित व्यक्ति के संबंध में नए प्रावधान:

- अपराध की स्थिति में सबसे जरूरी प्रक्रिया है अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना और आरोपपत्र दाखिल करने का तरीका इस प्रकार का होना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से झूठे मामले में न फसाया जा सके तथा चार्जशीट फाइल करने वाले प्राधिकारी गलत आरोप पत्र न दायर करें। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए आपराधिक कानूनों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमीशन दे सकेंगी, इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर नया दंड विधान:

- केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों में यह नया प्रावधान किया है कि शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे तथा गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन की स्नेचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान नए कानून में रखा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

नए कानून में आतंकवाद की व्याख्या:

- भारत के पास जो भी ब्रिटिशकालीन आपराधिक कानून रहे हैं, उनमें पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी लेकिन अब जब भारतीय दंड संहिता, 1860 को हटा कर भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है तो उसमें आतंकवाद और इसके दायरे की व्याख्या की गई है। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। इसके अलावा अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरूद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान भी किया गया है। मॉब लिंचिग जैसे जघन्य अपराधों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है।
- गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति और मामूली चोट लगने के दोनों मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए अपंगता या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हिरासत में से भाग जाने वाले अपराधियों के लिए भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे, परन्तु अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा।

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया और दृष्टिकोण दोनों में बदलाव:

- केंद्र सरकार का मानना है कि अभी के कानूनों में मानव हत्या या स्त्री के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया और राजद्रोह, खजाने की लूट तथा शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया। केंद्र सरकार इस अप्रोच को बदल रही है और इन नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं तथा बच्चों के साथ अपराध पर होगा। दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों पर होगा। भारत सरकार का मत है कि शासन की जगह नागरिक को केन्द्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय करके ये कानून लाए गए हैं जिसका भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

लैंगिक रूढ़िवादिता प्रदर्शित करने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला

लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' नामक एक पुस्तिका जारी की है। यह पुस्तिका न्यायिक प्रणाली और कानूनी समुदाय के भीतर मौजूद गहरी अंतर्निहित लैंगिक रूढ़ियों को संबोधित करने और मिटाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में यह हैंडबुक न्यायिक फैसलों में निष्पक्ष भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है जो सभी के लिए निष्पक्षता और न्याय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानना:

- **न्यायसंगत न्याय के लिए मुख्य न्यायाधीश का आह्वान:** मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की हैंडबुक के प्रकाशन की घोषणा एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि न्यायिक निर्णय लेने में लैंगिक रूढ़ियों का उपयोग न्यायाधीशों के मौलिक कर्त्तव्य के विपरीत है अर्थात प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके अद्वितीय गुणों के आधार पर होना चाहिए।
- **रूढ़ियों का विकृत प्रभाव:** हैंडबुक लैंगिक रूढ़ियों की व्यापक प्रकृति को स्वीकार करती है जो अक्सर विकृत कानूनी परिणामों की ओर ले जाती है। ये समानता और न्याय के सिद्धांतों से समझौता करते हैं। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों से पूर्वनिर्धारित धारणाओं पर सवाल उठाने और निष्पक्षता के साथ मामलों पर विचार करने का आग्रह करके इन विकृतियों का मुकाबला कैसे किया जाए? इस पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

हैंडबुक का अनावरण: एक प्रतिमान बदलाव

- **रूढ़िवादी भाषा को उजागर करना:** 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' न्यायाधीशों और कानूनी चिकित्सकों के लिए कानूनी दस्तावेजों के भीतर मौजूद लिंग-आधारित रूढ़ियों को पहचानने, समझने और उनका मुकाबला करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह सामान्य वाक्यांशों और शब्दों का प्रयोग करता है जो महिलाओं की भूमिकाओं तथा विशेषताओं के बारे में पुरातन धारणाओं को बनाए रखते हैं।
- **तटस्थ शब्दावली को सशक्त बनाना:** हैंडबुक लैंगिक-पक्षपाती भाषा को तटस्थ, सटीक और सम्मानजनक शब्दों के साथ बदलने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। यह शब्दावली के उपयोग की वकालत करता है जो जेंडर पर समकालीन दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है और समानता के सिद्धांतों को बरकरार रखता है। उदाहरण के लिए हैंडबुक में 'करियर महिला' के बजाय 'महिला' के उपयोग का प्रस्ताव है ताकि यह पहचाना जा सके कि महिलाओं के करियर पुरुषों के रूप में मान्य और विविधरुपी हैं।

जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है?

- लैंगिक रूढ़ियाँ जो समाजों के भीतर गहराई से अंतर्निहित हैं, ये हानिकारक और पूर्वाग्रही धारणाएं हैं जो व्यक्तियों को केवल उनके लैंगिक पहचान के आधार पर विशिष्ट भूमिकाएं, विशेषताएं तथा व्यवहार निर्धारित करती हैं। ये रूढ़ियाँ असमानता को बनाए रखती हैं, अवसरों को सीमित करती हैं और सामाजिक प्रगति में बाधा डालती हैं। इन पूर्वाग्रहों पर काबू पाना एक अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है जो मानवीय गरिमा, समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखता है।

जेंडर स्टीरियोटाइप के हानिकारक प्रभाव:

- **अवसरों के स्पेक्ट्रम को संकुचित करना:** लैंगिक रूढ़ियां व्यक्तियों को संकीर्ण भूमिकाओं और अपेक्षाओं के भीतर सीमित करती हैं। महिलाओं को अक्सर रूढ़िबद्ध किया जाता है, जबकि पुरुषों से मजबूत और प्रभावशाली होने की उम्मीद की जाती है। यह विभिन्न अवसरों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करता है तथा व्यक्तिगत विकास और सामाजिक उन्नति पर अंकुश लगाता है।
- **व्यावसायिकता और क्षमता को कम करना:** महिलाओं को भावनाओं से और पुरुषों को तर्क से जोड़ने वाली रूढ़ियां इस भ्रम को कायम रखती हैं कि महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने के लिए आवश्यक तर्कसंगतता की कमी है। इस तरह की गलत धारणाएं पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति में बाधा डालती हैं और कांच की छत (मुहावरे के रूप में) को मजबूत करती हैं जो उनके करियर पथ को सीमित करती हैं।
- **जेंडर आधारित हिंसा को मजबूत करना:** हानिकारक लैंगिक रूढ़ियां पीड़ित-दोष की संस्कृति में योगदान करती हैं, खासकर यौन हिंसा के मामलों में। यह विश्वास है कि महिलाओं के कपड़े या व्यवहार उत्पीड़न को आमंत्रित करते हैं।

रूढ़ियों को मजबूत करने पर भाषाई प्रभाव:

- **शब्दों की शक्ति:** भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है जो सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है और आकार देता है। पक्षपाती भाषा रूढ़ियों को मजबूत करती है और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बनाए रखती है। लैंगिक-तटस्थता भाषा को व्यक्तियों द्वारा निभाई जाने वाली विविध और विकसित भूमिकाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।
- **न्यायिक परिप्रेक्ष्य:** कानूनी दायरे के भीतर लैंगिक रूढ़ियों का प्रभाव गहरा है। पक्षपातपूर्ण भाषा निर्णयों को दूषित कर सकती है और भेदभावपूर्ण परिणामों को बनाए रख सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' जैसी पहल इस मुद्दे को संबोधित करने में

महत्त्वपूर्ण हैं।

- लैंगिक रूढ़ियों पर काबू पाना एक सामूहिक प्रयास है जो सामाजिक, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तरों पर व्यापक परिवर्तन की मांग करता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, शिक्षा और नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है जो स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हैं। जैसा कि समाज इन रूढ़ियों को छोड़ देते हैं, वे सभी व्यक्तियों की पूरी क्षमता को अनलॉक करेंगे, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देंगे जहां हर कोई अपने जेंडर की परवाह किए बिना कामयाब हो सकता है। समानता की दिशा में यह प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य और अद्वितीय क्षमताओं की मान्यता एक अधिक न्यायपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर ले जाएगी।

कानूनी क्षेत्र में भाषा का महत्त्व:

- **मूल्यों के रूप में भाषा:** मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ कानूनी मूल्यों और धारणाओं पर भाषा के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। वह पिछले उदाहरणों को याद करते हैं जहां मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए भाषा में बदलाव किए गए थे। यह दर्शाता है कि भाषाई बदलाव विकसित सामाजिक मानदंडों और समावेशिता के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **संवैधानिक लोकाचार को बनाए रखना:** यहां तक कि जब रूढ़ियां परिणामों को प्रभावित नहीं करती हैं, तो हैंडबुक का तर्क है कि न्यायिक भाषा में उनकी उपस्थिति लैंगिक समानता के संवैधानिक लोकाचार के विपरीत है। न्यायाधीशों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा कानून और समाज दोनों की उनकी व्याख्या को दर्शाती है जिससे पूर्वाग्रह को बनाए रखने वाली भाषा को छोड़ना अनिवार्य हो जाता है।

वैश्विक पहल और भारत के शानदार प्रयास:

- **न्यायिक प्रथाओं के लिए एक वैश्विक दर्पण:** न्यायपालिका के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह का मुकाबला करने के प्रयास भारत की सीमाओं से परे फैले हुए हैं। कनाडा की महिला अदालत और भारतीय नारीवादी निर्णय परियोजना जैसी पहलों का उद्देश्य भेदभावपूर्ण भाषा तथा धारणाओं को चुनौती देते हुए नारीवादी लेंस के माध्यम से कानूनी निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करना है।

आगे की राह:

न्यायसंगत न्याय के लिए परिवर्तन को लागू करना:

- भारत की 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' का विमोचन कानूनी समुदाय के भीतर चेतना के एक नए युग की शुरुआत करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' का शुभारंभ कानूनी परिदृश्य के भीतर लैंगिक समानता के लिए चल रही लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अभूतपूर्व पहल पीढ़ियों से चली आ रही गहरी पैठ वाले पूर्वाग्रहों को संबोधित करने की अनिवार्यता को रेखांकित करके भाषा और धारणा दोनों को प्रभावित करती है।
- भाषा का परिवर्तन केवल एक सतही परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह समाज की विकसित चेतना और समझ का प्रतिबिंब है। मानव गरिमा को बनाए रखने में भाषा की ऐतिहासिक भूमिका पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का जोर एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि शब्दों में या तो भेदभाव को बनाए रखने या अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाने की अपार शक्ति है। पक्षपाती शब्दावली के मूर्त विकल्प पेश करने और न्यायाधीशों को तटस्थ तथा सम्मानजनक भाषा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का हैंडबुक का दृष्टिकोण लैंगिक रूढ़ियों को खत्म करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो कानूनी प्रवचन के भीतर गहराई से अंतर्निहित हैं।
- इस पहल का वैश्विक संदर्भ भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि भारत में कानूनी समुदाय अधिक समानता की ओर बढ़ रहा है। यह इसी तरह के वैश्विक प्रयासों में साहचर्य पाता है जो न्यायपालिकाओं के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देना चाहते हैं। कनाडा की महिला अदालत और भारतीय नारीवादी निर्णय परियोजना जैसी पहल भारतीय हैंडबुक की प्रतिध्वनि को बढ़ाती हैं और सामूहिक रूप से एक वैश्विक आंदोलन में योगदान करती हैं जो एक निष्पक्ष और न्यायसंगत कानूनी ढांचे के लिए प्रयास करता है।
- संक्षेप में 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' एक कानूनी दस्तावेज से कहीं अधिक है, यह कार्यवाही के लिए एक आह्वान है, परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक है और अधिक न्यायसंगत समाज को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप है। लैंगिक रूढ़ियों के हानिकारक प्रभाव और पक्षपाती भाषा की भूमिका को स्वीकार करके यह पुस्तिका इस विचार को मजबूत करती है कि कानूनी प्रणाली का विकास सामाजिक दृष्टिकोण के विकास से अविभाज्य है। जैसा कि कानूनी समुदाय इस परिवर्तन को गले लगाता है, यह आशा की किरण बन जाता है। न्यायाधीशों और कानूनी चिकित्सकों को गहरी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करके हैंडबुक इस सिद्धांत में जान फूंकती है कि न्याय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अंधा, निष्पक्ष तथा दृढ़ होना चाहिए।
- एक अधिक न्यायसंगत और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ने पर हैंडबुक प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय मूल्य तथा क्षमताओं की मान्यता को विकसित करती है और उन्हें लैंगिक रूढ़ियों की जंजीरों से मुक्त करती है। यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, लैंगिक भूमिकाओं की पूर्वधारणा से अप्रतिबंधित है। इस उल्लेखनीय पहल के साथ, भारत की न्यायपालिका पूर्वाग्रह के खिलाफ एक दृढ़ रुख अपनाती है, एक ऐसा रास्ता बनाने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करती है जहां जेंडर की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय वास्तव में प्रबल हो। 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' न केवल कानूनी प्रवचन में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि आशा, प्रगति और समानता की अदम्य भावना के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है।

भारत में जल विद्युत उत्पादनः संभावनाएँ और चुनौतियाँ

'हमें सीओपी 26 में हुई प्रगति पर रोक लग जाने का खतरा है। जब तक हम नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को मजबूत करने में जलविद्युत की भूमिका के बारे में गंभीरता से बात करना शुरू नहीं करते, तब तक हमारे जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना संभव नहीं होगा।' –मैल्कम टर्नबुल, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री

सन्दर्भः

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 11.5 गीगावॉट से अधिक की 12 हाइड्रो पावर परियोजनाएं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत हाइड्रो पीएसयू को सौंपी गई। इन परियोजनाओं से लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में 12 रुकी हुई पनबिजली परियोजनाओं को फिर से जीवंत करने और निष्पादित करने के लिए एक साथ आई हैं।

पृथ्वी पर नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्रोत के रूप में, जलवायु परिवर्तन से निपटने में जलविद्युत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी अन्य स्वच्छ तकनीक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को सक्षम करने के लिए बड़े पैमाने पर आवश्यक भंडारण और लचीलापन प्रदान नहीं कर सकती है। वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) की रिपोर्ट है कि हमें 2050 तक जलविद्युत क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता है।

भारत में जल विद्युत की संभावनाएँः

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश में अनुमानित जलविद्युत क्षमता लगभग 145 गीगावॉट है जिसमें से 42.6 गीगावॉट (29%) विकसित किया जा चुका है और 15.5 गीगावॉट (10.3%) निर्माणाधीन है। इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए) की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी पनबिजली क्षमता का 80% से अधिक विकसित किया है, वहीं यूरोपीय संघ ने अपनी 70% से अधिक जलविद्युत क्षमता विकसित की है। स्थापित क्षमता के मामले में भारत चीन, ब्राजील, अमेरिका और कनाडा के बाद दुनिया में पनबिजली का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है।

पनबिजली संयंत्र कैसे काम करता है?

- पनबिजली संयंत्र में जलाशय और पावर स्टेशन बनाने के लिए एक बड़ी नदी पर बांध बनाया जाता है जहां ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। बांध से बहता पानी टरबाइन नामक एक बड़े पहिये को घुमाता है जो गिरते पानी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद बिजली उत्पन्न होती है जिसे ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जबकि पानी को वापस जल निकाय में छोड़ दिया जाता है।

जल विद्युत के लाभः

- हाइड्रो परियोजनाओं का विकास 2030 तक भारत की 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के घोषित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा। हाइड्रो पावर वर्ष 2070 के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य में एक प्रभावी योगदानकर्ता होगा। .
- इन परियोजनाओं से देश में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र में कौशल विकास तथा तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।
- चूंकि अधिकांश जलविद्युत क्षमता हिमालय और उत्तर-पूर्व क्षेत्र की ऊंची पहुंच में स्थित है जिससे बिजली क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करके क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। यह परिवहन, पर्यटन और अन्य छोटे पैमाने के व्यवसायों के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार/उद्यमशीलता के अवसर भी प्रदान करेगा।
- इसके अलावा जलविद्युत जल सुरक्षा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण लाभ भी प्रदान करता है।
- जब इसे अच्छे पर्यावरण और सामाजिक प्रथाओं के अनुसार विकसित किया जाता है, तो जलविद्युत संयंत्रों को ऐसी बिजली का उत्पादन करने का लाभ होता है जो नवीकरणीय और स्वच्छ दोनों होती है। क्योंकि वे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन संयंत्रों की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और प्रदूषणकारी निलंबित कण पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करते हैं।
- जलविद्युत संयंत्र भी जल्दी शुरू और बंद हो सकते हैं जिससे ये विभिन्न मौसमों और दिन के अलग-अलग समय में मांग में व्यापक उतार-चढ़ाव का जवाब देने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। यह लचीलापन भारत जैसे अत्यधिक आबादी वाले देश में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है जहां घरेलू बिजली की मांग कुल मांग का एक प्रमुख हिस्सा है।
- यद्यपि जलविद्युत संयंत्र जल प्रवाह में दैनिक और मौसमी बदलावों के अधीन हैं। वे ईंधन लागत में उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं हैं जो थर्मल पावर संयंत्रों को परेशान करते हैं।
- जलविद्युत संयंत्र आमतौर पर प्राकृतिक गैस-आधारित संयंत्रों और कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में लंबे समय में सस्ते होते हैं जो वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतों में वृद्धि से लगातार जोखिम में हैं।
- जबकि भारत मुख्य रूप से रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रहा है, जल भंडारण सुविधाओं के साथ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत संयंत्र बाढ़ नियंत्रकों के साथ-साथ सिंचाई और बहुत जरूरी पेयजल के स्रोतों के रूप में कार्य करके महत्त्वपूर्ण जल संसाधनों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं।

चुनौतियाँः

- बड़े पैमाने पर पनबिजली बांध स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों को प्रभावित करते हैं। वे लोगों को विस्थापित करते हैं जो मछली और अन्य वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े जलविद्युत बांधों के निर्माण और रखरखाव का भी महत्त्वपूर्ण

पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है।

- देश में जलविद्युत क्षमता के विकास में मुख्य चुनौतियाँ दूरस्थ स्थान, अप्रत्याशित भूविज्ञान, प्राकृतिक आपदाएँ, पर्यावरण और वन मुद्दे, पुनर्वास तथा पुनर्वास (आर एंड आर) मुद्दे हैं।
- बांध और जलाशय नदी पारिस्थितिकी तंत्र तथा आसपास के आवासों को बाधित करते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जलाशय पहले की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जित कर सकते हैं।
- अधिक समय और लागत वृद्धि, परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उच्च अग्रिम लागत, हरित मंजूरी प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया, परियोजनाओं पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया अतिरिक्त उपकर, उच्च टैरिफ तथा बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यों की अनिच्छा कुछ ऐसी चीजें हैं उन कठिनाईयों के बारे में जो वर्तमान में देश में जलविद्युत विकास को बाधित कर रही हैं।
- प्रारम्भिक वर्षों में उच्च टैरिफ के कारण डिस्कॉम हाइड्रो पावर से बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने में अनिच्छुक होते हैं। जलविद्युत के उच्च टैरिफ का एक कारण परियोजना लागत में बाढ़ नियंत्रण और सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत का लोड होना है।

भारत में हाइड्रो पावर को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपाय:

- भारत में सरकार ने जलविद्युत को एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में पहचाना है। हिमालय में कई जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं या योजना के चरण में हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना और सिक्किम में तीस्ता लो डैम जलविद्युत परियोजना शामिल हैं।
- सरकार ने देश में जलविद्युत विकास के लिए अतीत में कई नीतिगत पहल की हैं। जैसे-राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 तथा भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 शामिल है।
- इसके बाद सरकार ने 2019 में हाइड्रो पावर को बढ़ावा देने के लिए उपाय भी जारी किए हैं जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
  - बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
  - जलविद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय (Tariff rationalization measures) करना।
  - बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता करना।
  - सक्षम बुनियादी ढांचे यानी सड़कों/पुलों और बाढ़ नियंत्रण की लागत के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान करना।
  - संविदात्मक विवादों को तेजी से और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए 'स्वतंत्र अभियंता' के माध्यम से 'विवाद निवारण तंत्र' और 'स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई)' के माध्यम से 'विवाद समाधान तंत्र' की अधिसूचना जारी करना।
  - जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत में वृद्धि की घटनाओं को कम करने के लिए दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी करना।
  - नई पनबिजली परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली के ट्रांसमिशन पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क की छूट घोषित करना।
- ये उपाय विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों/राज्यों में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए फायदेमंद होंगे जो अक्सर दूरदराज तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं और भारी, बड़े आकार के परिवहन के लिए सड़कों, पुलों आदि जैसे व्यापक संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता होती है।

विश्व बैंक की भूमिका:

- भारत सरकार ने देश की जलविद्युत क्षमता बढ़ाने की अपनी योजनाओं के लिए विश्व बैंक से समर्थन का अनुरोध किया है। इसने जलविद्युत डिजाइन, निर्माण और संचालन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी बिजली क्षेत्र की एजेंसियों को उनकी हालिया उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में मदद करने हेतु बैंक से सहायता का भी अनुरोध किया है।
- विश्व बैंक का लक्ष्य भारत सरकार को जलविद्युत विस्तार के लक्ष्यों को स्थायी तरीके से पूरा करने में सहायता करना है। इसमें न केवल वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी सुदृढ़ता सुनिश्चित करना शामिल है, बल्कि हाल के वर्षों में उद्योग द्वारा विकसित की गई सामाजिक प्रथाओं को पूरा करना तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संपत्तियों की सुरक्षा करना भी शामिल है।
- विश्व बैंक 1950 के दशक के उत्तरार्ध से भारत में जलविद्युत के क्षेत्र में सहायता कर रहा है। नाथपा झाकरी और कोयना IV परियोजनाएँ क्रमशः 2002 और 1998 में पूरी हुई जिन्हें विश्व बैंक के समर्थन से लाभ प्राप्त हुआ है।

आगे की राह:

जलविद्युत को अक्सर हरित ऊर्जा माना जाता है क्योंकि यह बिना कोई उत्सर्जन या प्रदूषक छोड़े पानी के प्राकृतिक प्रवाह से बिजली उत्पन्न करता है। यह जीवाश्म ईंधन पर भी निर्भर नहीं है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के विपरीत, जलविद्युत जो दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक स्रोत है, वैश्विक बिजली उत्पादन को स्वच्छ करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वर्तमान वैश्विक जलविद्युत क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य के साथ, समुदायों और पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए जलविद्युत परियोजनाओं को जिम्मेदारी से तथा टिकाऊ ढंग से बनाने की आवश्यकता है।

भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की रणनीति और पहल

वर्तमान समय में जिस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की प्रकृति में बदलाव आया है, उसके चलते केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और उसके क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे साइबर वारफेयर, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, ड्रोन हमले, नार्को आतंकवाद जैसी चुनौतियां बढ़ गई हैं इसलिए इंडियन आर्मी द्वारा भी खुद को सशक्त करने के प्रयास तेज हुए हैं।

- हाल ही में इस बात की सूचना मिली है कि भारतीय सेना के लिए अमेरिकी एयरोस्पेस बोइंग 6 जंगी अपाचे हेलीकॉप्टर के निर्माण कार्य में लग गई है। बोइंग ने भारतीय सेना को सौंपे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन एरीजोना के मेसा में शुरू किया है। एएच-64 अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देश्यीय लड़ाकू हेलीकाप्टरों में से एक है। एएच-64 की उन्नत तकनीक और प्रमाणित प्रदर्शन, भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों तथा उसकी रक्षा क्षमताओं को अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगा। भारतीय सेना के अपाचे की आपूर्ति 2024 तक निर्धारित है। AH-64E दुनिया का प्रमुख लड़ाकू हेलीकॉप्टर बना हुआ है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इससे भारतीय सेना की क्षमता बढ़ेगी।
- इससे पहले बोइंग ने 2020 में भारतीय वायु सेना को 22 ई-मॉडल अपाचे की सफल डिलीवरी पूरी की थी। उल्लेखनीय है कि बोइंग भारतीय सेना को कुल छह AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपेगी। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना बड़े पैमाने पर करती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायु सेना ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने 2017 में भारतीय सेना के लिए 4,168 करोड़ रुपये की लागत से छह अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी।

भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए किए गए महत्त्वपूर्ण प्रयासः

- भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों हेतु हथियार प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इस दिशा में सेना द्वारा माइंस, पर्सनल वेपंस और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित कई नए उपकरण शामिल किए गए हैं। नए स्वदेशी हथियार मिलने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ गई है। इन हथियारों में माइंस, पर्सनल वेपंस और लड़ाई में काम आने वाले वाहन हैं। स्वदेश में बने इन हथियारों में एंटी पर्सनेल माइंस, आमने सामने लड़ाई के हथियार, इन्फैंट्री के लड़ाकू वाहन शामिल हैं। इनमें एके-203 और एफ-इंसास राइफलों के अलावा नई ऐंटी पर्सनेल माइन 'निपुण' भी शामिल है। नए हथियार भारतीय कंपनियों ने विकसित किए हैं। पिछले वर्ष रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय सेना को स्वदेशी में विकसित उपकरण एवं प्रणालियां सौंपीं थीं। अत्याधुनिक उपकरणों में फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर, नई पीढ़ी की एंटी-पर्सनल माइन, टैंकों के लिए अपग्रेडेड साइट सिस्टम, उच्च गतिशीलता इन्फैंट्री प्रोटेक्टेड वेहिकल्स और असॉल्ट बोट्स शामिल हैं।
- क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल (मीडियम) पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए जरूरी पहल है। इन्फैंट्री मोबिलिटी प्रोटेक्टेड व्हीकल के जरिए भी लद्दाख क्षेत्र में सैन्य तंत्र को मजबूती मिली है। मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम सामरिक स्तर पर भारतीय वायु सेना के विमान और मानवरहित हवाई वाहनों हेरॉन द्वारा सामना की जाने वाली ऑपरेशनल सीमाओं को हटा देता है। यह पैदल सेना बटालियन और मशीनीकृत इकाईयों के स्तर पर निगरानी, पहचान और टोही की प्रतिबंधित क्षमता को हटाकर भारतीय सेना को सशक्त बनाता है।
- **निपुण माइंस होगी भारतीय सेना के लिए मददगारः** निपुण माइंस देश में विकसित बारूदी सुरंग हैं। यह घुसपैठियों और दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति की तरह काम करती है। इन्हें एंटी पर्सनेल माइंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में बिछाए जा सकते हैं।

पैंगोंग झील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्टः

- एलसीए यानी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट का विकास पैंगोंग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किया गया है। ये उन नावों की जगह लेंगे जो अभी पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग सो झील में गश्त करती हैं और सीमित क्षमता रखती हैं। एलसीए को गोवा की एक्वेरियस शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये स्पीड में तेज हैं और हर तरह की परेशानी के बावजूद पानी में काम करने की क्षमता रखते हैं। ये नावें एक समय में 35 लड़ाकू सैनिकों को ले जा सकती हैं जो बहुत ही कम समय में झील के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं।

फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर (F-INSAS):

- फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर को तीन प्राथमिक सब सिस्टम से लैस किया जा रहा है जिसमें पहला सब सिस्टम दिन-रात के होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट के साथ अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है। प्राथमिक हथियार प्रणाली के अलावा सैनिकों को मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड भी दिया जाएगा जिसे मल्टीपरपज नाइफ के साथ स्वदेशी रूप से खरीदा गया है।
- सशस्त्र बलों हेतु प्रतिरक्षा उपकरणों के पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। इन उपकरणों में रडार, एयरक्राफ्ट रॉकेट, आर्टलरी गंस, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट, वेपंस, सिम्युलेटर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज और विस्फोटक आदि शामिल है।
- भारतीय सेना अपने नीतियों के जरिए महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वूमेन सर्विंग पर्सनेल को

ग्रांट ऑफ परमानेंट कमिशन दिया गया है। सशस्त्र बलों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति दी है, साथ ही भारतीय सेना ने 2021 से महिला अधिकारियों को पायलट के रूप में सेवा देने के लिए भी अवसर देने शुरू किए हैं।

- भारतीय सेना ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नई खोज के द्वारा सामरिक लैन रेडियो की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 'मेक इन इंडिया' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए भारतीय सेना ने 9 जून 2023 को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के द्वारा दूसरे खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल लैन रेडियो की खरीद के लिए मेसर्स एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड (बैंगलोर) के साथ अनुबंध नई दिल्ली में उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एम. वी. सुचिन्द्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के साथ भारतीय सेना ने अब तक आईडीईएक्स के तहत दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके अपनी बढ़त बना ली है।
- आईडीईएक्स को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2018 को डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018 के दौरान लॉन्च किया गया था। आईडीईएक्स का उद्देश्य अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, एमएसएमई सहित उद्योगों, स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को शामिल करके अनुदान वित्त/पोषण व अन्य सहायता प्रदान करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचारों को बढ़ावा देना, जिन्हें भारतीय रक्षा और एरोस्पेस में भविष्य में शामिल करने की अच्छी संभावना हो। इस तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है। पिछले चार वर्षों में डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत आईडीईएएक्स, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के साथ सही तरह का संपर्क स्थापित करने में एक 'फ्रंटरनर' रूप के में उभरा है तथा डिफेंस स्टार्टअप कम्यूनिटी में पर्याप्त ध्यान आकर्षित कर रहा है।

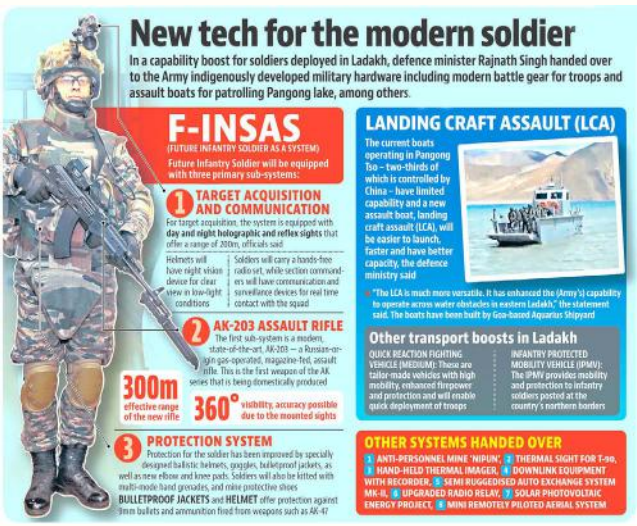

थिएटर कमांड बनाने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीतिः

- थिएटर कमांड बनाने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और उच्च रक्षा संगठन होना आवश्यक है। इसके बाद ही थियेटर कमांड के बारे में सोचना तर्कपूर्ण रहेगा। सेना के पुनर्गठन की बात करें तो मानव संसाधन प्रबंधन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का समावेश, पुनर्संतुलन, पुनर्गठन तथा संयुक्तता और बेहतर एकीकरण इसके चार प्रमुख पहलू हैं। एनएसएस के साथ एक ऐसे उच्च रक्षा संगठन की भी आवश्यकता है जो पूरे देश के दृष्टिकोण को प्रभावी करे जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व हो। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय रक्षा योजना समिति की स्थापना 2018 में की गई थी जिसे एनएसएस और एनडीएस तैयार करना था लेकिन अब तक इस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए जरूरी है कि इसके संस्थागत, संगठनात्मक ढांचे को और अधिक तार्किक तथा परिणाममूलक बनाया जाये और सभी आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन करते हुए थियेटर कमांड बनाने की दिशा में बढ़ा जाए। दुनिया भर के 32 से अधिक देशों के पास अपने सैन्य बलों के बीच बेहतर एकीकरण लाने के लिए पहले से ही किसी न किसी रूप में थिएटर या संयुक्त कमांड है। संयुक्त राज्य अमेरिका थिएटर कमांड सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश था जिसमें वर्तमान में छह भौगोलिक और चार कार्यात्मक कमांड शामिल हैं। रूस ने भी 2008 में अपने रक्षा बलों के पुनर्गठन के साथ शुरुआत की थी जिसके चार थिएटर कमांड हैं। कहा जाता है कि चीन का थिएटर कमांड सिस्टम अमेरिकी मॉडल पर आधारित है जिसमें "शांति के समय में पांच भौगोलिक कमांड" हैं। चाइनीज वेस्टर्न थिएटर कमांड भारतीय सीमा से सटे इलाके को कवर करती है।
- 'थियेटर कमांड सिस्टम' के पीछे का विचार सशस्त्र बलों की तीन शाखाओं के बीच सहक्रियाशील समन्वय लाना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य सेना तथा नौसेना, वायु सेना के लिए अलग-अलग कमानों को एक ही कमांडर के नेतृत्व वाली एकीकृत कमान के तहत लाना है। एकीकरण प्रक्रिया अंततः ऑपरेशनल हेड के तहत एक ही कमांड में जुड़े हुए एकीकृत सैन्य संपत्ति की ओर अग्रसर होगी जो किसी दिए गए स्थिति में उनकी गतिविधियों को निर्देशित करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्व भर में अपनी सैन्य क्षमता के लिए प्रसिद्ध भारतीय सेना अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव के साथ-साथ आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। हथियारों को अपग्रेड करने के लिए रक्षा उद्योग से जुड़े देश के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर नई रक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है। इसी क्रम में रक्षा आत्मनिर्भरता के विजन पर भी सेना तेजी से काम कर रही है जिसके परिणामस्वरूप न केवल स्वदेशी तकनीकों को सेना में अपनाया जा रहा है, बल्कि रक्षा निर्यात में भी उछाल देखा गया है। सेना के थिएटराइजेशन के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और उच्च रक्षा संगठन के विकास को लेकर भी सेना संकल्पित है। केंद्र सरकार आने वाले वर्ष में सैन्य बदलावों पर तेजी से काम करते हुए सुरक्षा बलों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

राष्ट्रीय मुद्दे

1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) के मसौदा दस्तावेज में प्रावधान किया गया कि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को अब अनिवार्य रूप से दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं (जिसे R1, R2 तथा R3 दर्शाया गया है) का अध्ययन करना होगा, जबकि कक्षा 11-12 के छात्रों को एक भारतीय भाषा और एक अन्य भाषा का अध्ययन करने की बात की गई।

NEW BOARD GAME NCF proposals for Classes IX-XII

Classes IX-X	To pass Class X, students to take **2 curricular areas** (list below, Physical Edu instead of Sports) for 2 years	Recommended: 2 board exams in each class

Classes XI-XII

Curricular Areas	Disciplines (list not exhaustive)
Humanities	Languages, Literature, Philosophy
Social Science	History, Geography, Pol Sc, Psychology, Economics, Sociology
Science	Physics, Chem, Biology
Maths & Computing	Maths, Comp Sc, Business Maths
Arts	Music, Dance, Theatre, Sculpture, Painting
Vocational Education	Aligned to national skills qualifications framework
Sports	Courses on specific sports, games or yoga
Interdisciplinary	Commerce, Sustainability & Climate Change, Health, Media & Journalism, Indian Knowledge

- For Classes XI & XII, each year divided into 2 semesters
- Curricular areas further sub-divided into **choice-based courses (disciplines)**
- Students must complete **any 16 choice-based courses** to complete Class XII
- Eg: If a student opts for **History in all 4 semesters,** she would've completed **4 choice-based courses**

मसौदा दस्तावेज की मुख्य बातें:

- मसौदे के अनुसार, R1 मातृभाषा या घरेलू भाषा को दर्शाता है, R2 कोई अन्य भाषा (अंग्रेजी सहित) हो सकती है और R3 कोई भी भाषा है जो R1 या R2 नहीं है। राज्य सरकारों और संबंधित स्कूल बोर्डों को R1, R2 तथा R3 भाषा को तय करने की स्वतंत्रता दी गई है।
- मसौदा समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन ने की जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष, जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर, दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबले और एनजीओ लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक धीर झिंगरन आदि सदस्य शामिल थे।
- NCF की रूपरेखा कक्षा 10 तक तीन भाषाओं (R1, R2 और R3) की शिक्षा को अनिवार्य करता है। इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषा R1, R2 या R3 भारत की मूल भाषा होनी चाहिए। कक्षा 11 और 12 में छात्रों को दो भाषाएं पढ़नी होंगी जिनमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए।
- इसमें कहा गया है कि कक्षा 12 में छात्रों का मूल्यांकन अधिकतम सात विषयों पर किया जाएगा। हालाँकि वर्तमान में अधिकांश स्कूल बोर्डों में केवल छह विषय शामिल हैं।

भाषाओं को लेकर वर्तमान नियम:

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) सहित अधिकांश स्कूल बोर्ड, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में दो भाषाओं और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में एक भाषा के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। हालाँकि, कुछ राज्य बोर्ड कक्षा 10 तक एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाना अनिवार्य करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी और पश्चिम बंगाल में बंगाली आदि।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) क्या है?

- एनसीएफ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 पर आधारित एक बेंचमार्क दस्तावेज है जिसका उपयोग एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 12 के बीच सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए किया जाता है।

आगे की राह:

यह रूपरेखा साल में दो बार कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का मसौदा पेश करती है तथा छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए साल में कम से कम दो बार बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित करने की भी सिफारिश करती है।

2 भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत NCAP) लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है।

भारत एनसीएपी के बारे में:

- एनसीएपी कार्यक्रम की शुरूआत 2011 में हुई थी परन्तु 2016 से इसमें तेजी आयी जब सरकार ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक मानक बनाने का निर्णय लिया।
- यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसमें दिए गए मॉडल के बेस वेरिएंट का परीक्षण किया जाएगा। यह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 197 पर आधारित होगा।
- यह 3.5 टन वाहन भार रेटिंग (GVW) से कम एम1 श्रेणी (चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं) के प्रकार से अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू होगा।
- इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (CIRT) द्वारा किया जाएगा। यह इस वर्ष 01 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

- इस परीक्षण में कार के प्रदर्शन के आधार पर वाहन को वयस्क यात्रियों (AOP) और बच्चों के बैठने वालों (COP) के लिए 0-5 के पैमाने पर स्टार रेटिंग दी जाएगी।
- यह कार्यक्रम स्वैच्छिक होगा परन्तु परीक्षण में वैश्विक स्तर पर 2.5 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 60 लाख रुपये का खर्च आ सकता है।

एनसीएपी के तहत किये जाने वाले परीक्षण:

- इस परीक्षण के माध्यम से वाहन सुरक्षा का आंकलन किया जाता है क्योंकि सरकार निकट भविष्य में ईवी सेगमेंट को शामिल करने की योजना बना रही है।
- कार निर्माता पहले ही भारत एनसीएपी कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन के लिए लगभग 15 से 20 मॉडल प्रदान कर चुके हैं।

कारों की चयन प्रक्रिया:

- चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्माताओं और आयातकों को सरकार के अधीन नामित एजेंसी को एक आवेदन (फॉर्म 70-ए) जमा करना होगा।
- फॉर्म 70-ए जमा करने के बाद, कारों को क्रैश टेस्ट के लिए चुना जाएगा जिसमें निर्माता और भारत एनसीएपी टीम दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- क्रैश टेस्ट के नतीजों के सार्वजनिक खुलासे के बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (CIRT) इसका प्रकाशन और प्रमाणीकरण करेगा।

आगे की राह:

भारत एनसीएपी परीक्षण प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के साथ संरेखित होगा। इसमें 64 किमी/घंटा की गति से फ्रंट इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट तथा पोल इम्पैक्ट परीक्षण शामिल होंगे। इसमें रेटिंग प्रणाली दुर्घटना परीक्षण के अलावा सभी कारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम (ESP) और पैदल यात्री सुरक्षा उपायों तथा बेल्ट रिमाइंडर जैसे सुरक्षा तत्वों को शामिल किया जायेगा।

3 विश्वकर्मा योजना और लखपति दीदी

चर्चा में क्यों?

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो नयी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े समुदायों के लिए विश्वकर्मा योजना, जबकि महिला सशक्तीकरण हेतु लखपति दीदी शामिल हैं।

विश्वकर्मा योजना के बारे में:

- यह योजना पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के उत्थान के लिए फोकस करेगी।
- यह नाम प्रसिद्ध वास्तुकार और शिल्पकार विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया जिसके तहत विभिन्न व्यवसायों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को होने वाले कौशल हस्तांतरण करने की गुरु-शिष्य परंपरा को संरक्षित किया जायेगा।
- इसमें बुनकर, सुनार, लोहार, कपड़े धोने वाले श्रमिक और नाई सहित 18 समुदायों को 'विश्वकर्मा योजना' के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा जिसके लिए अगले पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) हेतु शुरूआती बजट लगभग 13-15 हजार करोड़ रुपये होगा।
- इस योजना के तहत नामांकित श्रमिकों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- इसके तहत श्रमिकों को घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर व्यापक पहुँच मिलेगी जिससे वे भी प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को विकसित कर सकेंगे।

लखपति दीदी योजना के बारे में:

- इसमें सरकार महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है जिसके तहत सरकार का लक्ष्य गांवों से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है।
- इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाया जायेगा जिससे वे कम से कम 1 लाख रूपये प्रति वर्ष कमा सकें।
- इसमें प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाना, ड्रोन का संचालन और मरम्मत करने का प्रशिक्षण शामिल है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 15 हजार से अधिक ड्रोन दिया जायेगा ताकि उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से सशक्त किया जा सके।
- इससे महिलाओं को अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई- कामर्स प्लेटफार्मों से जुड़ने का अवसर मिलेगा ताकि बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

स्वयं सहायता समूह क्या है?

- ये समुदाय- आधारित समूह होते हैं जो लोगों के एक छोटे समूह, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने संसाधनों को इकठ्ठा करने और उसके आर्थिक उत्थान मिलकर कार्य करने के लिये सहमत होते हैं। इसमें आमतौर पर समान सामाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि के 10 से 20 सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए केरल का कुडुम्ब श्री स्वयं सहायता समूह।

आगे की राह:

भारत सरकार को इसके तहत राज्य सरकारों को भी सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से प्रशिक्षण देकर और जागरूक करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इन दोनों पहलों से गरीबी उन्मूलन में भी सहायता मिल सकती है।

4 युवाओं की सबसे बड़ी चिंता नौकरी और आर्थिक संघर्ष-सीएसडीएस सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

लोक नीति और सीएसडीएस 2023 द्वारा जारी एक सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 15 से 34 वर्ष के युवाओं हेतु सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति है।

रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु:

- 40% उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों ने बेरोजगारी को सबसे गंभीर चिंता बताया।
- 27% गैर-साक्षर लोगों ने बेरोजगारी को अपनी प्राथमिक चिंता बताया।
- 42% पुरुषों ने बताया कि बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है।
- निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए गरीबी व मूल्य वृद्धि एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी है।
- 6% युवाओं के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चिंता है।

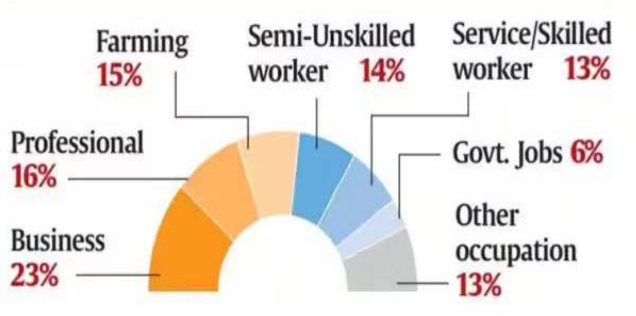

युवाओं की व्यावसायिक स्थिति:

- 49% युवा किसी न किसी कार्य में कार्यरत हैं।
- 40% युवा पूर्णकालिक एवं 9% युवा अंशकालिक रोजगार प्राप्त करते हैं।
- 23% युवा स्वरोजगार एवं 16% डॉक्टर या इंजीनियर, 15% कृषि एवं 6% सरकारी नौकरी से रोजगार प्राप्त करते हैं।

नौकरी की आकांक्षा:

- 16% युवा स्वास्थ्य, 14 प्रतिशत शिक्षा, 10% विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और 10% उद्योग तथा 6% सरकारी नौकरी करना चाहते हैं।

बेरोजगारी तथा आर्थिक संघर्ष सबसे बड़ी चिंता क्यों?

- भारत में श्रमिकों के कौशल एवं बाजार में उपलब्ध नौकरी के बीच असंतुलन देखने को मिलता है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि नवीनतम प्रौद्योगिकी ने रोजगार की संभावनाओं को कमजोर किया है।
- अभी तक कॉविड-19 के दुष्प्रभाव से अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र रोजगार की पूर्ण क्षमता विकसित नहीं कर सका।
- भारत के युवाओं के पास व्यवसाय उन्मुख कौशल का बेहद अभाव है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी श्रम की गति हीनता देखने को मिलती है जिसका कारण सामाजिक संदेह, कानून व्यवस्था, प्रवासी क्षेत्र में आर्थिक विनियम का पालन न होना है।
- विभिन्न सर्वे में देखा गया है कि भारत के युवा डिप्रेशन, एंजायटी एवं बिहेवियर डिसऑर्डर के शिकार होते जा रहे हैं जिससे उनके रोजगार की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आगे की राह:

वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश है। इसका लाभ उठाने के लिए शिक्षा और कौशल में निवेश करने के साथ ही सामाजिक बुनियादी ढाँचे में सुधार करना होगा। इसके अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना एवं विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है।

5 भारत की कार्यशक्ति वृद्ध हो रही- सीएमआईई रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के एक युवा राष्ट्र होने का विशेष उल्लेख किया और भारत के युवाओं के सामने मौजूद अवसरों पर प्रकाश डाला, वहीं सीएमआईई (CMIE) के आर्थिक आउटलुक डेटा से प्राप्त भारत के कार्यबल के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश हो सकता है लेकिन इसकी कार्यशक्ति तेजी से वृद्ध हो रही है।

भारत के लिए वृद्ध होती आबादी से तात्पर्य:

- वृद्ध कार्यबल का मूल रूप से तात्पर्य यह है कि यदि कोई भारत में सभी नियोजित लोगों को देखता है, तो इसमें युवा लोगों की हिस्सेदारी कम हो रही है, जबकि 60 वर्ष के करीब की उम्र वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है।
- कुल कार्यबल में 15-29 वर्ष के इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी 2016-17 में 25% से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17% हो गई है।
- इसी अवधि में 30-44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की हिस्सेदारी भी 38% से घटकर 33% हो गई है।
- कुल कार्यबल में 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 2016-17 में 37% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 49% हो गई है।
- दूसरे शब्दों में, पिछले सात वर्षों में कार्यबल इतना वृद्ध हो गया है कि 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी एक तिहाई से लगभग आधी हो गई है।

वृद्ध कार्यबल के निहितार्थ:

- **कम विकास क्षमता:** एक युवा कार्यबल आमतौर पर पुराने कार्यबल की तुलना में अधिक उत्पादक, नवीन और अनुकूलनीय होता है। युवा कार्यबल का तात्पर्य उच्च श्रम बल भागीदारी दर और कम निर्भरता अनुपात से भी है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- **कम मानव पूंजी विकास:** वृद्ध कार्यबल का मतलब युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण में कम निवेश हो सकता है जो भारत के मानव पूंजी विकास तथा भविष्य की उत्पादकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

- **उच्च सामाजिक सुरक्षा बोझः** वृद्ध कार्यबल को स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों पर अधिक व्यय की आवश्यकता हो सकती है जो भारत के राजकोषीय संसाधनों पर दबाव डाल सकता है और अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बाहर कर सकता है।

Table 1: Composition of the workforce by age group (%)

Year	Share of >15 and <30 in workforce (in %)	Share of 30 to <45 in workforce (in %)	Share of 45 years and more in workforce (in %)
2016-17	25	38	37
2017-18	23	38	39
2018-19	22	38	40
2019-20	21	37	42
2020-21	18	36	45
2021-22	18	35	47
2022-23	17	33	49
Source: CMIE's Economic Outlook and Indian Express Research			

भविष्य की प्रमुख तैयारीः

- भारत को अपने जनसांख्यिकीय अवसर से तभी लाभ होगा जब नीतियां और कार्यक्रम इस जनसांख्यिकीय बदलाव के अनुरूप होंगे।
- यदि अकुशल, कम उपयोग वाली तथा निराश युवा आबादी सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास को कमजोर करती है, तो अनुमानित जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा।
- जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन कामकाजी उम्र की आबादी की रोजगार क्षमता, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल के अलावा उपयुक्त भूमि और श्रम नीतियों के साथ-साथ सुशासन पर निर्भर करेगा।

आगे की राहः

अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में युवा आबादी अधिक है। तथापि यदि भारत उन्हें रोजगार देने में असमर्थ रहा, तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। जब तक इन प्रवृत्तियों को बदला नहीं जाता, भारत को उम्रदराज कार्यबल के साथ एक युवा देश होने की अपेक्षाकृत प्रतिकूल घटना का अनुभव करना पड़ सकता है।

6 76 वर्षों में भारत का विकास प्रदर्शनः एक तुलनात्मक विश्लेषण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूर्ण किया। इस दौरान भारत ने चार मापदंडों में अन्य देशों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति किया है जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, एचडीआई, आईएमआर और संसद में महिलाओं की भागीदारी शामिल है। निम्नलिखित विश्लेषण भारत की सफलता की यात्रा और आगे की चुनौतियों को परिभाषित करता है:

जीडीपी प्रति व्यक्ति रैंकिंगः

- काफी तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढांचे के विकास के बावजूद भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंकिंग 1960 के दशक से 2022 तक मूल्यांकन किए गए शीर्ष 26 देशों में से 24 पर स्थिर रही है।
- जहां 1960 के दशक में इंडोनेशिया और नेपाल भारत से पीछे थे, वहीं 2022 में ये देश बेहतर स्थिति में है।

एचडीआई प्रगतिः

- एचडीआई 0.11 अंक बढ़कर 2021 में 0.633 होने के बावजूद शीर्ष 31 देशों से तुलना करने पर भारत की रैंकिंग 1950 में 26 से फिसलकर 2021 में 29 हो गई है।
- इससे पता चलता है कि भारत ने शिक्षा, आय और जीवन प्रत्याशा जैसे क्षेत्रों में प्रगति किया है, जबकि अन्य देशों ने अपने सर्वांगीण विकास को बेहतर गति दी है।
- सऊदी अरब, इंडोनेशिया जो 1950 में भारत से पीछे थे, वर्तमान समय में एचडीआई रैंकिंग में आगे बढ़ गए हैं। यह भारत के लिए अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की गति को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

आईएमआर में सुधारः

- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में गिरावट स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और गुणवत्ता में प्रगति को रेखांकित करती है जो भारत की विकास यात्रा पर सकारात्मक रूप से दर्शाती है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारीः

- संसद में भारत की महिलाओं की भागीदारी 1997-98 में 7% से बढ़कर 2022 में 14.9% हो गई जिसमें प्रगति स्पष्ट है।

बुनियादी ढांचे की प्रगतिः

- भारत ने बिजली और इंटरनेट के उपयोग तक पहुंच में पर्याप्त सुधार हासिल किया। 1993 और 2000 के बीच बिजली की पहुंच 2020 तक 50% से बढ़कर 99% हो गई जो वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित है।
- 2020 तक भारत की 43% आबादी को प्रदान की गई इंटरनेट की पहुंच प्रगति को उजागर करती है।

जनसंख्या गतिशीलताः

- 1960 में भारत की आबादी 45.05 करोड़ थी जो चीन (66.7 करोड़) से पीछे थी। जून 2023 तक भारत की आबादी 1.417 बिलियन हो गई जो चीन के 1.412 बिलियन को पार कर गई (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार) जिससे भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया।

आगे की राहः

पिछले 76 वर्षों में भारत का मार्ग प्रमुख मापदंडों में प्रगति और चुनौतियों का एक सूक्ष्म मिश्रण दिखाता है। भारत की यात्रा आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और राजनीतिक समावेशिता के बीच जटिल अंतःक्रिया का उदाहरण देती है। व्यापक प्रगति प्राप्त करने के लिए यह

निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

7 बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो

चर्चा में क्यों?

जहाज रानी मंत्रालय सभी सरकारी और निजी बंदरगाहों के लिए बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना करेगा।

इसकी आवश्यकता क्यों?

- राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2021 में गुजरात के मुद्रा पोर्ट से एक कंटेनर मादक पदार्थ की चोरी पकड़ी जो कि अफगानिस्तान से तस्करी करके लाया गया था।
- समुद्री व्यापार भारत को आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसके लिए बंदरगाह एवं शिपिंग मार्ग सुरक्षित होने चाहिए।
- बंदरगाहों की बढ़ती संख्या, नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता को बढ़ाती है। यह पहल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि निजी बंदरगाहों की संख्या बढ़ रही है जिससे सभी भारतीय बंदरगाहों पर एक एकीकृत और मजबूत सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित हो सके।

लक्ष्य:

- भारत के महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों और शिपिंग केंद्रों में सुरक्षा उपायों को सुव्यवस्थित तथा मजबूत करना है।

कार्य:

- बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो एक एकल बिंदु एजेंसी होगी जो कि ओवरलैप को कम करने हेतु सभी भारतीय बंदरगाहों पर सुरक्षा ऑडिट के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी। यह सुरक्षा उपायों को एकीकृत तथा केंद्रित करके कानून प्रवर्तन एजेंसी एवं बंदरगाह अधिकारियों और समुद्री सुरक्षा कर्मियों सहित विभिन्न हित धारकों के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रयास करेगी। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुरक्षा खतरों और घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा।

वर्तमान स्थिति:

- केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सभी 12 प्रमुख बंदरगाह की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाती है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
- राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बंदरगाहों की अपनी सुरक्षा प्रणाली है।

नियंत्रण:

- बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो नामित प्राधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा। प्राधिकरण सुरक्षा स्तर निर्धारित करेगा और भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करने वाले व बाहर निकलने से पहले भारत के भीतर बंदरगाह सुविधाओं तथा प्रत्येक जहाज को जानकारी प्रदान करेगा।

आगे की राह:

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना व्यापक सुरक्षा तैयारियों की दिशा में एक सक्रिय बदलाव का प्रतीक है तथा यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में सहयोग करेगा। यह सुरक्षित नेविगेशन, सुरक्षित कार्गो हैंडलिंग और संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ सतर्क रहने में योगदान देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

1 भारत-जापान-श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2021 में संयुक्त भारत-जापान-श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग समझौता रद्द होने के दो साल बाद तीनों देश कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना (ECT) के त्रिपक्षीय सहयोग को पुन: शुरू करने के लिए सहमत हुए।

समझौते के मुख्य बिंदु:

- यह समझौता सहयोग कार्यक्रम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, पाथफाइंडर और सीआईआई द्वारा आयोजित किया गया।
- श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के पास ईसीटी का 100% का स्वामित्व होगा, जबकि श्रीलंका के साथ टर्मिनल का 51% और जापान व भारत के साथ 49% का स्वामित्व होगा।
- ईसीटी के विकास के लिए जापान से 0.1% की ब्याज दर पर 40 वर्षीय ऋण का समझौता हुआ है।

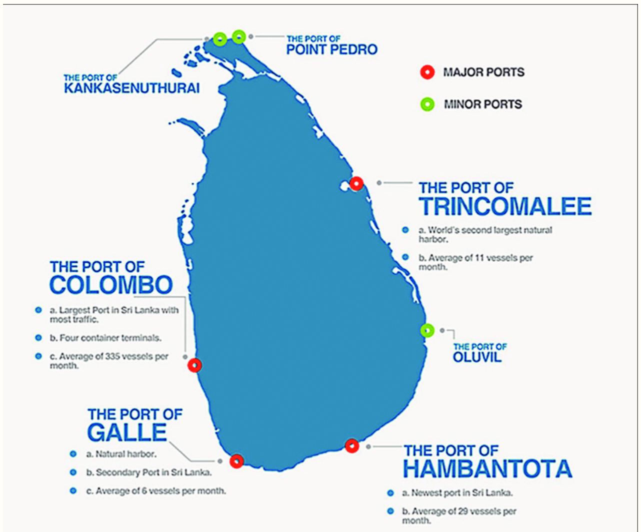

भारत व जापान के हित:

- श्रीलंका में चीन की उपस्थिति को कम करके इस पूरे क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकना है।
- ईसीटी के कुछ ही दूर पर चीन द्वारा निर्मित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है जिसको रणनीतिक दृष्टि से काउंटर करना महत्त्वपूर्ण है।
- भारत व जापान मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पेसिफिक (FOIIP) दृष्टिकोण को साझा करते हैं जो श्रीलंका सहित पूरे इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए प्रासंगिक है।
- त्रिपक्षीय सहयोग के माध्यम से चीन के ऋण जाल (Debt Trap) की नीति को चुनौती देना है जैसा कि चीन ने हंबनटोटा पोर्ट को ऋण जाल के माध्यम से 99 साल की लीज पर लिया है।

श्रीलंका का हित:

- आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे श्रीलंका को इस सहयोग से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है।
- ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत, जापान व फ्रांस द्वारा सहअध्यक्षता किया जा रहा है ताकि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभारा जा सके।
- संकट के इस दौर में श्रीलंका को जापान व भारत द्वारा बेल आउट पैकेज दिया गया।
- श्रीलंका के बुनियादी ढांचे के विकास में जापान व भारत ने प्रतिबद्धता दिखायी है।

आगे की राह:

राजपक्षे सरकार ने ईसीटी एमओयू को वर्ष 2021 में रद्द कर करके एक चीनी कंपनी को सौंप दिया था, परन्तु मई 2023 में विक्रमसिंघे सरकार ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया था। वर्तमान सरकार ने कहा कि भविष्य में किसी भी देश के साथ दूसरों की तुलना में अधिक अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगी जैसा कि पूर्ववर्ती श्रीलंका सरकारों ने किया।

2 सुलिना चैनल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस के ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के कई बंदरगाहों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यद्यपि सुलिना चैनल के माध्यम से यूक्रेन को अपने व्यापार के लिए नया वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया गया।

सुलिना चैनल का महत्त्व:

- सुलिना चैनल डेन्यूब नदी की 63 किलोमीटर लंबी सहायक नदी द्वारा यूक्रेनी काला सागर बंदरगाहों (उडेसा, चोर्नोमोस्को, पिवडेनी) से मालवाहक जहाज के लिए सुरक्षित पारगमन सुविधा प्रदान किया गया है जो बास्फोरस स्ट्रेट से होकर भूमध्य सागर से होते हुए वैश्विक पहुंच को यूक्रेन के लिए सुनिश्चित करेगा।

डेन्यूब नदी डेल्टा का महत्त्व:

- डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। यह दस देशों से होते हुए लगभग 2850 किलोमीटर की यात्रा करते हुए काला सागर में मिल जाती है। यूक्रेन अपने अनाज मालवाहक जहाजों को डेन्यूब नदी के अंतर्देशीय नदी जल परिवहन हेतु एक अन्य मार्ग को भी प्रशस्त कर रहा है।

यूक्रेन का व्यापार मार्ग व आर्थिक निर्भरता:

- सामानों के आवागमन के लिए डेन्यूब डेल्टा एक्सप्रेसवे नदी के रूप में यह अंतर्देशीय स्थानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- यूक्रेन कृषि निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है जिससे अनाज व्यापार उसके लिए अत्यंत गंभीर विषय हो जाता है।
- सुलिना चैनल सामानों के परिवहन के लिए एकमात्र गहरा और

चौड़ा चैनल है।

- अनाज ले जाने वाले जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों (इजमेल, रेनी) को सुलिना और रोमानिया के प्रमुख बंदरगाह कांस्टेंटा की ओर पहुंच की सुविधा होगी।

चुनौतियां और बाधाएं:

- रूस द्वारा यूक्रेनी बंदरगाहों और अनाज सुविधाओं को निशाना बनाने से मार्ग में स्थिरता को खतरा होगा।
- यूक्रेनी बंदरगाहों से अचानक अनाज की मात्रा बढ़ने की क्षमता सीमित है।
- सुलिना चैनल के मुहाने पर भीड़ भाड़ के कारण शिपिंग में काफी देरी होगी।
- ड्रोन के इस हमले ने दोनों देशों के बीच भविष्य में अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता में अविश्वास को गहरा कर दिया है।

आगे की राह:

ड्रोन हमलों का उद्देश्य यूक्रेन के अनाज व्यापार मार्ग को बाधित करना था। यद्यपि इससे यूरोप का ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले यूक्रेन व पूरे विश्व पर गंभीर अनाज का मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। इससे न केवल अनाज की कीमतों में उछाल आएगी, बल्कि समस्त सप्लाई चैन भी बाधित होगा। अतः इस संकट को अन्य देशों की वैश्विक पहल से जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए।

3 भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूरीनाम में भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की मान्यता के लिए भारत सरकार और सूरीनाम गणराज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन विशेष रूप से भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच किया गया।

एमओयू की मुख्य विशेषताएं:

- दवाओं के विनियमन के क्षेत्र में मजबूत सहयोग विकसित करने और महत्त्वपूर्ण जानकारी के आदान-प्रदान को पहचानने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एमओयू की प्रमुख विशेषता सूरीनाम में दवाओं के लिए मानकों की पुस्तक के रूप में भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) को स्वीकार कराना है ताकि सूरीनाम में निर्मित और/या आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- एक अन्य प्रावधान सूरीनाम निर्माताओं को आईपी के अनुसार भारतीय निर्माताओं द्वारा जारी विश्लेषण प्रमाणपत्र स्वीकार करने की अनुमति देता है।

समझौता ज्ञापन के लाभ:

- एमओयू की प्रमुख विशेषताओं का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के विकास को बढ़ावा देना और सूरीनाम में सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। समझौता ज्ञापन चिकित्सा

अनुसंधान और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के अवसरों की खोज में भी सहायता करेगा।

- यह सूरीनाम में चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा भी प्रदान करेगा और अंततः आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करेगा।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) क्या हैं?

- इंडियन फार्माकोपिया को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के आधार पर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) की ओर से भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- आईपीसी MoHFW की एक स्वायत्त संस्था है। आईपीसी आईपी रेफरेंस सब्सटेंस (आईपीआरएस) भी प्रदान करता है जो परीक्षण के तहत किसी वस्तु की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है।

आईपी का महत्त्व:

- यह भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त पुस्तक है। आईपी में उनकी पहचान, शुद्धता और ताकत के लिए दवाओं के विश्लेषण तथा विशिष्टताओं की अधिकृत प्रक्रियाओं का संग्रह शामिल है। अदालती विवाद की स्थिति में, ये आईपी मानक कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं।

सूरीनाम की भू-सामरिक स्थिति:

- सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गिनी, दक्षिण में ब्राजील और पूर्व में गुयाना से लगती है। यह एक छोटा सा तटीय देश है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। तेल और खनिजों का खनन इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है।

आगे की राह:

यह समझौता ज्ञापन भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा ज्ञान सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद को उजागर करता है।

4 यूनाइटेड किंगडम की उत्तरी सागर में ड्रिलिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तरी सागर में जीवाश्म ईंधन ड्रिलिंग की योजना का समर्थन किया है जिस पर पर्यावरणीय जलवायु वैज्ञानिक व विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है।

उत्तरी सागर के बारे में:

- उत्तरी सागर उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है जिसकी सीमा कई देशों से जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम एवं यूनाइटेड किंगडम से लगती है।
- यह ड्रोवर जल संधि व इंग्लिश चैनल द्वारा जुड़ा क्षेत्र है।
- महाद्वीपीय शेल्फ पर 1958 का जिनेवा कन्वेंशन पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून था जो उत्तरी सागर में अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करता है।
- इसके पश्चात यूके की संसद ने महाद्वीपीय शेल्फ सीमा अधिनियम 1964 कानून लागू किया जो अपने तट से सटे समुद्र तल के नीचे तेल व गैस संसाधनों पर देश के अधिकार क्षेत्र को मजबूत करता है।

वर्तमान समय में यूनाइटेड किंगडम की आवश्यकता:

- वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के बाद भी यूके ऊर्जा आवश्यकता के लगभग एक चौथाई तेल व गैस के आयात पर निर्भर रहेगा।
- रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन द्वारा ऊर्जा को पश्चिमी देशों को आपूर्ति करना बंद कर दिया। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग इसी गैस पाइपलाइन से पूरा होता है।
- ब्रिटेन के दूसरे राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन के लिए अपर्याप्त तैयारी है।
- अन्य देशों के संभावित अविश्वसनीय स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू आपूर्ति का उपयोग करके इन आवश्यकताओं को पूरा करना बेहतर होगा।

ड्रिलिंग से जुड़ी पर्यावरण चिंताएं:

- तेल रिसाव से पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा होगा।
- समुद्री आवासों का अपक्षय होगा जो भविष्य में जैव विविधता के लिए खतरा होगा।
- ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होगी।
- ड्रिलिंग से महासागर गर्म होते हैं जिससे सामुद्रिक जलस्तर में वृद्धि होगी।
- पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लिए किए गए पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन होगा।

आगे की राह:

ब्रिटेन का यह कदम उत्तरी सागर में ड्रिलिंग हेतु दुनिया भर के पर्यावरणीय चिंतकों के लिए गंभीर विषय है। उनका मानना है कि दुनिया किसी भी नई जीवाश्म ईंधन परियोजना को विकसित करने का जोखिम नहीं उठा सकती।

5 भारत और समोआ संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और समोआ ने स्वास्थ्य, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लघु तथा मध्यम उद्योग, क्षमता निर्माण जैसे विकास के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयाम व सहयोग पर चर्चा की।

भारत और समोआ संबंध:

- भारत 1970 में समोआ के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला न्यूजीलैंड के बाद दूसरा देश था।
- दोनों ही राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।

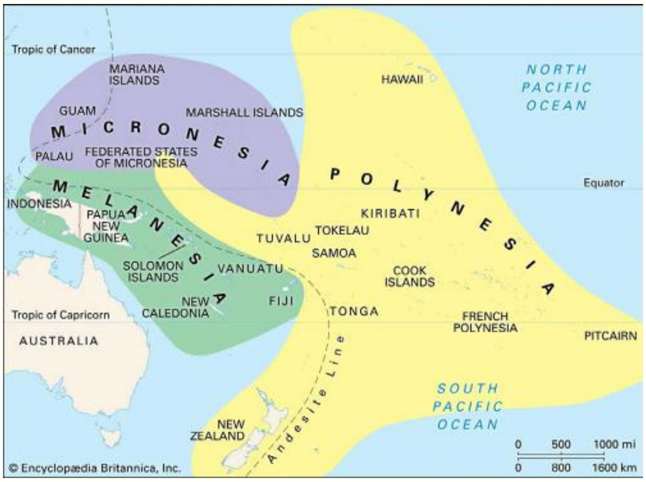

विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा सहयोग:

आर्थिक क्षेत्र:

- 2014 में भारत ने समोआ के लिए आर्थिक अनुदान सहायता बढ़ाकर 2 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया।
- वर्ष 2015 में एफआईपीआईसी (FIPIC) बिजनेस एक्सेलेरेटर कार्यालय को फिक्की परिसर में खोला।

कृषि क्षेत्र:

- वर्ष 2012 में नारियल क्षेत्र में नारियल विकास बोर्ड द्वारा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त किया गया।
- इसके अलावा, समोआ ने भारत से पौधा संरक्षण और प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की मंशा जाहिर किया।

खेल सहयोग:

- वर्ष 2015 में पांचवें राष्ट्रमंडल युवा खेल समोआ में आयोजित किए गए जिसमें भारत ने 33 सदस्य दल के साथ आठ खेल विधाओं में भाग लिया।

भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) क्या है?

- एफआईपीआईसी एक बहुपक्षीय समूह है जिसका उद्देश्य प्रशांत द्वीप समूह क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाना है जिसकी शुरुआत नवंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फिजी यात्रा के दौरान किया गया जिसमें कुल 14 देश हैं।

वर्तमान परिदृश्य:

- जुलाई 2023 में भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) समोआ की राजधानी एपिया में आयोजित किया गया।
- भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच शिखर सम्मेलन के साथ-साथ क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों और प्रशांत दीप समूह फोरम राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र के ढांचे पर सहयोग पर भी चर्चा हुई।
- समोआ अक्टूबर 2024 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम की मेजबानी करेगा जिसमें भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण प्रतिभाग करेगा।

आगे की राह:

भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में मुक्त आवागमन व्यापार क्षेत्र बनाए रखना चाहता है ताकि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक सहयोग मंचों के माध्यम से इस क्षेत्र में बढ़ते चीन के प्रभाव का रणनीतिक मुकाबला किया जा सके।

6 ऋण-जीवाश्म ईंधन का जाल (Debt-Fossil Fuel Trap)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारी कर्ज वाले गरीब देश को विभिन्न आर्थिक जरूरत को पूरा करने हेतु अमीर देश और निजी ऋण दाताओं से लिए गए ऋण को वापस करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है।

ग्लोबल साउथ का ऋण बोझ:

- रिपोर्ट वैश्विक दक्षिण में स्थित देशों पर केंद्रित है जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील, कम विकसित तथा अविकसित देश शामिल हैं।
- इन देशों ने विदेशी ऋण भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है जो 2011 और 2023 के बीच 150% की आश्चर्यजनक वृद्धि तक पहुंच गया है।

महामारी के बीच ऋण संकट:

- रिपोर्ट कहती है कि महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया जिससे 54 देशों को ऋण चुकाने के लिए अपने सार्वजनिक व्यय बजट में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कर्ज से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन निकालना:

- बढ़ते कर्ज से निपटने के लिए इन देशों ने राजस्व के स्रोत के रूप

में जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण की ओर रुख किया है।

- इसका उदाहरण अर्जेंटीना है जिसने वाका मुएर्टा तेल और गैस क्षेत्र में फ्रैकिंग परियोजनाओं का समर्थन किया है।
- विशेषज्ञ सावधान करते हैं कि ऐसी रणनीति पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न किए बिना अनजाने में उच्च ऋण स्तर में योगदान कर सकती है जोकि 'ऋण-जीवाश्म ईंधन जाल' का निर्माण कर सकती हैं।

संसाधन समर्थित ऋण (आरबीएल):

- रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि संसाधन समर्थित ऋण (आरबीएल) जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को और बढ़ाते हैं।

मुक्त होने की रणनीतियां:

- यह महत्त्वाकांक्षी ऋण रद्दीकरण के कार्यान्वयन का आग्रह करता है जिसमें सभी लेनदारों को शामिल किया गया है और आर्थिक स्थितियों से मुक्त किया गया है।
- समृद्ध सरकारों और संस्थानों द्वारा समर्थित स्वच्छ ऊर्जा पहल को स्थायी प्रथाओं में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव है।
- जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण।

आगे की राह:

सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने हेतु एवं पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों को निजी हित को छोड़कर पर्यावरण एवं संसाधनों के विषय में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए विकास उन्मुख पथ पर चलना होगा।

7 भारत और आसियान के बीच आर्थिक संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 20वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक सेमारंग (इंडोनेशिया) में आयोजित की गई। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए)-2009 की समय पर समीक्षा करना था।

बैठक का मुख्य उद्देश्य:

- उपर्युक्त बैठक में आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और एक पर्यवेक्षक के रूप में तिमोर-लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य ने भी भाग लिया। इस दौरान भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार निवेश संबंधों की समीक्षा की गई।
- मंत्रियों ने आसियान-भारत व्यापार परिषद (एआईबीसी) द्वारा निर्धारित गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) पर गौर किया और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक भागीदारी की प्रभावशीलता की भी जांच की।
- भारतीय व्यवसायों से एआईटीआईजीए की लंबे समय से मांग की गई थी जिसकी समीक्षा 2025 तक पूरी हो जाएगी।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता- 2009:

- एआईटीआईजीए (जिसे आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यह जनवरी 2010 से लागू हुआ। दोनों पक्ष निम्नलिखित चिंताओं के कारण इस समझौते की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं:
  - समझौते के लागू होने के बाद से आसियान के साथ व्यापार घाटा काफी बढ़ गया है।
  - अध्ययन से पता चलता है कि आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 2011 में 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 25 बिलियन डॉलर हो गया था।
  - व्यापार घाटे का प्रमुख कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा एफटीए मार्गों का कम उपयोग करना था।
- यह आशा की जाती है कि समीक्षा से एफटीए व्यापार को सुविधाजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। समझौते की समीक्षा से द्विपक्षीय व्यापार में वर्तमान विषमता को संबोधित करते हुए व्यापार को बढ़ाने और विविधता लाने की उम्मीद है।

भारत और आसियान:

- भारत और आसियान ने 2022-23 में 131.5 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया। आसियान के साथ व्यापार 2022-23 में भारत के वैश्विक व्यापार का 11.3% था। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह तीसरा सबसे बड़ा बाजार है जिससे भारत को अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

आगे की राह:

आर्थिक महत्त्व के साथ-साथ आसियान भारत के लिए अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति को लागू करने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। आसियान-भारत संबंधों को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में भी विकसित कर सकता है। इसलिए एआईटीआईजीए की शीघ्र समीक्षा और तदनुसार बाधाओं का समाधान समय की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 275 पक्षी प्रजातियों की गणना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नैनीताल के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षी सर्वेक्षण के दौरान दो गंभीर रूप से लुप्तप्राय, चार संवेदनशील और दो लुप्तप्राय प्रजातियों सहित लगभग 275 पक्षी प्रजातियों की गणना की गई।

पक्षी सर्वेक्षण से सम्बंधित मुख्य बातें:

- इस सर्वे में पक्षी विज्ञानियों, संरक्षणवादियों, वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) भारत के स्वयंसेवकों, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन और विलेज वालंटियर प्रोटेक्शन फोर्स की 62 सदस्यीय टीम द्वारा 20 से 23 जून के बीच किए गए सर्वेक्षण में 135 वन मार्गों के कुल 540 किमी क्षेत्र को कवर किया गया।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय मानी जाने वाली दो प्रजातियों अर्थात् सफेद दुम वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध को भी इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया।
- इस सर्वेक्षण के दौरान शोधकर्ताओं ने दो लुप्तप्राय प्रजातियों पलास फिश ईगल तथा मिस्र के गिद्ध की भी गिनती की गई जिनका वैज्ञानिक नाम क्रमशः हैलीएटस ल्यूकोरीफस और नेफ्रॉन पर्कनोप्टेरस हैं। इसमें चार पक्षी प्रजातियों जैसे ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट स्लैटी कठफोड़वा, ग्रे-क्राउन्ड प्रिनिया और रिवर टर्न को भी शामिल किया गया है।

अन्य प्रजातियों की गणना:

- इस सर्वे में लगभग अन्य 10 लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियाँ जिनमें रिवर लैपविंग, रेड-ब्रेस्टेड पैराकीट, ओरिएंटल डार्टर, लेसर फिश-ईगल, हिमालयन ग्रिफॉन, ग्रेट थिक-नी, ग्रे-हेडेड फिश-ईगल, ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क, एशियन वूली-नेक्ड स्टॉर्क और एलेक्जेंड्राइन तोता की भी गणना की गयी है।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में:

- जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है।
- इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था।
- कॉर्बेट नेशनल पार्क कुल 520.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जिसमें नदी बेल्ट, दलदली अवसाद, घास के मैदान और एक बड़ी झील भी शामिल है। इसकी ऊंचाई 1300 से 4000 फीट तक है।

आगे की राह:

इन पक्षियों की प्रजातियों को रिकॉर्ड करने के दो तरीकों जिसमें प्वाइंट काउंट मेथड तथा ट्रेल मॉनिटरिंग काउंट मेथड का उपयोग करके किए गए सर्वेक्षण का उद्देश्य एक समग्र दृष्टिकोण देना और परिदृश्य के सभी हिस्सों की रक्षा करना है जो बड़े पैमाने पर मेगा-फौना (Mega-Fauna) द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

2 यूरिया गोल्ड

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान के सीकर में सल्फर लेपित यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड को लांच किया गया। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।

यूरिया गोल्ड क्या है?

- यह सल्फर कोटेड यूरिया (SCU) होता है, इसलिए इसे सल्फर यूरिया भी कहते हैं। इसमें 37 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 17 प्रतिशत सल्फर होता है।

प्राथमिक उद्देश्य:

- भारतीय मिट्टी में सल्फर की आवश्यकताओं को पूरा करना।

विशेषताएं:

- यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में अधिक दक्ष है। जिस कार्य को पारंपरिक यूरिया 20 किलोग्राम में पूरा करती है, उसे यूरिया गोल्ड 15 किलोग्राम में पूरा करेगा।
- यूरिया गोल्ड में बेहतर पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की शक्ति शामिल है।
- यूरिया गोल्ड मिट्टी की गुणवत्ता एवं धारण क्षमता को बढ़ाएगी।
- यूरिया गोल्ड में उर्वरक की क्षमता बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड मिलाया गया है।
- यूरिया गोल्ड का प्रयोग कम मात्रा में कई बार किया जाता है जिसके बाद पौधों को लंबे समय तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। सल्फर कोटिंग के कारण पौधों को सल्फर का पोषण भी मिलता है।

यूरिया के अधिक उपयोग से उत्पन्न चुनौतियां:

- यूरिया पर सरकार भारी मात्रा में सब्सिडी प्रदान करती है, चूंकि इससे यूरिया की खपत बढ़ती है जो मिट्टी एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी नुकसानदायक है।
- यूरिया का आयात करने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
- यूरिया नाइट्रोजन पोषक तत्व पर केंद्रित होता है।

सुझाव:

- हमें यूरिया सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- हमें पोषक तत्व प्रबंधन एवं फसल विविधीकरण के माध्यम से संतुलित उर्वरक व्यवस्था की तरफ बढ़ना होगा।
- हमें यूरिया गोल्ड, नीम लेपित यूरिया एवं जैविक खेती को अधिकतम बढ़ावा देना होगा।

आगे की राह:

यूरिया गोल्ड को जन सामान्य के मध्य पूरी तरह सफल बनाने हेतु

व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे तथा सहकारी समितियों एवं मंत्रालयों को विशिष्ट कार्य योजना के तहत कार्य करना होगा, तभी हम सतत कृषि करने में सफल होंगे।

3 हाथियों की गणना 2023

चर्चा में क्यों?

अगस्त 2023 की एशियाई हाथी जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य का वन प्रभाग 6395 हाथियों का घर हैं जो 2017 की रिपोर्ट से 346 हाथियों की वृद्धि दिखाता है। हाथियों की आबादी 5,914 से 6,877 के बीच होने का अनुमान है। अधिकांश हाथी (80%) संरक्षित क्षेत्रों में हैं, जबकि अन्य (935) बाहर हैं। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को मनाए जा रहे विश्व हाथी दिवस से पहले जारी की गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हर पांच साल में आयोजित समकालिक हाथी आबादी आंकलन में हाथियों की संख्या में बदलाव का पता चला।
- बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 1,116 हाथी हैं, नागरहोल टाइगर रिजर्व में 831 हैं, जबकि येल्लापुर डिवीजन में केवल एक और हलियाल में दो हैं।
- तमिलनाडु की जनगणना में हाथियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है जो 2017 में 2,761 से बढ़कर 2,961 हो गई। इसके विपरीत, केरल की गिनती 3,322 से घटकर 1,920 हो गई।
- मैसूर हाथी रिजर्व में 6,111 हाथी हैं, जबकि दांदेली हाथी रिजर्व में 36 हाथी हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों के बाहर 161 हाथियों को निजी भूमि पर और 792 को गैर-संरक्षित क्षेत्रों में देखा गया जो स्वस्थ जन्म दर के कारण हाथी गलियारों को बनाए रखने के महत्त्व को रेखांकित करता है।

संरक्षण के लिए प्रयास:

- हाथी भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु है जिसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की 'एकांत प्रजातियों' के तहत संरक्षित किया गया है।
- हाथी परियोजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 1992 में शुरू की गई थी।
- हाल ही में दो नए हाथी रिजर्व (तराई हाथी रिजर्व दुधवा-पीलीभीत क्षेत्र और तमिलनाडु में अगस्तियारमलाई हाथी रिजर्व) को अधिसूचित किया गया है।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड में चिल्ला-मोतीचूर तथा केरल में तिरुनेली- कुदराकोट कॉरिडोर जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण हाथी गलियारों को बहाल किया गया है।
- वन अधिकारियों द्वारा गज सूचना मोबाइल एप्लिकेशन के एक हिस्से के रूप में बंदी हाथियों हेतु डीएनए प्रोफाइलिंग पहल अगस्त 2022 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य शारीरिक ऊतक के नमूने से एक विशिष्ट डीएनए पैटर्न या प्रोफाइल प्राप्त करना है जो 'बंदी हाथियों के आधार कार्ड' के रूप में काम करेगा।

आगे की राह:

मानव-हाथी संघर्ष भारतीय हाथी संरक्षण में एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब किसानों को वन्यजीवों से संबंधित फसल के नुकसान की भरपाई करती है। हाथी परियोजना के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव शुरू किया जिसका उद्देश्य संरक्षण संदेश फैलाना और इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाना है।

4 हवाई द्वीप के जंगल में आग

चर्चा में क्यों?

अमेरिका में आई सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक हवाई, (विशेषकर माउई) द्वीप में कई जगह जंगल की आग की घटनायें देखी गई है जिसमें अब तक लगभग 100 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।

हवाई द्वीप के बारे में:

- हवाई द्वीप (जिसे बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है) हवाई द्वीप समूह का हिस्सा है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है। यह हवाई द्वीपसमूह में सबसे बड़ा और दक्षिणपूर्वी द्वीप है। हवाई द्वीप निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में आता है:
  - हवाई द्वीप कैलिफोर्निया के दक्षिण-पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है।
  - यह हवाई द्वीपसमूह का हिस्सा है जिसमें ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला शामिल है।
  - यह द्वीप अपने सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है जिनमें मौना लोआ और किलाउआ शामिल हैं। इन ज्वालामुखियों ने लाखों वर्षों में द्वीप के परिदृश्य को नया आकार दिया है।
  - द्वीप के अन्य ज्वालामुखियों में से एक मौना केआ, हवाई राज्य का उच्चतम बिंदु है।
- हवाई द्वीप में अपनी विविध स्थलाकृति के कारण विभिन्न प्रकार के माइक्रॉक्लाइमेट हैं। आम तौर पर जलवायु उष्णकटिबंधीय है, लेकिन स्थान के आधार पर यह आर्द्र और बरसात से लेकर शुष्क तथा धूप तक हो सकती है।

हवाई द्वीप में जंगल की आग के कारण:

- आग लगने का सटीक कारण अभी भी अनिश्चित है।
- अमेरिकी वन सेवा और अन्य द्वारा 2000-2017 के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अमेरिका के 85% जंगल की आग मानवीय गतिविधियों के कारण होती है।
- मानव-जनित कारकों में कैम्पफायर, कचरा जलाना, उपकरण की खराबी और फेंकी गई सिगरेट शामिल हैं।
- आग के प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखीय गतिविधि और बिजली गिरना भी प्रमुख है।

- माउई हवाई द्वीप समूह के छह सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक का घर है।
- विशेषज्ञ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि माउई के अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ना भी कारण हो सकता है।
- गैर-देशी घास और वनस्पति वाली शुष्क भूमि ने आग के लिए पर्याप्त ईंधन प्रदान किया।
- इन शुष्क परिस्थितियों ने आग को तेजी से फैलने में मदद की।
- देशी पौधों और पशु प्रजातियों के आवास का नुकसान।
- जलवायु परिवर्तन अद्वितीय आवासों और जैव विविधता के नुकसान में योगदान देता है।
- हीटवेव सूखे की स्थिति को बढ़ा सकती है जिससे जंगल की आग का भी खतरा बढ़ जाता है।

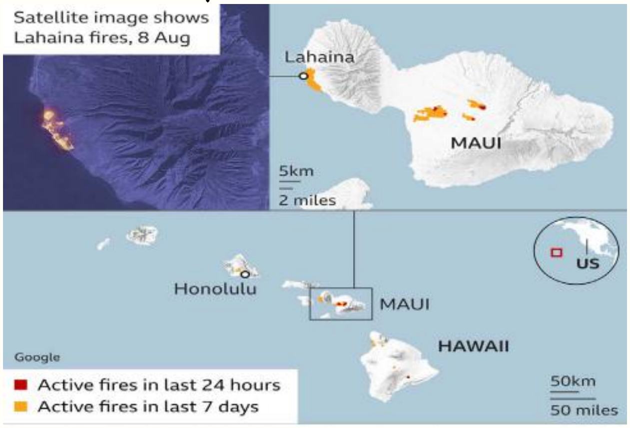

हवाई द्वीप पर तूफान डोरा की हवाओं का प्रभाव:

- माना जाता है कि हवाई द्वीप में आग की उत्पत्ति जंगल में हुई थी।
- लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने आग फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ये हवाएं प्रशांत महासागर में स्थित एक असामान्य रूप से शक्तिशाली तूफान डोरा से जुड़ी थीं।

आगे की राह:

हमेशा कैम्प फायर नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना, चेनसॉ और वाहनों जैसे आग भड़काने वाले उपकरणों का नियमित रूप से रखरखाव व निरीक्षण करना, आग की रोकथाम तथा सुरक्षा के बारे में जनता को शिक्षित करना, निकासी योजना और आपातकालीन किट तैयार रखने से जंगल की आग जैसी भयानक घटनाओं से बचा जा सकता है।

5 सदी का तीसरा सबसे लंबा मानसून अवकाश

चर्चा में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में इस वर्ष मानसून के समय 1901 के बाद से चौथी सबसे कम बारिश हुई।

मानसून ब्रेक क्या है?

- जब मुख्य वर्षा का कारण बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्रों का विस्तारित क्षेत्र (जिसे मानसून गर्त के रूप में जाना जाता है) अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बढ़ता है, तो इसे दक्षिण-पश्चिम मानसून का ब्रेक फेज कहा जाता है। इसकी सामान्य स्थिति मुख्यत: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत पर होती है जिसे मुख्य मानसून क्षेत्र भी कहा जाता है। यह पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक फैला क्षेत्र है जहाँ कृषि गतिविधियाँ वर्षा पर आधारित हैं।
- ब्रेक मॉनसून चरण के दौरान वर्षा हिमालय की तलहटी और उत्तर-पूर्व में केंद्रित होती है। नवीनतम ब्रेक मॉनसून चरण 7 अगस्त से 18 अगस्त तक चला था जो 2002 और 2009 के बाद 21वीं सदी में तीसरा सबसे लंबा ब्रेक था।

लंबे समय तक मानसून ब्रेक के कारण:

- **मानसून 2023, एक अल-नीनो वर्ष:** अल-नीनो की निरंतर प्रगति, उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में जलवायु पैटर्न का उष्ण रूप है जिसे अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) कहा जाता है। इससे सामान्यत: भारत में मानसूनी वर्षा कम हो जाती है।
- दूसरी बड़े पैमाने की जलवायु घटना इंडियन ओशन डायपोल (आईओडी) है जो भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारों के अलग-अलग तापमान के कारण घटित होती है। जब पश्चिमी भाग गर्म होता है, तो आईओडी को सकारात्मक चरण में कहा जाता है जिससे भारत में मानसूनी वर्षा बढ़ जाती है परन्तु जब पूर्वी भाग गर्म होता है, तो आईओडी को नकारात्मक चरण में हो जाता है जिससे भारत में मानसूनी वर्षा कम हो जाती है। हालाँकि मौसम विज्ञान ब्यूरो (ऑस्ट्रेलिया) के अनुसार, IOD फिलहाल नार्मल है।
- तीसरी बड़े पैमाने की जलवायु घटना उत्तरी हिमालय और यूरेशियाई भूभाग पर बर्फ का आवरण है जो भूभाग के अलग-अलग तापमान के माध्यम से भारतीय मानसून पर भी प्रभाव डालता है।

उष्णकटिबंधीय देशों में अल नीनो का प्रभाव अधिक स्पष्ट होगा:

- **जलवायु-** अल-नीनो के कारण 2099 तक 84 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक नुकसान होगा जिसमें भारत अनुमान से अधिक असुरक्षित हो सकता है। पिछले मानसून अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ तथा भूस्खलन हुआ जिससे मानव जीवन और बुनियादी ढांचे की हानि हुई।
- **कृषि-** दो मौसम संबंधी घटनाएँ सिन्धु-गंगा बेल्ट में कृषि का भाग्य तय करती हैं। मानसून की कमी का असर खरीफ फसल के मौसम पर पड़ेगा। क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप के अनुसार, 2023 में धान का बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में पहले ही 8% कम हो गया है।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव-** मौसम पूर्वानुमान सेवा प्रदाता स्काईमेट के अनुसार, भारत की 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानसून के मौसम पर निर्भर करती है, जबकि देश के 260 मिलियन किसान चावल तथा गन्ना आदि जैसे फसल उत्पादों के

लिए मानसून पर निर्भर हैं।

आगे की राह:

मानसून के असमान वितरण के कारण, राजस्थान में दो गुना अधिक बाजरा बोया जाता है क्योंकि भारत में धान का क्षेत्र 26% कम हो गया है। उत्पादन में कमी से बचने के लिए, आईएमडी किसानों को खरीफ सीजन में कम अवधि वाली किस्मों पर स्विच करने हेतु सलाह अलर्ट जारी कर रहा है।

6 फ्लडवॉच मोबाइल ऐप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने वास्तविक समय के आधार पर अगले सात दिनों के लिए बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने हेतु अपना इन-हाउस विकसित मोबाइल एप्लिकेशन 'फ्लडवॉच' लॉन्च किया है।

ऐप से सम्बंधित मुख्य बातें:

- इस ऐप से उपयोगकर्ता देश भर में बाढ़ की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप जानकारी के अनुकूल एक इंटरफेस प्रदान करेगा जो बाढ़ की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम कर सकता है।
- यह एप्लिकेशन 24 नदी घाटियों में फैले 1543 में से 328 बाढ़ निगरानी बिंदुओं के आधार पर पूर्वानुमान लगाएगा। बाढ़ निगरानी बिंदु वे होते हैं जहां नदियों, जलाशयों और नहरों के जल स्तर का प्रत्येक घंटे पर आंकलन किया जाता है।
- ये डेटा जल आवंटन बाढ़ और सूखे के जोखिमों के पूर्वानुमान के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा।
- यह द्विभाषी मोबाइल (हिंदी तथा अंग्रेजी) ऐप है जो एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है तथा वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं को व्यापक पहुंच प्रदान करेगा।
- यह ऐप विभिन्न स्रोतों से वास्तविक समय के नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है और निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता होम पेज पर ही अपने निकटतम स्टेशन पर बाढ़ सलाह की जांच कर सकते हैं।
- यह वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं को व्यापक पहुंच प्रदान करेगा तथा इस ऐप को Google Play Store से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है जो जल्द ही Apple iOS पर भी उपलब्ध होगा।

ऐप की आवश्यकता क्यों?

- भारत में बाढ़ की स्थिति कुछ क्षेत्रों में भयावह हो जाती है। भारत में लगभग 400 नदियाँ और सात प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं जिनकी लंबाई 2 लाख किमी से अधिक है, लेकिन स्थितिजन्य आंकलन की सही तस्वीर देने के लिए बाढ़ निगरानी प्रणाली उपलब्ध नहीं हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी 208.62 मीटर के आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई जिसने 45 साल पुराने 207.49 मीटर के रिकॉर्ड को बड़े अंतर से तोड़ दिया था।

आगे की राह:

यह मोबाइल ऐप सटीक तथा समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है जिससे बाढ़ की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम किया जा सके।

7 स्पंज सिटी

चर्चा में क्यों?

जुलाई व अगस्त के महीनों में हुई विनाशकारी वर्षा ने अनेक चीनी शहरों को तबाह कर दिया जिससे मानव जीवन, चीन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस आपदा ने 2015 में शुरू की गई चीनी शहरी बाढ़ निवारण पहल 'स्पंज सिटीज' की प्रभावशीलता को बढ़ा दिया है।

स्पंज सिटी क्या है?

- शहरी बाढ़ का मुद्दा चीन में गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि 654 चीनी शहरों में से 180 शहर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा के साथ-साथ शहरों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव और शहरीकरण की तीव्र गति से शहरी बाढ़ का मुद्दा नीति निर्माताओं के लिए हल करना प्राथमिकता बन गया है।
- इसलिए पानी को बेहतर ढंग से वितरित करने तथा जल निकासी और भंडारण में सुधार के लिए कम प्रभाव वाले 'प्रकृति-आधारित समाधान' का अधिक उपयोग करने हेतु 2015 में 'स्पंज सिटीज' कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- इसमें शहरी पर्यावरण में सुधार करते हुए जल भराव की समस्या को कम करने के लिए पारगम्य डामर का उपयोग नहरों और तालाबों का निर्माण तथा आर्द्रभूमि की बहाली शामिल थी।

इसके अप्रभावी होने का कारण:

- अब तक कम संख्या में शहरों (654 में से केवल 64) को कवर किया जाना।
- स्पंज शहरों की संख्या उस क्षेत्र की औसत वर्षा से बहुत कम होना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक फोकस का अभाव।
- इस प्रकार स्पंज शहरों में कुछ संरचनात्मक और प्रशासनिक दोष हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है।

शहरी बाढ़ एक वैश्विक समस्या के रूप में:

- शहरी बाढ़ बेतरतीब शहरीकरण, प्रभावी जल निकासी प्रणालियों की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जीवन तथा संपत्ति के लिए प्रमुख खतरों में से एक है। 2020 में बाढ़ के कारण वैश्विक स्तर पर अनुमानित 6000 लोगों की मौत और 51.3 बिलियन डॉलर की आर्थिक क्षति हुई।

आगे की राह:

दुनिया भर में ज्यादातर विकासशील देशों में अस्थिर विकास के विस्तार पर संबंधित एजेंसियों द्वारा ध्यान देने की जरूरत है ताकि शहरों का लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि शहरी बाढ़ से न केवल निवेशित पूंजी का नुकसान होता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति शहर की संवेदनशीलता भी बढ़ती है।

1 वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव हृदय में 'माइक्रोप्लास्टिक' का पता लगाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (ACS) द्वारा एक नवीनतम अध्ययन में कहा गया है कि चीन के बीजिंग अंजेन अस्पताल में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मानव हृदय में माइक्रोप्लास्टिक्स का पता लगाया है। अस्पताल के वैज्ञानिकों ने हृदय संबंधी सर्जरी कराने वाले 15 रोगियों के हृदय ऊतकों का विश्लेषण करते हुए यह खोज की।

माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

- माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के पांच मिलीमीटर से कम लंबे टुकड़ों और कपड़ों के माइक्रोफाइबर के छोटे टुकड़े होतें है जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाये जाते हैं।
- यह दुनिया भर में फैल रहा है जिसमें अंटार्कटिका जैसे दूरदराज के इलाके भी शामिल हैं, जहां पिछले साल बर्फबारी में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए थे।
- अध्ययन में पाया गया है कि मुंह, नाक और शरीर के अन्य छिद्रों के माध्यम से ये मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक मोटापे, मधुमेह और क्रोनिक लीवर रोग जैसी बीमारियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि वे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में परिवर्तन का कारण बनते हैं।

अध्ययन से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण बातें:

- अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ऑपरेशन से पहले और बाद के रक्त के नमूने एकत्र किए और फिर नमूनों का लेजर डायरेक्ट इंफ्रारेड इमेजिंग से विश्लेषण किया तथा यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ये कण अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जोखिम के माध्यम से लोगों के हृदय प्रणाली में प्रवेश कर सकते हैं?
- शोधकर्ताओं ने आठ प्रकार के प्लास्टिक से बने 20 से 500 माइक्रोमीटर चौड़े कण प्राप्त किए और उन्हें एकत्रित किए गए अधिकांश ऊतक नमूनों में हजारों माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े भी मिले, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में यह अलग-अलग थी।
- अध्ययन में आठ प्रकार के प्लास्टिक में पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट था जिसका उपयोग कपड़ों और खाद्य कंटेनरों के साथ-साथ पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) में किया जाता है जो खिड़की के फ्रेम, जल निकासी पाइप तथा पेंट में पाया जाता है।

आगे की राह:

शोधकर्ताओं द्वारा मानव हृदय में इन विवो एमपी (माइक्रोप्लास्टिक्स) का पाया जाना चिंताजनक है। यह जांच करना आवश्यक है कि एमपी हृदय के ऊतकों में कैसे प्रवेश करते हैं और कार्डियक सर्जरी के बाद इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं?

2 डोनानेमबः अल्जाइमर का इलाज

चर्चा में क्यों?

अल्जाइमर के इलाज के लिए अपेक्षित प्रभावकारी दवा डोनानेमब फिर से चर्चा में है क्योंकि जाँच परीक्षण (जो अभी भी प्रक्रिया में हैं) से यह संकेत मिला है कि डोनानेमब की प्रभावकारिता के खिलाफ कुछ जटिलताएं उभर रही हैं।

परीक्षण डोनानेमब के बारे में क्या बताता है?

- एली लिली कंपनी ने पिछले महीने कहा था कि डोनानेमब ने चरण 3 परीक्षणों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन डोनानेमब, लेकानेमब और एडुकानुम्ब (इन सभी का अल्जाइमर के लिए परीक्षण चल रहा है) पर आगे के परीक्षणों में कुछ जटिलताएँ दिखाई दी हैं।
- बताया गया है कि इनसे घातक मस्तिष्क रक्तस्राव और दिल के दौरे पड़ सकते हैं। 2021 में JAMA न्यूरोलॉजी से यह भी पता चला कि डोनानेमब और एडुकानुम्ब लागत प्रभावी नहीं हैं।

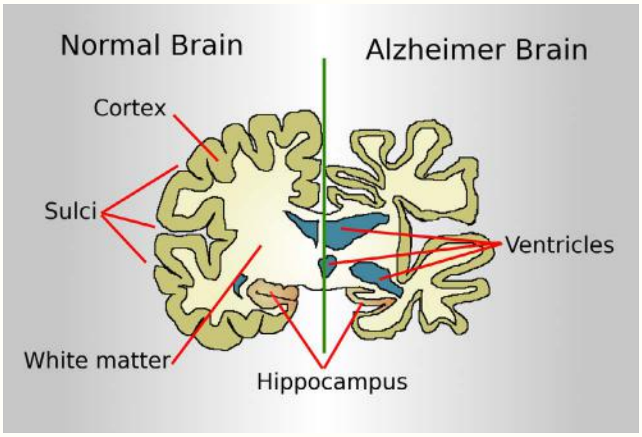

अल्जाइमर क्या है?

- अल्जाइमर एक तंत्रिका तंत्र संबंधी मस्तिष्क विकार है जिसके कारण मस्तिष्क सिकुड़ जाता है और अंततः मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित होता है। इसका सबसे सामान्य रूप डिमेंशिया स्मृति, सोच, व्यवहार और सामाजिक कौशल में धीरे-धीरे गिरावट की ओर ले जाता है। ये परिवर्तन व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी मस्तिष्क कोशिकाओं में और उसके आसपास प्रोटीन (अमाइलॉइड प्रोटीन) के असामान्य निर्माण के कारण होती है।
- वैश्विक स्तर पर लगभग 55 मिलियन लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं जिसका सबसे आम कारण अल्जाइमर रोग है। भारत में 2030 तक लगभग 7.6 मिलियन लोगों के अल्जाइमर रोग से पीड़ित होने की उम्मीद है जैसा कि डिमेंशिया इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में

बताया गया है।

डोनानेमब, लेकानेमब और एडुकानुम्ब:

- ये अल्जाइमर का इलाज नहीं बल्कि एंटीबॉडी-आधारित उपचार हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होने के अलावा इन दवाओं में आम बात यह है कि वे मस्तिष्क में अमाइलॉइड प्रोटीन के निर्माण को बेअसर कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी से सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है।

अल्जाइमर के उपचार से संबंधित चुनौतियाँ:

- डिमेंशिया इलाज के लिए सबसे कठिन स्थिति है। दवाओं के साथ सीमित सफलता से पता चलता है कि इस बीमारी के लिए (एमिलॉयड प्रोटीन के अलावा) अन्य कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं।
- बढ़ती जीवन अवधि विकलांगता और मोटापा आदि जैसी बीमारियों के बहुत अधिक बोझ से भारत में डिमेंशिया का प्रसार बढ़ने की आशंका है।

आगे की राह:

दवाओं से जुड़ी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भारतीय एजेंसियां भी विभिन्न नैदानिक परीक्षण कर रही हैं। फिलहाल बीमारी का बोझ तेजी से बढ़ रहा है तथा इसके लिए पर्याप्त उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए अल्जाइमर पर और अधिक शोध व प्रोत्साहन आधारित विकास समय की मांग है।

3 भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर

चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु स्थित वोक्सेलग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड अक्टूबर में सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज, बेंगलुरु में, अपना पहला भारत में निर्मित एमआरआई स्कैनर का अनावरण करेगा। इस एमआरआई स्कैनर को शक्ति देने वाले बड़े सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट में शीतलक के रूप में उपयोग के लिए तरल हीलियम पर निर्भरता से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा करने के लिए तरल हीलियम के स्थान पर तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाएगा।

तरल नाइट्रोजन का उपयोग करने के लाभ:

- तरल नाइट्रोजन आमतौर पर तरल हीलियम की तुलना में किफायती होता है।
- यह लागत एमआरआई स्कैनर का उपयोग करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के परिचालन खर्चों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है जिससे तकनीक अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाएगी।
- तरल हीलियम की तुलना में तरल नाइट्रोजन बेहतर सुरक्षा पहलू प्रदान करता है। इसका उच्च क्वथनांक (हीलियम के लिए-196°C बनाम-268.9°C) इससे तेजी से वाष्पित होने और दबाव से संबंधित खतरों का कारण बनने की संभावना कम कर देता है। यह हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन को सुरक्षित तथा अधिक प्रबंधनीय बनाता है।
- तरल नाइट्रोजन की सुरक्षा प्रोफाइल और हैंडलिंग विशेषताएँ इसे क्लीनिकल में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाती हैं।
- एमआरआई स्कैनरों में तरल नाइट्रोजन का उपयोग करना आमतौर पर तरल हीलियम का उपयोग करने से सामान्य रूप से सरल होता है।

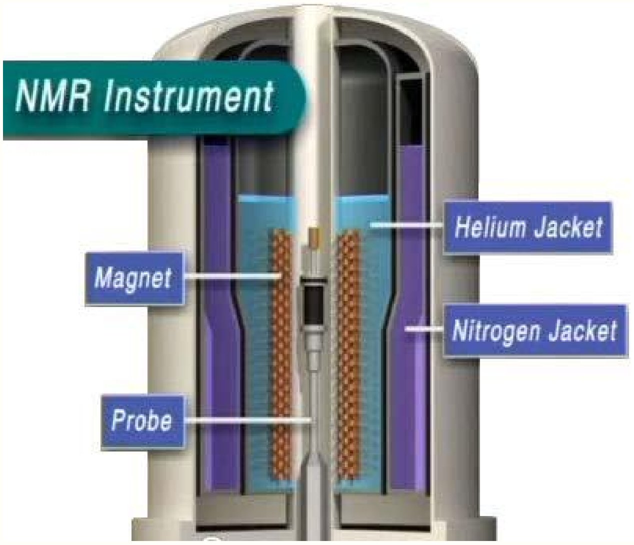

एमआरआई स्कैनर कैसे काम करता है?

- एमआरआई शरीर की आंतरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियोफ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग करता है।
- मानव शरीर अधिकतर पानी से बना है जिसमें हाइड्रोजन नाभिक (प्रोटॉन) होते हैं। जब एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये नाभिक चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाते हैं।
- संरेखित हाइड्रोजन नाभिक पर एक संक्षिप्त रेडियोफ्रीक्वेंसी पल्स लगाया जाता है। यह पल्स हाइड्रोजन नाभिक की प्राकृतिक आवृत्ति के साथ अनुनादित होती है जिससे वे ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।
- एक विस्तृत छवि बनाने के लिए स्कैनर रॉ फार्म सिग्नल डेटा को दृश्य प्रतिनिधित्व में परिवर्तित करने के लिए जटिल गणितीय एल्गोरिदम को नियोजित करता है।

एमआरआई स्कैनर का अनुप्रयोग:

- मस्तिष्क विकारों से लेकर मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं तक, चिकित्सा स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के निदान के लिए आंतरिक शरीर संरचनाओं का विस्तृत दृश्य लेना।
- ट्यूमर, घावों और असामान्यताओं का पता लगाकर उनका लक्षण वर्णन करना।

आगे की राह:

भारत में स्वदेशी एमआरआई स्कैनर की शुरूआत किफायती स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा प्रौद्योगिकी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। इस उपलब्धि में न केवल भारत में बल्कि विश्व

स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है जो सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल परिणामों को आगे बढ़ाने में तकनीकी प्रगति के महत्त्व को रेखांकित करती है।

4 कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन की प्रभावकारिता

चर्चा में क्यों?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की क्लिनिकल स्टडीज और ट्रायल इकाईयों द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कम से कम एक खुराक से डिस्चार्ज के बाद मृत्यु दर के खिलाफ लगभग 60% सुरक्षा प्रदान करता है।

अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष:

- शोध में पाया गया है कि अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों में डिस्चार्ज के बाद मृत्यु दर 6.5% है। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष रोगी मध्यम से गंभीर कोविड -19 बीमारी से पीड़ित थे जिसमें अस्पताल से छुट्टी के एक वर्ष के भीतर मृत्यु की संभावना अधिक थी।
- शोध में यह बताया गया है कि 17.1% प्रतिभागियों में पोस्ट-कोविड स्थिति की सूचना मिली थी जो डिस्चार्ज के बाद मृत्यु दर की 2.7 गुना अधिक संभावना से जुड़ा था।
- नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ने सितंबर 2020 और फरवरी 2023 के बीच कोविड-19 के लिए तीन नेस्टेड केस-कंट्रोल विश्लेषणों की श्रृंखला पर डेटा एकत्र किया।
- नेस्टेड केस-कंट्रोल विश्लेषण ऐसे अध्ययन होते हैं जिनमें मिलान किए गए नियंत्रणों की तुलना में निदान किए गए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनमें बीमारी विकसित नहीं हुई है।

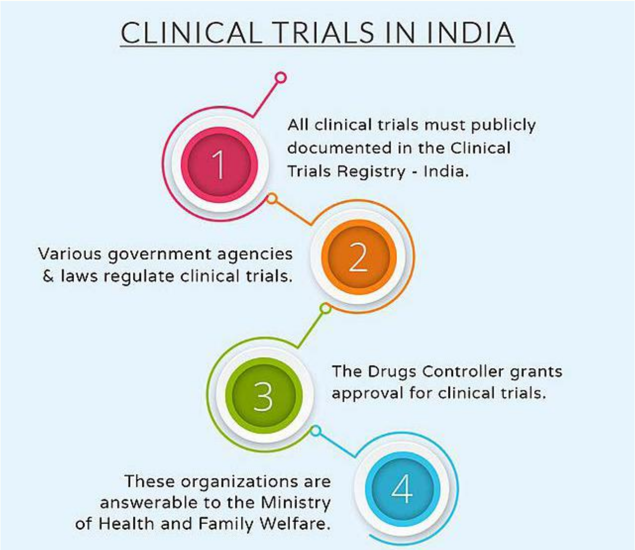

पोस्ट कोविड स्थिति क्या है?

- रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा पीसीसी को 'संकेत, लक्षण या स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रारंभिक संक्रमण के चार सप्ताह या उससे अधिक समय तक बनी रहती है या विकसित होती है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन में संवैधानिक, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सहित अन्य लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

कोविड-19 टीकाकरण का लाभ:

- शोध से पता चला है कि टीके की प्रभावशीलता 165-195 दिनों के बाद कम हो गई लेकिन फिर भी लगभग 86% थी। इसलिए इसने कम से कम एक खुराक से पोस्ट-डिस्चार्ज मृत्यु के खिलाफ 60% सुरक्षा प्रदान की।

कोविड-टीकाकरण का कवरेज:

- राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम जनवरी 2021 से शुरू किया गया था और मार्च 2023 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने स्वीकृत टीकों की कुल मिलाकर 2.2 बिलियन से अधिक खुराकें (पहली, दूसरी और एहतियाती/बूस्टर खुराक सहित) दी हैं।

आगे की राह:

वर्तमान अध्ययन ने पोस्ट-कोविड रोगियों के लिए सतर्क चिकित्सा कार्यवाही के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से नियमित, सस्ती तथा सक्रिय जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि बीमारी के प्रारंभिक चरण में बेहतर उपचार प्रदान किया जा सके।

5 मेटाजेनोम सीक्वेंसिंग और पैथोजेन सर्वेलेंस

चर्चा में क्यों?

मेटाजेनोम सीक्वेंसिंग ने COVID-19 महामारी के दौरान पैथोजेन सर्वेलेंस को क्रांति दिलाई। पारंपरिक तरीकों के विपरीत, वैज्ञानिकों ने त्वरित रूप से मरीजों के नमूनों से वायरस के जीनोम का सीक्वेंसिंग करके विश्लेषण किया।

मेटाजेनोम सीक्वेंसिंग क्या है?

- यह व्यक्तिगत माइक्रोऑर्गेनिज्मों को अलग करने की आवश्यकता को नजरअंदाज करके माइक्रोबियल समुदाय का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है।
- मेटागेनोमिक्स एक नमूने के भीतर संपूर्ण आनुवंशिक विविधता को कैप्चर करता है, बिना इस बात की पूर्व जानकारी के कि क्या मौजूद हो सकता है?
- यह पैथोजेन्स की जीनोम को सीक्वेंसिंग करके उनकी पहचान करने के लिए त्वरित तरीके से सक्षम करता है तथा पारंपरिक माइक्रोबायोलॉजिकल तकनीकों की आवश्यकता को दूर करता है।
- इसे एक ही सैम्पल के भीतर कई जीनोम का समय-समय पर विश्लेषण करने के लिए समर्थ बनाता है जो जटिल माइक्रोबियल पारिस्थितिकि का अध्ययन करने के लिए प्रभावी होता है।
- यह विशेष प्राइमर्स या लक्ष्यों पर निर्भर नहीं करता, इसलिए नई

या अज्ञात पैथोजेन्स की पहचान करने में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

- पैथोजेन्स की जीनेटिक संरचना, संभावित प्राकोपिक घटकों और पैथोजेन्स के विकास के परिप्रेक्ष्य में अनुशासन प्रदान करता है।
- महामारी के समय पैथोजेन्स के मूल, प्रसारण पथ और जीनेटिक परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करता है।
- मेटागेनोमिक्स रोगी के नमूनों से सीधे कारक एजेंट की पहचान करके संक्रमण का निदान करने में सहायता कर सकता है।

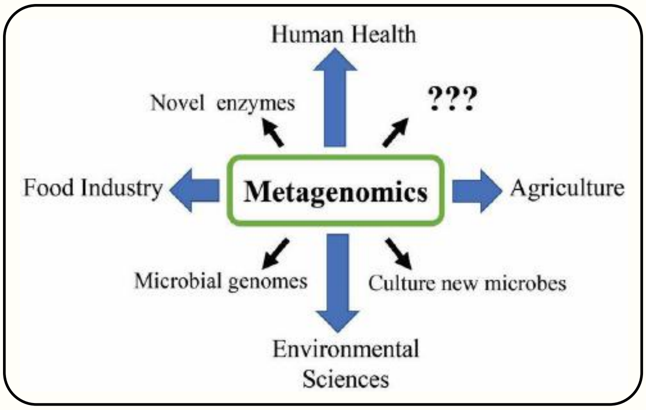

पैथोजेन सर्वेलेंस:

- पैथोजन सर्वेलेंस का मतलब है कि पैथोजेन्स (रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव) का विश्लेषण करना, उनकी मौजूदगी, प्रसारण और जनस्वास्थ्य पर प्रभाव को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह सर्वेलेंस संक्रामक बीमारी के प्रकोप की पहचान, प्रतिक्रिया और नियंत्रण के लिए सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

प्रयोग:

- पारंपरिक माइक्रोबायोलॉजी विधियों की तुलना में वैज्ञानिकों ने संक्रमित रोगी के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए मेटाजेनोम सीक्वेंसिंग का चयन किया। मेटाजेनोम में वायरस के जीनेटिक सामग्री का सीक्वेंसिंग सीधे पर्यावरणीय नमूनों से किया जाता है जिसमें इस मामले में मरीज के नमूने शामिल हैं।
- मेटाजेनोम एक दृष्टिकोण है जिसके लिए पूर्व जानकारी पैथोजेन्स के बारे में आवश्यक नहीं होती। इससे वैज्ञानिकों को विशिष्ट नैदानिक परीक्षणों या ज्ञात पैथोजेन्स का लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी कारक एजेंट की पहचान की जाती है।
- मेटाजेनोम का प्रयोग उन्नत जैव-सूचना विज्ञान के साथ मिलाकर वायरस की त्वरित पहचान की समर्थन किया। पारंपरिक तरीके जीव-संक्रमक को पालन करने की आवश्यकता होती है जो समय लेता है। मेटाजेनोम की गति महामारी का तुरंत प्रतिसाद देने के लिए महत्त्वपूर्ण थी।
- इस दृष्टिकोण का प्रयोग नए पैथोजेन्स की पहचान तथा विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है जो संकटों के संदर्भ में त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करता है।
- मेटाजेनोम का प्रयोग संक्रामक एजेंट्स की पहचान और अध्ययन करने के लिए तेज और अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए पथोजन सर्वेलेंस के क्षेत्र को परिवर्तित किया है।

आगे की राह:

मेटाजेनोम सीक्वेंसिंग एक नवाचारी दृष्टिकोण है जिसमें सीधे जीनोम सीक्वेंसिंग और बायोइंफॉर्मेटिक विश्लेषण शामिल है जिससे त्वरित रूप से COVID-19 के कारण SARS-CoV-2 की पहचान की गई। पारंपरिक तरीकों से अलग, इस तकनीक ने वैज्ञानिकों को त्वरित रूप से वायरस की पहचान करने की संभावना को पहचाने में सहायक होगा।

6 शिशुओं में आरएसवी वायरस को रोकने हेतु फाइजर के टीके को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

आरएसवी वायरस से नवजात शिशुओं की रक्षा हेतु एक नया टीका अब गर्भवती महिलाओं के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। आरएसवी के लिए एक नया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी शिशुओं और बच्चों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।

मोनोक्लोनल शरीर:

- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मानव निर्मित प्रोटीन हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मानव एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं।

रेस्पिरेटरी सिंसी टीएएल वायरस (RSV) के बारे में:

- यह एक संक्रमित व्यक्ति से श्वसन संक्रमण, खांसी तथा छींकना आदि से फैलता है।
- आरएसवी को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस (एचआरएसवी) और ह्यूमन ऑर्थोन्यूमोवायरस भी कहा जाता है।
- यह अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो सामान्य रूप से शिशुओं और कुछ चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों में श्वसन बीमारी का कारण बनता है।
- यह सिंगल-स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है।
- इसका नाम बड़ी कोशिकाओं से सम्बंधित है जिन्हें सिंकिटिया कहा जाता है जो संक्रमित कोशिकाओं के फ्यूज होने पर बनते हैं।
- आरएसवी कठोर सतहों पर कई घंटों तक जीवित रह सकता है।

लक्षण:

- इन्फ्लुएंजा (फ्लू) या (सीओवीआईडी -19) की तरह आरएसवी के लक्षणों में खांसी, छींकना, बुखार, नाक से घरघराहट और भूख में कमी आदि प्रमुख हैं।

फाइजर की मातृ वैक्सीन के बारे में:

- 32 से 36 सप्ताह की गर्भवती माताओं को शिशुओं में लोअर श्वसन पथ के संक्रमण और संक्रामक रोग को रोकने के लिए दिया जाता है, जब तक कि वे छह महीने के नहीं हो जाते।
- वैक्सीन गंभीर बीमारी का मुकाबला करने में 80% से अधिक प्रभावी है जिसके लिए जीवन के पहले तीन महीनों के दौरान शिशुओं के बीच डॉक्टर की आवश्यकता होती है और फिर 6

महीने तक जोखिम कम हो जाता है।

- यह मातृ टीकाकरण गर्भवती महिलाओं को दूसरे और शुरुआती तीसरे तिमाही के दौरान भ्रूण को रोग-विशिष्ट एंटीबॉडी को बनाने में मदद करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- फाइजर ने वयस्कों में आरएसवी की रोकथाम के लिए आरएसवीपीआरईएफ के लिए भी मंजूरी मांगी है।

आगे की राह:

आरएसवीपीआरईएफ का संभावित अनुमोदन आरएसवी से संबंधित बीमारी की रोकथाम में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, कमजोर आबादी को सुरक्षा प्रदान करता है और संभावित रूप से आरएसवी संक्रमणों के वैश्विक बोझ को कम करता है।

7 नैनोमेकैनिकल परीक्षण प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?

भारतीय वैज्ञानिक डॉ. सुधर्शन फणि ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करके (जिनमें केएलए कॉर्प और टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय भी शामिल हैं) एक नवाचारिक तरीका विकसित किया है जिसका उपयोग बहुत ही छोटे मापों पर सामग्रियों की नैनोमेकैनिकल गुणों का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है जिसमें उच्च सटीकता और प्रेशन होता है।

नैनोमेकैनिकल परीक्षण क्या है?

- नैनोमीटर स्केल पर यांत्रिक गुणों का परीक्षण किया जाता है।
- एक हीरे के टिप वाले इन्डेंटर का उपयोग नियंत्रित बल लागू करने के लिए किया जाता है।
- इन्डेंटर सामग्री की सतह में एक निश्चित गहराई तक प्रवेश करता है।
- लागू किए गए बल और गहराई को निरंतर ट्रैक किया जाता है।
- बल-गहराई डेटा सामग्री के प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है।
- प्राप्त जानकारी में हार्डनेस, लचीला मोड्यूलस, कठोरता शामिल है।
- धातु, पॉलिमर, जैव सामग्री जैसे विभिन्न सामग्रियों के लिए उपयुक्त।
- नैनोमीटर स्केल संरचनाओं के लिए उपयुक्त।
- सामग्री विज्ञान, इंजीनियरिंग, नैनोटेक्नोलॉजी में उपयोग होता है।
- नई तकनीकें तेज परीक्षण दरें प्राप्त करने की संभावना प्रदान करती हैं।

नैनोइंडेंटेशन परीक्षण की मुख्य विशेषता:

- नैनोइंडेंटेशन परीक्षण बहुत छोटे स्तर पर यांत्रिक गुणों की सटीक और विश्वसनीय मापें प्रदान करता है जिससे शोधकर्ताओं को सामग्री के व्यवहार को नैनोमीटर स्तर पर समझने की अनुमति मिलती है।
- पारंपरिक यांत्रिक परीक्षण विधियाँ अक्सर नैनोस्केल सामग्रियों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं क्योंकि नमूने के आकार और उपकरण की संवेदनशीलता में सीमाएँ होती है।
- नैनोइंडेंटेशन धातु, पॉलिमर, सिरेमिक्स और जैविक ऊतकों सहित विभिन्न सामग्रियों पर किया जा सकता है। यह विभिन्न सामग्रियों और अनुप्रयोगों में यांत्रिक गुणों की विशेषता का वर्गीकरण करने में मदद करता है।
- प्रारंभिक विवरण में उल्लिखित नवाचारिक मैथोडोलॉजी नमूनों के उच्च प्रवाह की संभावना को बढ़ाती है जिससे नमूनों की अधिक प्रवाह की संभावना होती है।

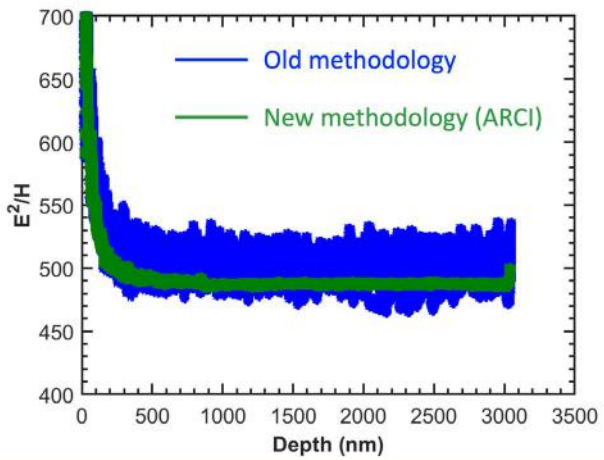

अनुप्रयोग:

- यह नया तरीका यांत्रिक मजबूती को तेज परीक्षण की अनुमति देता है।
- चिकित्सा से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।
- **प्रेसिजन में सुधार:** नैनोइंडेंटेशन परीक्षण की प्रेसिजन और सटीकता को बढ़ावा देता है।
- एक मानव बाल के व्यास के लगभग 1/100 तक के स्केल की सामग्रियों के लिए उपयुक्त है।
- सेमीकंडक्टर्स और संरचनात्मक सामग्रियों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर इसका उपयोग किया जा सकता है।
- कैंसर कोशिकाओं की पहचान और जैव सामग्रियों का विश्लेषण करने में सहायक।
- गहरे अंतरिक्ष में उल्का गठन का अध्ययन करने में उपयोगी।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग से विकसित किया गया है।
- तरीका सुधार के लिए विस्तृत मॉडलिंग और सिमुलेशन शामिल है।
- मॉडलिंग के परिणाम अत्यधिक परिस्थितियों में प्रयोगों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है।
- विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्रों पर प्रभाव डालने की संभावना है।

आगे की राह:

नव विकसित नैनोमेकैनिकल परीक्षण पद्धति कई क्षेत्रों और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण वादा करती है। इसकी क्षमता का लाभ उठाकर और चल रहे सहयोग तथा अनुसंधान को बढ़ावा देकर, वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रख सकते हैं।

1 RBI ने अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगाने हेतु UDGAM पोर्टल किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नागरिकों को उनके अनक्लेम्ड अमाउंट की खोज में मदद करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसे UDGAM (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information) के रूप में जाना जाता है।

UDGAM पोर्टल के बारे में:

- यह पोर्टल केंद्रीय बैंक द्वारा जनता के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में उनकी अनक्लेम्ड अमाउंट की खोज में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। सर्वप्रथम इसकी घोषणा 6 अप्रैल, 2023 को एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल के रूप में की गई थी।
- आरबीआई अनक्लेम्ड अमाउंट की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इस मामले पर जनता को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है।
- इस पहल के माध्यम से आरबीआई अपने सदस्यों को अनक्लेम्ड डिपोजिट का दावा करने के लिए अपने संबंधित बैंकों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

यह कैसे कार्य करेगा?

- इस पोर्टल के लॉन्च होने से उपयोगकर्ताओं को अपने अनक्लेम्ड डिपोजिट अथवा खातों की जानकारी करने में मदद मिलेगी और वे जमा राशि का दावा करने या अपने जमा खातों को अपने संबंधित बैंकों में चालू करने में सक्षम होंगे।
- इस पोर्टल को रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (REBIT), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (IFTAS) और भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से विकसित किया गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया और सिटी बैंक ऐसे बैंक हैं जिसके उपयोगकर्ता इस पोर्टल के द्वारा अपने अनक्लेम्ड अमाउंट का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

पंजीकरण का तरीका क्या है?

- इस पोर्टल में उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड तथा कैप्चा दर्ज करना होगा और फिर सबमिट करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसके बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके UDGAM खाते में लॉग इन कर सकते हैं।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ताओं को एक पेज पर पुनः खाताधारक का नाम, बैंक का नाम, एक आईडी जैसे पैन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर आदि दर्ज करना होगा।

आगे की राह:

यह केंद्रीकृत वेब पोर्टल उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही विंडो के माध्यम से कई बैंकों में अपने अनक्लेम्ड डिपोजिट/एकाउंट को खोजने और पहचानने के लिए एक आदर्श मंच होगा। भारत में अनक्लेम्ड डिपोजिट की कुल राशि 35,000 करोड़ रुपये है, जबकि कई खातों को या तो हटा दिया गया है या फिर अनदेखा कर दिया गया है।

2 ब्याज को विनियमित करने के लिए बैंकों तथा एनबीएफसी के लिए नए दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क तथा ब्याज दरों के खुलासे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे।

आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देश:

- RBI ने कहा कि उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्त्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा तथा उसे दर में जोड़े जाने वाले 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। हालाँकि इससे ऋण खाते की ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।
- विनियमित संस्थाएं ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल न करके इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
- इसमें दंडात्मक शुल्क की उचित मात्रा होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभावपूर्ण हुए बिना ऋण अनुबंध के महत्त्वपूर्ण नियमों तथा शर्तों का अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।
- इसके अंतर्गत विनियमित संस्थाएं (REs) अपने नीतिगत ढांचे में उचित संशोधन कर सकती हैं और प्रभावी तिथि से नवीनीकृत किए गए सभी संस्थाएं नए ऋणों के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकती हैं।
- विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण नियमों तथा शर्तों को मुख्य तथ्य विवरण (KFS) में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसके अलावा आरईएस वेबसाइट पर ब्याज दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

यह नियम किस पर प्रभावी होगा?

- यह नियम आरबीआई द्वारा विनियमित सभी बैंकिंग संस्थाओं पर लागू होंगे जिनमें सभी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
- हालाँकि यह निर्देश क्रेडिट कार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार क्रेडिट और संरचित दायित्वों पर लागू नहीं होंगे जो उत्पाद-विशिष्ट निर्देशों के अंतर्गत आते हैं।

आगे की राह:

केंद्रीय बैंक ने कहा कि दंडात्मक ब्याज अथवा शुल्क लगाने से अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे शुल्कों का उपयोग अनुबंधित ब्याज दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।

3 बहुपक्षीय विकास बैंक

चर्चा में क्यों?

जी-20 के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का ध्यान बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करने पर रहा है।

बहुपक्षीय विकास बैंक के बारे में:

- एमडीबी एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई सदस्य देशों द्वारा मिलकर स्थापित किया गया है। उदाहरण: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि। ये विकासशील देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

एमडीबी का उद्देश्य:

- एमडीबी गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास, मानव पूंजी निर्माण आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करके कम आय और मध्यम आय वाले देशों दोनों के विकास का समर्थन करने में सहायक रहे हैं।
- हालाँकि, एमडीबी को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है जो बदलते वैश्विक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता और प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।
- एमडीबी द्वारा उधार लेने वाले देशों पर लगाई गई शर्तें हमेशा उचित नहीं होती हैं।
- वे ऋणों में सशर्तता लागू करते हैं।
- **पश्चिमी प्रभुत्व:** विश्व बैंक अध्यक्ष नामित होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुझाव देना, जबकि आईएमएफ अध्यक्ष हमेशा एक यूरोपीय नागरिक होना।

पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव:

- **एमडीबी में सुधार की आवश्यकता:** भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत विशेषज्ञ समूह ने ट्रिपल जनादेश को अपनाने का सुझाव दिया।
- वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश को बढ़ावा देकर अत्यधिक गरीबी को खत्म करना।
- **विकासशील देशों में वित्त की आवश्यकता-** विश्व बैंक समूह का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और महामारी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 2023 से 2030 के बीच प्रति वर्ष औसत वार्षिक खर्च $2.4 ट्रिलियन होगा।
- **निजी क्षेत्र का निवेश जुटाना:** मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त निजी वित्त जुटाने में विफल रही है। मांग पक्ष में, निजी पूंजी से जुड़े नैतिक खतरों के बारे में चिंताएं हैं, जबकि आपूर्ति पक्ष निजी पूंजी जोखिमों से प्रतिरक्षित नहीं है। जैसे कि विदेशी मुद्रा से जुड़े जोखिम।
- अन्य सिफारिशें जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार, देश-विशिष्ट रणनीतियाँ और क्षेत्रीय चुनौतियों पर सामूहिक कार्यवाही करना आदि।

आगे की राह:

समावेशी विकास और साझा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एमडीबी में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। भारत के लिए एमडीबी में सुधार का मतलब ग्लोबल साउथ की आवाज की वकालत करना होगा।

4 आरबीआई ने पब्लिक टेक प्लेटफार्म किया लांच

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋण तक पहुंच को आसान बनाने के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस कदम का उद्देश्य ऋणदाताओं को कुछ ही मिनटों में ऋण या लोन की सुविधा के लिए डिजिटल जानकारी प्रदान करना है।

पब्लिक टेक प्लेटफार्म क्या है?

- यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है। प्लेटफॉर्म में एक खुला आर्किटेक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानक भी होंगे जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ी 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में जुड़ सकते हैं।
- वर्तमान समय में क्रेडिट मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, खाता एग्रीगेटर्स, बैंकों, क्रेडिट सूचना कंपनियों तथा डिजिटल पहचान प्राधिकरणों जैसी विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध है। इससे नियम-आधारित ऋण देने में बाधा उत्पन्न हुई है।
- पायलट कार्यक्रम के दौरान प्लेटफॉर्म प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, डेयरी ऋण, एमएसएमई ऋण (संपार्श्विक के बिना), व्यक्तिगत ऋण और भाग लेने वाले बैंकों के माध्यम से गृह ऋण जैसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- क्रेडिट देने की प्रक्रिया में क्रेडिट मूल्यांकन शामिल होता है जिसमें उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता और क्रेडिट समझौते का पालन करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

पायलट प्रोजेक्ट उदाहरण:

- डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड डेटा का उपयोग कुछ ही मिनटों में ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने के लिए किया जा सकता है? इससे किसानों को भौतिक बैंक शाखाओं में जाने की आवश्यकता से मुक्ति मिल जाती है। यह पूरी तरह से कागज रहित और डिजिटलीकृत था।
- इसी तरह इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल डेयरी लोन ने दूध सहकारी समितियों के पास उपलब्ध डेटा का लाभ उठाया है जिससे संवितरण प्रक्रिया के लिए ऋण मंजूरी को एंड-टू-एंड डिजिटाइज किया गया।

लाभ:

- ऋण तक पहुंच में सुधार।
- परिचालन लागत एवं समय में कमी।
- उन्नत क्रेडिट पोर्टफोलियो प्रबंधन।
- अधिक कुशल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र।
- आधार ई-केवाईसी एण्ड ऑनबोर्ड राज्य सरकारों (एमपी, टीएन, कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र) से भूमि रिकॉर्ड जैसी सेवाओं के साथ लिंकेज को सक्षम करना।

आगे की राह:

पायलट प्रोजेक्ट लर्निंग के आधार पर अधिक उत्पादों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार किया जाएगा जिससे निर्बाध क्रेडिट वितरण की सुविधा मिलेगी। इससे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

5 बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी (ABBFF) पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी (एबीबीएफएफ) पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों द्वारा जांच के लिए सिफारिशें या संदर्भ दिए जाने से पहले बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर की जाँच करेगा।

बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड के बारे में:

- यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों द्वारा जांच के लिए सिफारिशें या संदर्भ दिए जाने से पहले बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर की जांच करता है।
- इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले में अधिकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों (पूर्व अधिकारियों/पूर्व पूर्णकालिक निदेशकों सहित) की भूमिका की जांच करने का अधिकार दिया गया है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी किसी मामले या तकनीकी मामले को सलाह के लिए बोर्ड को भेज सकता है।
- यह बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सतर्कता आयोग को धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण के लिए इनपुट भी दे सकता है।
- यह आमतौर पर प्रारंभिक संदर्भ प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीआई द्वारा मांगे जाने पर अपनी सलाह देगा।
- इसमें अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- एबीबीएफएफ का मुख्यालय- नई दिल्ली

केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में:

- इसकी स्थापना सरकार द्वारा 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी।
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा शासित एक वैधानिक निकाय है।
- सीवीसी किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं है।
- लोक सेवकों, किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किए गए कथित अपराधों की जांच करना।
- आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और सतर्कता आयुक्त (सदस्य) दो से अधिक नहीं।
- नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मामलों के मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।
- **अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल**- नियुक्त होने की तिथि से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

आगे की राह:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले 10 वर्षों में पीएमएलए के तहत सार्वजनिक प्रथा और निजी क्षेत्र के बैंकों में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े 757 मामले और चालू वर्ष में 36 मामले दर्ज किए हैं। यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य है। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम ऋण धोखाधड़ी के संबंध में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

6 'रेल-समुद्र-रेल परिवहन' को बढ़ावा देने की नई पहल

चर्चा में क्यों?

घरेलू कोयले की कुशल आवाजाही के लिए रेल-समुद्र-रेल (आरएसआर)

परिवहन को बढ़ावा देने की पहल भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग में क्रांति लाने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता के कारण चर्चा में है।

उपाय के मुख्य बिंदु:

- कोयला मंत्रालय घरेलू कोयले के प्रशासनिक चलन के लिए रेल-समुद्र-रेल (RSR) परिवहन के मिलाप को बढ़ावा देने का प्रचार कर रहा है।
- RSR माइनों से बंदरगाहों और फिर गंतव्य स्थान तक कोयले के सुगम परिवहन की अनुमति देता है, परिवहन लागतों को कम करता है और परिवहन की दक्षता में सुधार करता है।
- ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों ने वित्तीय वर्ष (FY) 2023 में कुल घरेलू कोयले के प्रेषण का लगभग 75% योगदान किया।
- मंत्रालय का लक्ष्य FY 2030 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ भारत में कोयले के उत्पादन को दुगुना करना है।
- **अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी):** आईएमसी विद्युत आपूर्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पोर्ट, शिपिंग तथा जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिलकर बनाई गई है। आईएमसी दीर्घकालिक कोयले परिवहन रणनीतियों की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है।
- वर्तमान में रेलवे कोयले के निकास का लगभग 55% योगदान करता है। इसका लक्ष्य है कि FY 2030 तक इस हिस्से को 75% तक बढ़ा दिया जाए।
- RSR मोड सभी रेल मार्ग पर भरपूर भीड़ को कम करने का लक्ष्य रखता है और कोयले के निकास के लिए एक पर्याप्त विकल्प प्रदान करता है।
- समिति का लक्ष्य FY 2030 तक RSR के माध्यम से 2030 में 112 MT कोयले का निकास प्राप्त करना है जो वर्तमान के 40 MT से अधिक होगा।
- RSR भीड़ को कम करता है, निर्यात के अवसर पैदा करता है और ऑल-रेल रूट (एआरआर) की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जित करता है।

रेल-समुद्र -रेल (RSR) के लाभ:

- आरएसआर रेल और समुद्री साधनों को एकीकृत करता है जिससे खदानों से बंदरगाहों तथा फिर अंतिम उपयोगकर्ताओं तक एक निर्बाध परिवहन प्रणाली तैयार होती है। इससे कोयले की आवाजाही को सुव्यवस्थित करते हुए हैंडलिंग और स्थानांतरण संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं।
- RSR वस्तुओं के आवागमन के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है, खासकर दक्षिण भारत में यह पारंपरिक तरीकों के मुकाबले लगभग 760-1300 रुपये प्रति टन तक की बचत कर सकता है। यह लागत-कुशलता व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता को बढ़ावा देती है।
- RSR ऑल-रेल रूट (ARR) के साथ तुलना में कार्बन प्रिंट कम होता है जो पर्यावरण हितैशी होने का एक अच्छा उदाहरण है।
- कोयले के RSR परिवहन ने पिछले चार सालों में लगभग 125% की महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर का सामर्थ्य और संभावना को दर्शाया है जो प्रभावकारिता तथा विस्तार की संभावना को सुझाता है।

आगे की राह:

रेल, समुद्र और फिर से रेलवे जैसे कई परिवहन मोड का एक सम्मिलित दृष्टिकोण, लॉजिस्टिकल कुशलता तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न लाभ प्रस्तुत करता है। क्योंकि कोयले का उत्पादन बढ़ने की संभावना है जिससे पहल का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

7 भारत के लिए आर्कटिक के उत्तरी सागर मार्ग का बढ़ता महत्त्व

चर्चा में क्यों?

आर्कटिक महासागर में संचार का प्रमुख समुद्री लेन (एसएलओसी), उत्तरी सागर मार्ग (एनएसआर) भारत के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत 2023 के 7 महीनों में एनएसआर के माध्यम से मरमांस्क बंदरगाह द्वारा भेजे गए कुल कार्गो का 35% का प्रमुख प्राप्तकर्ता है।

उत्तरी सागर मार्ग क्या है?

- उत्तरी सागर मार्ग (जिसे पूर्वोत्तर मार्ग के रूप में भी जाना जाता है) आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ता है। यह मार्ग यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच माल ढुलाई के लिए सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है। इसमें आर्कटिक महासागर के चार समुद्र यानी बैरेंट्स, कारा, लापटेव और पूर्वी साइबेरियाई सागर शामिल हैं जिसका विस्तार 5,600 किमी है।

एनएसआर भारत के लिए महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- इस मार्ग से जुड़ा प्रमुख लाभ इसकी सामर्थ्य है और समय की खपत पारंपरिक समुद्री मार्गों (स्वेज और पनामा नहर) की तुलना में अनुकूल है। इसमें शिपिंग लागत को 50% तक कम करने की क्षमता है।
- भारत रूसी आयातित कोयले तथा कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है और इस व्यापार का प्रमुख हिस्सा समुद्री परिवहन से जुड़ा हुआ है।
- प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्वोस्ताक समुद्री गलियारा (सीवीएमसी) परियोजना पर 2019 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय स्तर पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें परिवहन समय को 12 दिनों (वर्तमान अवधि का लगभग एक तिहाई) तक कम करने की क्षमता है। यह सीवीएमसी (10,500 किमी) जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरेगी।
- यह मार्ग रूसी एजेंसियों द्वारा प्रमुख रूप से नियंत्रित है जिनके साथ भारत के सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण रणनीतिक संबंध हैं। इससे भारत इस मार्ग में बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित कर सकता है। चीन का ध्रुवीय रेशम मार्ग एनएसआर और आर्कटिक क्षेत्र पर एकाधिकार करने का लक्ष्य रख रहा है।

आर्कटिक क्षेत्र की संभावनाएं और खतरेः

- आर्कटिक क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है जिसमें आर्कटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव शामिल हैं। इसमें खनिजों, हाइड्रोकार्बन संसाधनों, कोयला, जिप्सम, हीरे और अन्य दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की विशाल मात्रा है। अकेले ग्रीनलैंड में दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी भंडार का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।
- लेकिन आर्कटिक क्षेत्र वर्तमान जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे वलनरेबल बना हुआ है। आर्कटिक में वार्मिंग दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत तेजी से हुई है। पर्माफ्रॉस्ट पिघलने से वायुमंडल में जीएचजी गैसों की मात्रा और बढ़ेगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है।

आगे की राहः

आर्कटिक क्षेत्र भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अत्यधिक भू-रणनीतिक महत्त्व रखता है। इसके साथ ही संबंधित पर्यावरणीय जटिलताएं भी विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय हैं। इसलिए भारत को एनएसआर मार्ग के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूसी एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और अपने वैज्ञानिकों को स्थायी खोज विकल्पों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

1 यूजीसी ने पांडुलिपियों के अध्ययन के लिए पैनल का गठन किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एक विशेष पैनल का गठन किया है जो देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पांडुलिपि विज्ञान तथा पुरातत्व में पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु एक मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करेगा।

पैनल से सम्बंधित मुख्य बातें:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पांडुलिपि विज्ञान तथा पुरालेख विज्ञान में पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु एक मॉडल पाठ्यक्रम विकसित किया।
- इस ग्यारह सदस्यीय पैनल का नेतृत्व राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के पूर्व निदेशक प्रफुल्ल मिश्रा करेंगे जिसमें आईआईटी-मुंबई के प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज, गुजरात विश्वविद्यालय और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक भी शामिल होंगे।
- यूजीसी के अनुसार इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित किया गया है। यह पांडुलिपि विज्ञान में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए कार्य करेगा।
- इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं, पांडुलिपियों में दर्शन, विज्ञान, साहित्य, धर्म और विविध विषयों को भी शामिल किया गया है।

पांडुलिपि विज्ञान और पुरालेख क्या है?

- पांडुलिपि विज्ञान हस्तलिखित दस्तावेजों के माध्यम से इतिहास और साहित्य का अध्ययन है, जबकि पुरालेख प्राचीन लेखन प्रणालियों का अध्ययन है। हालाँकि अधिकतर पुरालेख शास्त्रीय और मध्ययुगीन काल की रचना मानी जाती है।
- भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण देश की विविधता को बनाए रखने में अपना योगदान देती है एवं विरासत की गहरी समझ विकसित करती है जो अतीत के विचारों, विश्वासों और प्रथाओं को दर्शाती हैं।
- पांडुलिपियाँ भारत के इतिहास तथा बौद्धिक परंपराओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि, संस्कृति का संरक्षण, अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की क्षमता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के अनुसार भारत में 80 प्राचीनतम लिपियों में लगभग 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं जो ताड़ के पत्ते, कागज, कपड़े और छाल जैसी सामग्रियों पर लिखी हैं।
  - वर्तमान पांडुलिपियों में से 75% संस्कृत में हैं, जबकि 25% अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।
  - भारत में ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा और मैथिली जैसी अनेक प्राचीन पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं।

आगे की राह:

भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में पांडुलिपि का अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा जिससे एक मॉडल पाठ्यक्रम विकसित होगा तथा संस्कृति एवं प्राचीन सभ्यताओं को छात्रों के लिए खुले ऐच्छिक विषय के रूप में मौजूद होगा।

2 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर (NMC) में की गई। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 में सेंसर की गई फिल्मों के लिए सम्मान की घोषणा हुई। यह कार्यक्रम भारत सरकार के फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

69वें फिल्म पुरस्कार से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्रीः द नांबी इफेक्ट' को प्रदान किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्रमशः गंगूबाई काठियावाड़ी, मिमी के लिए आलिया भट्ट और कृति सेनन को प्रदान किया गया।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 'पुष्पा' के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले तेलुगु अभिनेता हैं।
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार 'मिमी' के लिए पंकज त्रिपाठी को दिया गया। यह पुरस्कार उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था।
- शूजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म 'सरदार उधम' ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। यह फिल्म 2021 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी तथा इसमें विक्की कौशल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार 'द कश्मीर फाइल्स' के लिए पल्लवी जोशी को प्रदान किया गया।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मराठी फिल्म 'गोदावरी' के लिए निखिल महाजन को दिया गया है।
- राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा फिल्म निर्माता केतन मेहता द्वारा किया गया जिन्होंने 11 सदस्यीय जूरी का नेतृत्व किया।
- सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार बहुभाषी फिल्म 'आरआरआर' के तेलुगु संस्करण को प्रदान किया गया है।

अन्य फिल्म पुरस्कारों की घोषणा:

- मिठू दी (अंग्रेजी) के निर्माता और निर्देशक असीम कुमार सिन्हा को पुरस्कार प्रदान किया गया।
- थ्री टू वन (मराठी और हिंदी) के निर्माता एफटीआईआई तथा निर्देशक हिमांशु प्रजापति को साझा पुरस्कार प्रदान किया गया।
- कृषि सहित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म पुरस्कार मुन्नम वलावु (मलयालम) के निर्माता श्री गोकुलम मूवीज और निर्देशक आरएस प्रदीप को प्रदान किया गया।

- सर्वश्रेष्ठ प्रमोशनल फिल्म लुप्तप्राय विरासत 'वर्ली आर्ट' (अंग्रेजी) के निर्माता बाबा सिनेमाज तथा निर्देशक हेमंत वर्मा को प्रदान किया गया।
- सर्वश्रेष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी फिल्म 'एथोस ऑफ डार्कनेस' के निर्माता श्री गणेश प्रोडक्शंस तथा निर्देशक अविजीत बनर्जी को मिला।

आगे की राह:

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों की समझ और योगदान देने वाली तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ाना एवं सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना जिससे राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बढ़ावा मिल सके।

3 कुवी और देसिया पुस्तकें लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने भुवनेश्वर में कुवी तथा देसिया पुस्तकें लॉन्च कीं। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग की ओर से विशेष कवर भी जारी किया गया। यह ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और एनसीईआरटी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है।

कुवी और देसिया पुस्तकों के बारे में:

- कुवी और देसिया पुस्तकें ओडिशा के आदिवासी समुदाय को एक मजबूत एवं शैक्षिक नींव प्रदान करेंगी जिससे सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विरासत और पहचान को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
- ये पुस्तकें छात्रों को उनकी स्थानीयता प्रकृति और संस्कृति के आधार पर चित्रों, कहानियों, गीतों की मदद से उनके बोलने के कौशल, सीखने के परिणाम तथा संज्ञानात्मक विकास में सुधार करना करेगा।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने पहली बार ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से इन बच्चों के लिए दो अमूल्य पुस्तकें 'कुवी प्राइमर' और 'डेसिया प्राइमर' भी तैयार की हैं।
- यह किताबें विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तैयार की गई हैं जो ओडिशा के अविभाजित कोरापुट क्षेत्र में 'कुवी' और 'देसिया' आदिवासी भाषा बोलते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 क्या है?

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा जुलाई 2020 में की गई थी। यह स्कूली शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव रखता है।
- इस नीति में मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की बात की गयी है।
- यह नीति भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति पर आधारित है।
- एनईपी 2020 का मुख्य लक्ष्य 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100% तक बढ़ाना है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में जीईआर को 26.3% से 2035 तक 50% तक लाना है।

मेरी माटी मेरा देश का दौरा:

- इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक की रेत कला 'मेरी माटी मेरा देश' का दौरा किया और शिलाफलकम (स्मारक पट्टिका) समर्पित की, साथ ही 1000 पौधे लगाकर छात्रों के साथ पंच प्राण प्रतिज्ञा भी ली गयी।
- इस अवसर पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया तथा दिल्ली में 'अमृत वाटिका' बनाने के लिए शहीद जयी राजगुरु के जन्मस्थान, पुरी जिले के बिरहरेकृष्णपुर गांव के प्रत्येक घर से 'अमृत कलश' में मिट्टी और चावल एकत्र किए।

आगे की राह:

ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत, बलिदान एवं वीरता का प्रमाण है जो मेरी माटी मेरा देश अभियान को और भी अधिक प्रासंगिक बनाती है। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने पुरी जिले के एक विरासत शिल्प गांव (रघुराजपुर) के कारीगरों के साथ बातचीत की और 'पीएम विश्वकर्मा' योजना के लाभों पर प्रकाश डाला।

4 आईएनएस विंध्यगिरि

चर्चा में क्यों?

जीआरएसई में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट 17ए का छठा स्टील्थ फ्रिगेट विंध्यगिरि को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। यह 'प्रोजेक्ट 17 अल्फा' के तहत नौसेना के लिए बनाए जा रहे सात जहाजों में से छठा जहाज है।

आईएनएस विंध्यागिरी के बारे में:

- आईएनएस विंध्यगिरि का नाम कर्नाटक के एक पर्वत शृंखला के आधार पर रखा गया है। जैसे नीलगिरी श्रेणी।
- भारतीय नौसेना में नीलगिरि श्रेणी के युद्धपोतों का नाम भारत की विभिन्न पर्वत शृंखलाओं के नाम पर रखा गया था।
- फ्रिगेट्स की शृंखलाओं में आईएनएस नीलगिरि, आईएनएस उदयगिरि, आईएनएस हिमगिरि, आईएनएस तारागिरि, आईएनएस दुनागिरि और आईएनएस विंध्यगिरि शामिल हैं।
- प्रत्येक जहाज का नाम एक विशिष्ट पर्वत शृंखला को दर्शाता है।
- यह नामकरण परंपरा भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं को रेखांकित करती है जो देश के परिदृश्य के साथ नौसेना के संबंध का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है।

आईएनएस विंध्यागिरी की विशिष्टता:

- प्रोजेक्ट का नाम: प्रोजेक्ट 17 अल्फा
- युद्धपोत का आकार: 149 मीटर
- विस्थापन: 6670 टन

- अतिरिक्त विशेषताएं: लंबी दूरी की टॉरपीडो और जहाज-रोधी मिसाइलें
- अधिकतम गति 28 समुद्री मील

परियोजना 17ए:

- भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया।
- भारतीय रक्षा बलों द्वारा स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण की पहल की गई।
- इसका निर्माण दो कंपनियों द्वारा किया जा रहा है: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई)।
- प्रोजेक्ट 17A की कुल कीमत लगभग 25,700 करोड़ रुपये है।
- प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ जहाज 2019 में नीलगिरि था।
- दूसरी जहाज उदयगिरि (जिसे 2022 मई में लॉन्च किया गया) 2024 में कॉमीशन किया जाने की संभावना है।

आगे की राह:

ये जहाज भारत की स्वदेशी उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित करते हैं जिसमें 75% उपकरण व प्रणालियां घरेलू कंपनियों सहित छोटे और मध्यम उद्यमों से जुड़े होते हैं। आईएनएस 'विंध्यगिरि' का कमीशनिंग भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति और समुद्री हितों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 'विंध्यगिरि' का प्रक्षेपण सहयोगात्मक प्रयासों के सफल परिणामों के साथ ही जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

5 आयुष्मान भारत पर सीएजी की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सीएजी रिपोर्ट ने आयुष्मान भारत-पीएम जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के डेटाबेस में गंभीर विसंगतियों को उजागर किया है।

एबी-पीएमजेएवाई के बारे में:

- यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रदान करती है।
- लाभार्थियों की पहचान नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा की गई है और वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) का गठन किया गया है, जबकि राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को राज्य स्तर पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पीएमजेएवाई की स्थिति:

- 10.74 करोड़ लक्षित परिवारों में से 7.87 करोड़ यानी 73% लाभार्थी पंजीकृत थे। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया।

REGISTRATION OF BENEFICIARIES AGAINST SAME OR INVALID MOBILE NUMBERS

Number of mobile numbers in system	Mobile number	Number of people registered against them
3		9,85,166
	9999999999	7,49,820
	8888888888	1,39,300
	9000000000	96,046
20		10001 to 50,000
1435		1001 to 10,000
185397		11 to 1,000

Source: CAG report

क्या विसंगतियां मिलीं?

- **फर्जी मोबाइल नंबर और आधार:** लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों को एक ही सेल फोन नंबर- 9999999999 से जोड़ा गया था। इसी तरह एक ही आधार नंबर कई लाभार्थियों से जुड़े थे।
- इसमें कहा गया कि 2.25 लाख मामलों में की गई 'सर्जरी' की तारीख डिस्चार्ज की तारीख के बाद की दिखाई गई।

- अन्य मामलों में डिस्चार्ज की तारीख एडमिट की तारीख से पहले और यहां तक कि योजना की शुरुआत से भी पहले थी। इसी तरह मृत व्यक्ति के नाम पर भी कई दावे किए गए।
- **अवास्तविक आकार:** कुछ मामलों में पंजीकृत घरों का आकार अवास्तविक रूप से बड़ा था जो 11 से 201 सदस्यों तक था।
- **पेंशनभोगी भी उठा रहे लाभ:** कुछ राज्यों में पेंशनभोगी पीएमजेएवाई कार्ड से उपचार का लाभ उठा रहे थे।
- सूचीबद्ध कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पताल, फार्मेसी, ब्लड बैंक, प्रयोगशाला, डायलिसिस यूनिट, पोस्ट-ऑपरेटिव सेवाएं तथा आईसीयू देखभाल आदि जैसी सेवाओं के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
- इसके अलावा सूची में कई अस्पतालों ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है अर्थात वे पीएमजेएवाई सेवाएं बिल्कुल भी प्रदान नहीं कर रहे थे। लाभार्थियों की संख्या की तुलना में शामिल अस्पतालों की कम संख्या, बार-बार होने वाले कदाचार, ढांचागत अपर्याप्तता आदि से समस्या और भी बढ़ गई है।
- **डेटा संग्रह में लंबित दंड और मुद्दे:** रिपोर्ट ने नौ राज्यों के 100 अस्पतालों से 12.32 करोड़ रुपये के लंबित दंड को चिह्नित किया।

आगे की राह:

एसएचए को धन जारी करने से पहले एनएचए द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए, साथ ही धोखाधड़ी का पता लगाने और लाभार्थी पहचान प्रणाली के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग की तैनाती से प्रमुख मदद मिल सकती है।

6 सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सुधारों की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुरक्षित और स्वच्छ डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा हेतु दो सुधार पेश किए गए। यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल वातावरण की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए है।

क्या सुधार हैं?

- » केवाईसी में सुधार
- » ट्रांसफॉर्मिंग प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पंजीकरण

- ये दो सुधार मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग की नागरिक केंद्रित पहल तथा संचार साथी पोर्टल के लॉन्च के साथ शुरू किए गए पिछले सुधारों की दिशा में हैं जो साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे से लड़ने में मदद करेगा।

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) सुधार:

- इस सुधार में लाइसेंसधारियों द्वारा फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों (पीओएस) के अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। इससे साइबर अपराध और धोखाधड़ी गतिविधियों के खतरे से निपटने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य उन पीओएस इकाईयों को खत्म करना है जो असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सिम जारी करके धोखाधड़ी करने में संलग्न हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में पीओएस और लाइसेंसधारियों के बीच मजबूत सत्यापन तथा लिखित समझौते शामिल हैं। कोई भी पीओएस अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसे बंद कर दिया जाएगा और तीन साल की ब्लैकलिस्टिंग अवधि का सामना भी करना पड़ेगा।

केवाईसी सुधार:

- केवाईसी ग्राहक को उनकी पहचान (आईडी) और पता सत्यापन दस्तावेजों जैसे पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि के माध्यम से पहचानने की प्रक्रिया है। यह दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से पहले ग्राहक का पता लगाने में सक्षम बनाता है। केवाईसी सुधार दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों को किसी भी संभावित धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में आम जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **आधार की क्यूआर कोड स्कैनिंग:** आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए, केवाईसी प्रक्रिया के दौरान मुद्रित आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके लोगों का विवरण लिया जाएगा।
- **मोबाइल नंबर विच्छेदन:** 90 दिनों की समाप्ति तक बंद हुए मोबाइल नंबर को किसी भी नए ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाएगा। ग्राहक को अपनी सिम बदलने के लिए केवाईसी पूरा करना होगा तथा आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं पर 24 घंटे की रोक होगी।
- **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण:** आधार ई-केवाईसी में अंगूठे का निशान और आईरिस आधारित प्रमाणीकरण तथा चेहरे आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति है।

संचार साथी पोर्टल:

- दूरसंचार विभाग के तहत विश्व दूरसंचार दिवस (17 मई 2023) पर संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल नागरिकों को उनके नाम पर जारी किए गए कनेक्शनों की पहचान करने, धोखाधड़ी वाले पंजीकरण की रिपोर्ट करने, खोए हुए स्टेशनों का पता लगाने या ब्लॉक करने के लिए चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने की अनुमति देकर सशक्त बनाता है।

7 राष्ट्रपति मुर्मू ने मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि दी

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस शुभ दिन पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई महिलाओं की भूमिका को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने दो बहुत ही खास महिलाओं मातंगिनी हाजरा और कनकलता

बरुआ का उल्लेख किया।

मातंगिनी हाजरा:

- उनका जन्म 1869 में पश्चिम बंगाल के तामलुक के पास एक गांव में हुआ था। उनकी कम उम्र में शादी होने तथा मात्र 18 साल की उम्र में विधवा होना दुर्भाग्यपूर्ण था। तत्पश्चात इन्होंने खुद को सामाजिक कारणों के लिए समर्पित कर दिया।
- राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आदर्शों की प्रशंसा करने के लिए इन्हें 'बूढ़ी गांधी' का उपनाम दिया गया।
- हाजरा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा दांडी मार्च आदि जैसे कई विरोध प्रदर्शनों में योगदान दिया।
- 73 वर्ष की आयु के दौरान उन्होंने तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर लगभग 6,000 प्रदर्शनकारियों के एक जुलूस का नेतृत्व किया, जहां ब्रिटिश अधिकारियों के साथ संघर्ष के दौरान गोली मार दी गई और वह भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हो गई।
- उन्हें स्वतंत्रता के एक भावुक समर्थक के रूप में वर्णित किया गया है और देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 1977 में कोलकाता मैदान में एक महिला क्रांतिकारी की पहली प्रतिमा का नाम उनके नाम पर रखा गया।
- मातंगिनी हाजरा एक विनम्र पृष्ठभूमि से उन महिला योद्धाओं में से एक थीं जिन्होंने नागरिकों के दिल और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है।

कनकलता बरुआ:

- साहस की प्रतीक कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन की एक युवा शहीद थीं।
- 17 साल की उम्र में उन्होंने 20 सितंबर 1942 को असम के गोहपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगे को फहराने के प्रयास में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया।
- पुलिस के साथ टकराव में, बरुआ ने झंडे को छोड़ने से इंकार कर दिया जिससे पुलिस द्वारा गोली चला दी गई।
- इनके वीर बलिदान ने उस समय के दौरान कई लोगों को प्रेरित किया जब स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही थी।
- 2020 में तटरक्षक बल द्वारा इनकी बहादुरी के लिए इनके नाम पर एक फास्ट पेट्रोल वेसल 'आईसीजीएस कनकलता बरुआ' का नाम दिया गया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का महत्त्व:

- **मणिकर्णिका तांबे**- झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने व्यपगत के सिद्धांत के तहत झांसी के विलय का विरोध किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ झांसी और ग्वालियर में लड़ाई लड़ी जहां इनकी मृत्यु हो गई।
- **अरुणा आसफ अली**- भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा पर वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ ने गोवलिया टैंक मैदान (बॉम्बे) में तिरंगा फहराया।
- **बेगम सफिया अब्दुल वाजिद**- भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकारी व्याख्याता की नौकरी खो दी।

आगे की राह:

इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। अपने स्वयं के राजनीतिक संघ का गठन करके समाचार पत्रों की स्थापना की और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भाग लिया।

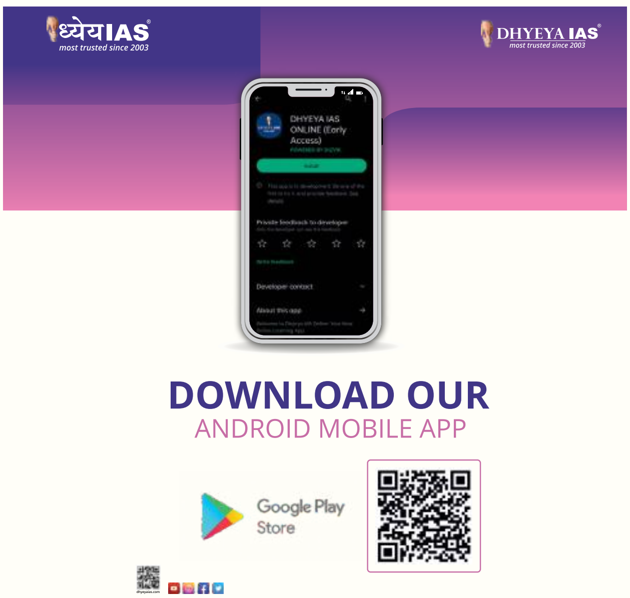

मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न

1. डिजिटल प्रौद्योगिकियां दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में जीवन, समाज और व्यवसायों के स्वरूप को बदल रही हैं। इस संदर्भ में डिजिटल स्वास्थ्य की वर्तमान में प्रासंगिकता तथा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
2. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को निर्णायक बनाती है। भारत-श्रीलंका संबंध के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
3. स्वयं सहायता समूह क्या है? महिला सशक्तीकरण में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें।
4. समय-समय पर पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानून की समीक्षा एक गतिशील लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आईपीसी व सीआरपीसी कानून में संशोधन का औचित्य सिद्ध कीजिए।
5. हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'हैंडबुक ऑन कांबेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका न्यायिक प्रणाली और कानूनी समुदाय के भीतर मौजूद गहरी अंतर्निहित लैंगिक रूढ़ियों को मिटाने में किस प्रकार भूमिका निभाएगी?
6. पृथ्वी पर नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्रोत के रूप में जल विद्युत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
7. आंतरिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की बदलती प्रकृति को देखते हुए भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता तथा प्रयासों का परीक्षण कीजिए।
8. बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति के बीच अनिवार्य संबंध हैं। भारत में हाल ही में सीएसडीएस सर्वेक्षण के संदर्भ में युवा बेरोजगारी से जुड़ी चिताओं और बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
9. आर्थिक महत्त्व के साथ-साथ आसियान और भारत के अपने हिंद प्रशांत रणनीति को लागू करना और चीन के प्रभाव को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। इस कथन के आलोक में भारत आसियान संबंधों की विवेचना कीजिए।
10. यूरिया गोल्ड क्या है? इसकी विशेषताएं तथा यूरिया के अधिक उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।
11. स्पंज सिटी क्या है? यहां शहरी बाढ़ की समस्या के समाधान में किस प्रकार प्रभावी होगी? स्पष्ट करें।
12. उद्गम पोर्टल (UDGAM Portal) क्या है? इसकी कार्यप्रणाली तथा लाभों का विस्तृत उल्लेख करें।
13. उत्तरी सागर मार्ग के संबंध में भारत के लिए आर्कटिक क्षेत्र में संभावनाओं और संभावित खतरों का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
14. भारत का आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कथन के आलोक में आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य तथा महत्त्व पर प्रकाश डालें।
15. परिवहन का परिचालन भारतीय लॉजिस्टिक उद्योग क्षेत्र के लिए एक परिवर्तन कार्यक्रम होगा। RSR परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए भारत के संदर्भ में इसके महत्त्व की विवेचना करें।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

ग्राफीन-अरोड़ा कार्यक्रम

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा केरल के मेकर विलेज कोच्चि में 'ग्राफीन-अरोड़ा कार्यक्रम' को लॉन्च किया गया है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:

- यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, केरल सरकार और उद्योग भागीदारों के संयुक्त वित्त पोषण के साथ 94.85 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया है।
- इसके अन्तर्गत विकसित स्टार्टअप उत्पादों के साथ-साथ, कोच्चि के मेकर्स विलेज में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन (IICG) जैसे अनुसंधान तथा विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के व्यावसायीकरण पर विचार किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम स्टार्टअप एवं उद्योग को पूरी सुविधा प्रदान करके अनुसंधान तथा विकास के व्यावसायीकरण के बीच संबंध स्थापित करेगा।
- यह उभरती ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा जो बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए विकसित ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण हेतु एसएमई तथा स्टार्टअप का मार्गदर्शन, विकास, कार्यान्वयन और समर्थन कर सकता है।

चुराचांदपुर से आइजोल एवं कांगपोकपी से दीमापुर तक हेलीकॉप्टर मार्गों को मंजूरी

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मिजोरम के चुराचांदपुर से आइजोल और दूसरा नागालैंड के कांगपोकपी से दीमापुर तक हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए दो अंतर-राज्य मार्गों को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- यह मंजूरी इसलिए दी गयी क्योंकि इंफाल घाटी में हुई हिंसा से वहाँ बसे कुकी-जोमी लोगों को उनके पहाड़ी जिलों में वापस भेज दिया, जबकि मैतेई लोगों को घाटी क्षेत्र में वापस भेज दिया क्योंकि एक समुदाय दूसरे समुदाय की हिंसा के डर से राज्य के भीतर यात्रा करने के लिए सड़कों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे।
- इस योजना में यात्रा के लिए 2,000 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि राज्य और केंद्र सरकारें सब्सिडी के रूप में शेष राशि वहन करेंगी। नए मार्गों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त उड़ानों हेतु सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत 75% हेलीकॉप्टर सब्सिडी एवं प्रति वर्ष 750 उड़ान घंटों की सीमा है, परन्तु राज्य सरकार इस सीमा को बढ़ाने के लिए नए प्रस्ताव भी बना सकती है।

कच्चे तेल एवं डीजल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया

हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला अप्रत्याशित कर 4,250 रूपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,100 रूपये प्रति टन कर दिया गया है।

मुख्य बातें:

- इसमें डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) 1 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। जेट ईंधन के निर्यात पर 2 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा।
- नए कर से पहले पेट्रोल और जेट ईंधन पर 6 रूपये प्रति लीटर ($12 प्रति बैरल) तथा डीजल पर 13 रूपये प्रति लीटर ($26 प्रति बैरल) का निर्यात शुल्क लगाया जाता था।
- तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रूपये प्रति टन ($40 प्रति बैरल) विंडफॉल लाभ कर भी लगाया गया।
- यदि वैश्विक दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ जाती हैं तो घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है परन्तु उत्पाद में कमी 20 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ जाती है तो डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात पर लेवी (levy) लगायी जाती है।

सांप की एक नई प्रजाति का नाम हैरिसन फोर्ड के नाम पर रखा गया

हाल ही में जर्मन सोसाइटी फॉर हर्पेटोलॉजी एंड हर्पेटोकल्चर (DGHT) द्वारा 'टैचीमेनोइड्स हैरिसनफोर्डी' का नाम पर्यावरण हितैशी हॉलीवुड अभिनेता हैरिसन फोर्ड के नाम पर रखा गया। यह जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई सांप की एक प्रजाति है।

मुख्य विशेषताएँ:

- सांप की यह प्रजाति पीले, भूरे रंग की है जिसके ऊपर बिखरे हुए काले धब्बे होते है इसकी लंबाई 16 इंच (40.6 सेंटीमीटर) है और तांबे के रंग की आंख पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा है।
- सांप की इस प्रजाति को दक्षिण अमेरिका के पेरू में एविरेरी-व्रेम बायोस्फीयर रिजर्व के ओटिशी नेशनल पार्क (ONP) में खोजा गया था।
- इससे पहले एक चींटी (फीडोले हैरिसनफोर्डी) और एक मकड़ी (कैलपोनिया हैरिसनफोर्डी) का नाम इनके नाम पर रखा गया था। हालाँकि इनके नाम पर रखा जाने वाला यह पहला सरीसृप है।

मिलाशा जोसेफ

केरल राज्य के अलाप्पुझा के मारारीकुलम की रहने वाली युवती मिलाशा जोसेफ सात ज्वालामुखी शिखर (सात महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी) पर चढ़ने के महत्त्वाकांक्षी मिशन पर है। इन्होंने 21 महीनों में तीन पहाड़ों किलिमंजारो, दमावंद और एल्ब्रस पर चढ़ाई की है।

जोसेफ से सम्बंधित मुख्य बातें:

- इन्होंने नवंबर 2021 और जून 2022 में क्रमशः तंजानिया के माउंट किलिमंजारो (5,895 मीटर) और ईरान के माउंट दमावंद (5,671 मीटर) पर चढ़ाई की। वह अगस्त, 2023 में रूस के माउंट एल्ब्रस (5,642 मीटर) के शिखर पर पहुंची है।
- जिन तीन पहाड़ों पर इन्होंने चढ़ाई किया, उनमें से माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रस क्रमशः अफ्रीका व यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और सेवन समिट्स (सात महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पहाड़) का एक हिस्सा हैं।
- अर्जेंटीना तथा चिली सीमा पर ओजोस डेल सालाडो, मैक्सिको में पिको डी ओरिजाबा, पापुआ न्यू गिनी में माउंट गिलुवे और अंटार्कटिका में माउंट सिडली पर चढ़ाई करना इनके मिशन का हिस्सा है।

पूर्व डीआरडीओ प्रमुख वीएस अरुणाचलम का निधन

हाल ही में रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के पूर्व अध्यक्ष वीएस अरुणाचलम का संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

अरुणाचलम के बारे में:

- पद्म विभूषण से सम्मानित अरुणाचलम एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम (IMDP) जैसे अनेक रणनीतिक कार्यक्रमों के मुख्य वास्तुकार थे जिसमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग, हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' तथा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है।
- इन्होंने बेंगलुरु में एक थिंक टैंक 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP)' की स्थापना की थी।
- 2015 में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें DRDO के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
- इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (1980), पद्म भूषण (1985) और पद्म विभूषण (1990) से भी सम्मानित किया गया।
- इनके द्वारा तीन प्रमुख कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए जिनमें एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) के तहत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम, उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (एटीवी) कार्यक्रम तथा रणनीतिक और सामरिक निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने के लिए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) भी शामिल है।

एमसीए बार्ज एलएसएएम 8 (यार्ड 76) लॉन्च

हाल ही में रक्षा मंत्रालय के युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक द्वारा गुट्टेनादेवी, पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) से दूसरा मिसाइल सह गोला बारूद (एमसीए) बार्ज, यार्ड 76 (एलएसएएम 8) युद्धपोत को लॉन्च किया गया।

एमसीए बार्ज, यार्ड 76 के बारे में:

- यह स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरण प्रणालियों के साथ, रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल का गौरवशाली ध्वजवाहक है।
- भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अंतर्गत 08 एक्स एमसीए बार्ज के निर्माण के लिए एमएसएमई, मेसर्स SECON इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम के साथ यह संपन्न लांच किया गया।
- यह एमसीए बार्ज की उपलब्धता जेट्टी और बाहरी बंदरगाह दोनों पर आईएन (Indian Navy) जहाजों के लिए गोला-बारूद के परिवहन,

आरोहण तथा उतरने की सुविधा प्रदान करके आईएन की परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति प्रदान करेगी।

उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल के तहत मार्गों का विस्तृत मूल्यांकन शुरू करेगा जिसे उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना के रूप में जाना जाता है जो कम सेवा वाले या गैर-सेवा वाले गंतव्यों हेतु उड़ान सब्सिडी प्रदान करता है।

योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:

- आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना के तहत 260 उड़ानें चालू हैं तथा चरण 1 से चरण 4 तक इसके अंतर्गत 1,154 मार्गों में से एयरलाइंस ने केवल 475 मार्गों पर ही उड़ानें शुरू की हैं।
- इस योजना के शुरूआत में फिक्स्ड-विंग विमान से 500 किलोमीटर की दूरी एक घंटे एवं हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा पर आधी सीटों का किराया 2,500 रुपये तय किया गया था जिसमें विभिन्न दूरी के मार्गों के लिए आनुपातिक मूल्य निर्धारण भी शामिल था।
- उड़ान के तहत क्षेत्रीय मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या वित्त वर्ष 2018 में लगभग 263,000 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 2.5 मिलियन पहुँच गयी।

दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गयी।

मुख्य विशेषताएँ:

- इस हवाई अड्डे का विकास लगभग 50 करोड़ की लागत से किया जा रहा है जिसके फरवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- इसके विकास के लिए 1810 मीटर रनवे का नवीनीकरण और एक एप्रन (Apron) का निर्माण शामिल है जिसमें दो उन्नीस सीटों वाले विमान 750 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन और एक एटीसी टॉवर भी शामिल है।
- इसके टर्मिनल भवन में पीक आवर्स (Peak Hours) के दौरान 100 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी।
- इसके शुरू होते ही खजुराहो और भोपाल को जोड़ने वाली उड़ानें संचालित की जाएंगी। इन मार्गों को पहले ही आरसीएस उड़ान के तहत सम्मानित किया जा चुका है।
- दतिया हवाई अड्डे के विकास से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को गति मिलेगी।

अभ्यास मालाबार-23

हाल ही में मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना (आईएन), रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (आरएएन), जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) और अमेरिकी नौसेना (यूएसएन) के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की भागीदारी की।

अभ्यास मालाबार-23 के बारे में:

- मालाबार 23 अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया जिसमें बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण शामिल था।
- भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस कोलकाता, फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री और पी8आई समुद्री गश्ती विमान द्वारा किया गया था।
- मालाबार के समुद्री चरण में हवा, सतह और समुद्र के नीचे जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास, हथियार फायरिंग तथा क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया था।

परवनार नदी मार्ग का स्थायी परिवर्तन

हाल ही में नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLCIL) ने परवनार नदी मार्ग परिवर्तन परियोजना पूरी कर ली जिससे इस क्षेत्र में बाढ़ से बचाव और कृषि समृद्धि प्रदान होगी। यह नदी खदान-2 के कटान क्षेत्र के आस-पास अपने अस्थायी संरेखण (Alignment) के कारण रास्ते में आने वाले गांवों और कृषि भूमि के लिए खतरा उत्पन्न करती थी।

मुख्य विशेषताएँ:

- इस परियोजना के पूरा होने से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है तथा कृषि क्षमता को बढ़ावा मिलेगा जो स्थानीय किसानों को सिंचाई का एक साधन प्रदान करेगा।
- परवनार नदी में पानी का निरंतर प्रवाह भूजल को समृद्धि प्रदान करेगा, साथ ही इस क्षेत्र के भविष्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण और टिकाऊ संसाधन प्रदान करेगा।
- समुदायों और कृषि संसाधनों की सुरक्षा के महत्त्व को देखते हुए इस नदी का कुल 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए स्थायी डायवर्जन अनुमानित क्षेत्र 18 हेक्टेयर है।

SVAMITVA योजना को ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व (ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई-गवर्नेंस 2023 (गोल्ड) के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

SVAMITVA योजना के बारे में:

- स्वामित्व योजना नवीनतम ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके गांव-आबादी वाले क्षेत्र में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व प्रदान करती है।
- यह योजना बैंक ऋण और अन्य वित्तीय लाभों के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती हैं जो 5 सेमी सटीकता मानचित्रों की तैयारी के माध्यम से भूमि से संबंधित विवादों के निपटारे में मदद भी करती हैं।
- इस योजना को भारतीय सर्वेक्षण विभाग, प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन भागीदार, राजस्व और पंचायती राज विभाग तथा एनआईसी-जीआईएस के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जाता है।

मेरा बिल मेरा अधिकार

हाल ही में भारत सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से सभी खरीद के लिए चालान या बिल मांगने वाले ग्राहकों के संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नाम से एक 'चालान प्रोत्साहन योजना' सितंबर 2023 से शुरू हुई। इसका उद्देश्य आम जनता में 'बिल मांगो' को उनके अधिकार के रूप में सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना।

योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:

- इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में शुरू किया गया।
- भारत के सभी निवासी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे, परन्तु लकी ड्रा के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 चालान ही इस वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।
- जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं (असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत) द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बी2सी चालान इस योजना के लिए पात्र हैं।

आर.बी.आई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गयी है। तीन केंद्रीय बैंक गवर्नरों में एक को दी गई है, जिसमें दास शीर्ष पर हैं। अन्य दो गवर्नरों में स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुयेन थी होंग भी शामिल हैं।
- ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 1994 से हर साल केंद्रीय बैंकरों को रेटिंग देता है।
- यह रिपोर्ट 101 प्रमुख देशों को शामिल करती है, जिसमें ईयू, ईस्टर्न कैरिबियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स शामिल हैं।
- ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को A से F तक रेटिंग देती है।
- महंगाई नियंत्रण, अर्थव्यवस्था विकास लक्ष्य, करेंसी स्टैबिलिटी और ब्याज दर प्रबंधन के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है।
- A ग्रेड उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जबकि F ग्रेड असफलता के लिए दिया जाता है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाले स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण गोवा तट पर करीब 20 हजार फुट की ऊंचाई पर किया।
2. कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
3. महान गणितज्ञ और सांख्यिकी प्रोफेसर कल्यम्पुडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया जिन्हें सीआर राव के नाम से भी जाना जाता था।
4. ई-गवर्नेंस में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए 8 स्वर्ण और 8 रजत पुरस्कारों सहित कुल 16 पुरस्कार दिये गए।
5. केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलने की घोषणा की है जिसे अब 'अस्मिता महिला लीग' के नाम से जाना जाएगा।
6. राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्माकुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16 वीं पुण्य तिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की 'माई स्टैम्प' पहल के अंतर्गत जारी किया गया।
7. ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोलू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी।
8. केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ने एएआई हवाई अड्डों के टर्मिनल बिल्डिंग आर्किटेक्चर पर पुस्तक का विमोचन किया।
9. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) ने रोजगार महानिदेशक (DGE) के सहयोग से एनआईईएलआईटी रोजगार मेला 2023 युवा रोजगार मंच, सशक्त युवा तथा सशक्त राष्ट्र का आयोजन किया।
10. आरईसी पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन को ऋण प्रदान करेगा।
11. वन वीक वन लैब अभियान के तहत कोलकाता स्थित सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (CGCRI) ने एक स्कूल संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
12. मिस्र के काहिरा एयर बेस में आयोजित एक्सरसाइज ब्राइट स्टार-23 में भारतीय वायु सेना ने भाग लिया। भारतीय वायु सेना इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार-23 आयोजन में पहली बार भाग ले रही है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायु सेना की टुकड़ियों ने प्रतिभाग किया।
13. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गाँधीनगर (गुजरात) में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। क्षेत्रीय परिषदें बुनियादी ढांचे, खनन, जल आपूर्ति, पर्यावरण और वन तथा राज्य-पुनर्गठन से सम्बंधित व्यापक मुद्दों के साथ-साथ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), दूर संचार व इन्टरनेट के व्यापक विस्तार तथा क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित आदि पर चर्चा करती हैं।
14. भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में पांचवीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित हुई। इस वार्ता में दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के बीच संबंधों की भावी रूपरेखा तैयार करने में इसके महत्त्व पर प्रकाश डाला।
15. नगर राजभाषा कार्यावयन समिति (नराकास) ने छमाही बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में नगर राजभाषा कार्यावयन समिति (नराकास) दिल्ली उपक्रम-2, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संयुक्त 'राजभाषा उत्सव' के आयोजन के लिए सेकी कार्यालय को वर्ष 2022-23 के 'शील्ड पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
16. बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में गोल्डेन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने।
17. चन्द्रमा की सतह पर वह स्थान जहाँ पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान उतरे थे, उस का नाम 'शिव शक्ति' बिन्दु रखा जायेगा तथा जहाँ चन्द्रयान-2 का लैंडर क्रैश हुआ था उसे तिरंगा बिन्दु के नाम से जाना जायेगा।
18. भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (इंडो-पैसिफिक) गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में प्रभारी डी' एफेयर (d' affairs) के पद पर नियुक्त किया है।

आदित्य-एल1 मिशन

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2 सितंबर, 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना सौर मिशन, आदित्य L1 लॉन्च किया।

आदित्य एल1 मिशन के बारे में

- आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने, सौर गतिविधियों और वास्तविक समय में अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित मिशन है।
- अंतरिक्ष यान को, 125 दिनों में पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी की यात्रा करने के बाद, लैग्रेन्जियन बिंदु L1 के पास एक हेलो कक्षा में स्थापित किये जाने की आशा है जिसे सूर्य के सबसे करीब स्थान माना जाता है।
- यह विद्युत चुम्बकीय, कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों (कोरोना) का निरीक्षण करने के लिए सात पेलोड का प्रयोग करेगा।
- 7 पेलोड:
  - दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC)
  - सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT)
  - सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS)
  - उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS)
  - आदित्य सौर पवन कण प्रयोग (ASPEX)
  - आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज (PAPA)
  - उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च-रिजॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर
- इनमें से 4 पेलोड सूर्य की रिमोट सेंसिंग करेंगे जबकि 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन-सीटू अध्ययन करेंगे।

आगे की राह

- चंद्रयान-3 की हालिया सफलता ने भारत को अंतरिक्ष जगत में एक प्रमुख स्थान दिलाया है।
- आदित्य एल1 मिशन, सफल सूर्य मिशन वाले कुछ देशों में भारत की स्थिति को और बेहतर करने की क्षमता रखता है।
- इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष वातावरण, इसके प्रभावों को समझने और दुनिया इन परिवर्तनों को बेहतर ढंग से कैसे अपना सकती है, इस मामले में प्रमुख योगदान दे सकता है।

दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (वीईएलसी)

- यह सबसे बड़े और प्राथमिक पेलोड में से एक है जो आदित्य एल1 मिशन पर जायेगा।
- यह कोरोनोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, पोलारिमेट्री मॉड्यूल और डिटेक्टरों की मदद से स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक साथ इमेजिंग और स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्री करने में सक्षम है।
- यह कोरोना के तापमान, वेग और घनत्व, कोरोना को गर्म करने वाली प्रक्रियाओं और सौर हवाओं के त्वरण का अध्ययन करेगा।

सूर्य का अध्ययन करने का महत्व

- पृथ्वी या सौर मंडल के बाहर के एक्सोप्लैनेट का विकास, मूल तारे द्वारा नियंत्रित होता है।
- पृथ्वी की मौसम प्रणालियाँ भी सौर मौसम और पर्यावरण से प्रभावित होती हैं और इसलिए सौर गतिविधियों को समझना आवश्यक है।

आदित्य एल1

- उपग्रह को लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
- L1 पृथ्वी-सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल में पांच बिंदुओं में से एक है, जहां दो-पिंड प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्रों का निर्माण करते हैं।
- इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने और बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य के संपर्क में रहने हेतु आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है।
- L1 बिंदु पर नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की संयुक्त परियोजना, सौर और हेलिओस्फेरिक वेधशाला उपग्रह (SOHO) भी उपस्थित है।

ब्रिक्स का विस्तार

चर्चा में क्यों?

15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त, 2023 तक सैंडटन कन्वेंशन सेंटर, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह 2019 और COVID-19 महामारी के बाद और 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पहला इन-पर्सन शिखर सम्मेलन है।
- **थीम:** 'ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी'
- शिखर सम्मेलन में छह नए देशों को सदस्यता देकर समूह के विस्तार की घोषणा की गयी।

ब्रिक्स और नए सदस्य देश

- शिखर सम्मेलन में ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना और इथियोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की गई, उनकी सदस्यता 1 जनवरी, 2024 से शुरू होगी।
- ब्रिक्स वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और दुनिया की जीडीपी के एक चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- इन देशों को शामिल करने से ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा।

आगे की राह

- वैश्विक समूहों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ब्रिक्स का विकास वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है।
- हालांकि सदस्यों का तेजी से विस्तार ब्रिक्स समूह के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है, खासकर अगर चीन को समूह में एक प्रमुख स्थान लेने के रूप में देखा जाता है।
- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मंच के रूप में, पश्चिम-विरोधी बयानों के मंच के रूप में अपना आंतरिक मूल्य न खो दे।

चीनी परिप्रेक्ष्य

- चीन विस्तार को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर समूह के विस्तार को आगे बढ़ा रहा है और उन देशों को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है जो पश्चिमी देशों के विरुद्ध संशय का भाव रखते हैं।
- चीन-रूस की मजबूत छाप का उदाहरण ईरान को निमंत्रण में देखा जा सकता है, जिसके पश्चिम के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं।
- चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है और उसने हाल ही में तेहरान और रियाद के बीच शांति समझौता कराया है।

प्रमुख कमियाँ

- ब्रिक्स देश अभी भी उद्देश्य की सुसंगतता प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं, और अभी भी आंतरिक विरोधाभास उपस्थित हैं।
- भारत-चीन संघर्ष ने समूह के उद्देश्य को कई मायनों में बाधित किया है।
- ईरान और सऊदी अरब के जुड़ने से, हालांकि उन्होंने फिलहाल अपनी प्रतिद्वंद्विता कम करने का फैसला किया है, संगठन के कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं।
- ब्रिक्स द्वारा कोई भी खुला राजनीतिक, पश्चिम विरोधी रुख भारत और ऐसे अन्य सदस्यों को असहज कर देगा, जो वैश्विक शक्तियों के बीच सामंजस्य बनाकर चलते हैं।
- ब्रिक्स में नए देश, हालांकि कुछ क्षेत्रों में समृद्ध हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो रहे हैं। यह आर्थिक सहयोग के एजेंडे से समूह के विचलन को दर्शाता है।

चंद्रयान-3

चर्चा में क्यों?

23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत दक्षिणी चंद्र ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है।

आगे की राह

- यदि चंद्रयान-3 इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर पाता है, तो इसरो के अग्रणी कार्य के आधार पर भविष्य के अंतरिक्ष यात्री, इन क्षेत्रों से नमूने एकत्र करने में सक्षम होंगे।
- इसका डीप अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतत: व्यावसायिक गतिविधियों के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

- चंद्रमा के कम सघन एवं हलके वातावरण के कारण घर्षण कम होता है और अंतरिक्ष यान को धीमा करने के लिए प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- इस हेतु अंतरिक्ष यान को बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जो यान के भार को और बढ़ा देता हैं।
- लैंडिंग स्थान के संदर्भ में कोई सटीकता नहीं रहती और अंतरिक्ष यान को नेविगेशन हेतु कंप्यूटर गणना और निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

- चंद्रयान-3 का मून लैंडर जिस स्थान पर उतरा, उसे अब **'शिव शक्ति'** के नाम से जाना जाएगा।
- जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिह्न छोड़े थे उसे अब **'तिरंगा'**कहा जाएगा।
- 23 अगस्त को **राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस** के रूप में मनाया जाएगा।

चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का महत्व

- चंद्रमा पर अधिकांश लैंडिंग चंद्रमा के भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में हुई, क्योंकि पर्याप्त धूप और समतल जमीन के कारण यहां का भूभाग और वातावरण अनुकूल है।
- चीन का चांग-4, यद्यपि चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा, (अर्थात चंद्रमा का वह हिस्सा जो पृथ्वी के सामने नहीं है), फिर भी वह चंद्रमा के भूमध्यरेखीय क्षेत्र के पास था।
- ऊबड़-खाबड़ इलाके, बड़े गड्ढों की मौजूदगी और अत्यधिक तापमान के कारण चंद्र ध्रुवों को अन्वेषण हेतु कठिन माना जाता है।
- ऐसे सबूत मिले हैं (चंद्रयान-1 द्वारा), कि चंद्र ध्रुवों के इन क्षेत्रों के गहरे गड्ढों में बर्फ की मौजूदगी हो सकती है।
- समय के साथ जमे रहने के कारण, यह क्षेत्र प्रारंभिक सौर मंडल के लिए प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

सॉफ्ट लैंडिंग के चार चरण

- **रफ ब्रेकिंग चरण:** इसमें चंद्र सतह से 30 किमी की ऊंचाई पर लैंडर के क्षैतिज वेग को 1.68 किमी/सेकंड से घटाकर लगभग शून्य करना शामिल है।
- **एटीट्यूड होल्ड चरण:** यह सतह से 7.42 किमी की ऊंचाई पर शुरू होता है, जो लगभग 10 सेकंड तक चलता है। 3.48 किमी की दूरी तय करते समय लैंडर को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति की ओर झुकना होता है।
- **फाइन ब्रेकिंग चरण:** यह चरण लगभग 175 सेकंड का होता है। लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाता है और लैंडिंग स्थल पर अंतिम 28.52 किमी की दूरी तय कर चुका होता है। ऊंचाई घटकर 800-1,000 मीटर रह जाती हैं और लैंडर 0 मीटर/सेकेंड की नाममात्र गति तक पहुंच जाता है।
- **टर्मिनल डीसेंट:** यह अंतिम चरण है, इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यान को सतह पर पूरी तरह से लंबवत उतरना होता है।
- चंद्रयान -2 एटीट्यूड होल्ड चरण और फाइन ब्रेकिंग चरण के बीच विफल हुआ था।

वैश्विक जल संकट

चर्चा में क्यों?

वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (डब्ल्यूआरआई) ने एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस प्रकाशित किया है। इससे अनुसार दुनिया की लगभग 25% आबादी वाले लगभग 25 देशों को हर साल गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता है।

लागत प्रभावी समाधान और सहयोगात्मक प्रयास

- डब्ल्यूआरआई शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैश्विक जल चुनौतियों से निपटना लागत प्रभावी है, जिसके लिए 2015 से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% या प्रति व्यक्ति प्रति दिन 29 सेंट की आवश्यकता होगी।
- सरकारों, समुदायों और व्यवसायों को आसन्न संकट को कम करने और स्थायी वैश्विक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल-सुरक्षित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।

वैश्विक जीडीपी पर आर्थिक प्रभाव

- एक्वेडक्ट के डेटा के अनुसार, 2050 तक उच्च जल संकट का आर्थिक प्रभाव 31% वैश्विक जीडीपी (लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर) पर हो सकता है, जबकि 2010 में यह 24% वैश्विक जीडीपी (करीब $15 ट्रिलियन) का हिस्सा था।
- चार देशों, भारत, मैक्सिको, मिस्र और तुर्की का इस प्रभावित सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक का योगदान होने का अनुमान है।

व्यापक वैश्विक जल तनाव:

- वैश्विक स्तर पर, दुनिया की कम से कम 50% आबादी, लगभग चार अरब लोग, हर साल कम से कम एक महीने के लिए अत्यधिक जल कमी की स्थिति का अनुभव करते हैं।
- अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2050 तक, यह संख्या वैश्विक आबादी का लगभग 60% तक बढ़ सकती है।
- जल की कमी तब उत्पन्न होती है जब पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है या जब पानी की गुणवत्ता के कारण इसके उपयोग में बाधा आती है।

अत्यधिक तनावग्रस्त क्षेत्र और देश

- 25 सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में बहरीन, साइप्रस, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, मिस्र, लीबिया, यमन, बोत्सवाना, ईरान, जॉर्डन, चिली, सैन मैरिनो, बेल्जियम, ग्रीस ट्यूनीशिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इराक, भारत और सीरिया शामिल हैं।
- सबसे गंभीर जल संकट पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में देखा जाता है, जहां क्रमशः 83%, 83% और 74% आबादी अत्यधिक जल संकट का सामना करती है।

चुनौतियाँ और राजनीतिक निहितार्थ

- पानी की बढ़ती मांग और कम पूर्वानुमानित जलापूर्ति मिलकर, 2050 तक पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के 100% हिस्से को अत्यधिक जल कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- यह मुद्दा व्यक्तिगत उपभोग और उद्योगों से परे राजनीतिक स्थिरता तक फैला हुआ है, जो इसके महत्व को प्रकट करता है।

उप-सहारा अफ्रीका में पानी की बढ़ती मांग

- 2050 तक पानी की मांग में सबसे बड़ा बदलाव उप-सहारा अफ्रीका में अनुमानित है, जिसमें 163% की वृद्धि का अनुमान है, जो मुख्य रूप से सिंचाई और घरेलू जल उपयोग के कारण होगा।

विकास और सततता का संतुलन

जबकि पानी का बढ़ा हुआ उपयोग आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दे सकता है, इसके साथ ही अकुशल जल उपयोग और असतत प्रबंधन प्रथाओं के कारण क्षेत्र की जीडीपी 6% तक कम होने का जोखिम भी है।

जीई-सरसों

चर्चा में क्यों?

भारतीय वैज्ञानिकों ने कम तीक्ष्णता वाली सरसों की किस्म विकसित की है जो कीट और रोग प्रतिरोधी भी है।

अनुसंधान संस्थान

यह शोध जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (एनआईपीजीआर) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।

जीई-सरसों की फसल के बारे में

- वैज्ञानिकों ने अधिक उपज देने वाली भारतीय सरसों की किस्म 'वरुणा' में 12 में से 10 जीटीआर जीनों को ष्संपादितष किया है।
- इसके लिए, उन्होंने CRISPR/Cas9- एक जीन-संपादन प्रणाली का उपयोग किया है, जो एक एंजाइम को प्रतिरोपित करता है, जो जीन के सटीक लक्षित स्थानों पर डीएनए में संशोधन के लिए 'आणविक कैंची' के रूप में कार्य करता है। इसके बाद प्राकृतिक रूप से डीएनए मरम्मत प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
- आनुवंशिक संशोधन एन्कोडेड प्रोटीन (जो बीजों तक ग्लूकोसाइनोलेट्स के परिवहन के लिए जिम्मेदार थे) को निष्क्रिय बना देता है।

जीई-सरसों फसल की आवश्यकता

- पारंपरिक सरसों में ग्लूकोसाइनोलेट्स का स्तर उच्च होता है जिसके परिणामस्वरूप तेल और भोजन में तीखापन आ जाता है।
- **ग्लूकोसाइनलेट्स-** सल्फर और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का समूह है।
- रेपसीड भोजन (बीजों के अवशेष) मुर्गी और सूअरों के लिए अरुचिकर होता है।
- ग्लूकोसाइनोलेट्स पशुओं में गण्डमाला (गर्दन की सूजन) और आंतरिक अंग असामान्यताओं का कारण भी बनते हैं।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जीएम हाइब्रिड सरसों और नई जीई कम बीज वाली उच्च पत्ती वाली ग्लूकोसाइनोलेट श्रृंखला की प्रमुख पादप हैं जिससे आयातित वनस्पति तेलों पर निर्भरता कम की जा सकती है।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए आईएसओपीओएम (तिलहन, दलहन, ऑयलपाम और मक्का की एकीकृत योजना), तिलहन उत्पादन पर राष्ट्रीय मिशन और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जैसी सरकारी पहल को अपनाया जाना चाहिए।

जीएम-सरसों का उत्पादन क्यों नहीं?

- जीएम सरसों की फसल डीएमएच-11 स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह भारतीय किस्म वरुणा और पूर्वी यूरोपीय 'अर्ली हीरा- 2' सरसों की आनुवंशिक रूप से संशोधित संकर नस्ल है।
- जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है क्योंकि इससे विभिन्न जैव सुरक्षा खतरे और कीटनाशक और शाकनाशी प्रतिरोध बढ़ने की संभावना है।

तिलहन उत्पादन से जुड़ी चुनौतियाँ

- भारत अपनी 60% खाद्य तेल की खपत की मांग आयात के माध्यम से पूरी करता है।
- तिलहन की खेती की उत्पादकता भी कम है।
- खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% वर्षा आधारित खेती पर आश्रित है।
- उत्पादित तीखी सरसों उपभोग और चारे के लिए बहुत आकर्षक नहीं है।

फुकुशिमा का अपशिष्ट जल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जापान ने नष्ट हुए फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से एक मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उपचारित रेडियोधर्मी जल पंप करना शुरू कर दिया है।

फुकुशिमा आपदा के बारे में

- 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद, फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कई रिएक्टर पिघल गए।
- आगे की आपदा को रोकने के लिए, वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों ने रिएक्टरों में जल भर दिया और वह जल जल्दी ही अत्यधिक दूषित हो गया।

जापान की योजना

- टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर आइसोटोप को हटाने के लिए दूषित जल को फिल्टर कर रहा है, जिससे केवल ट्रिटियम बच रहा है, जो हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसे अलग करना मुश्किल है।
- जल को समुद्र में पंप करने से पहले तब तक डाइलुट किया जाएगा जब तक कि ट्रिटियम का स्तर नियामक सीमा से नीचे न आ जाए।
- उपचारित जल में प्रति लीटर लगभग 190 बेकरेल ट्रिटियम होगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की पीने के जल की सीमा 10,000 बेकरेल प्रति लीटर से कम है।
- बेकरेल रेडियोधर्मिता की एक इकाई है।
- संयंत्र को बंद करने की योजना के साथ-साथ जल निपटान को पूरा होने में दशकों लगेंगे।
- शुरुआत में जल छोटे भागों में और अतिरिक्त जांच के साथ छोड़ा जाएगा।

आगे की राह

- दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने लोगों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 60 वर्षों से अधिक समय से नियमित रूप से ट्रिटियम युक्त जल छोड़ा है।
- ट्रिटियम को अपेक्षाकृत हानिरहित माना जाता है क्योंकि इसका विकिरण मानव त्वचा में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ऊर्जावान नहीं है।
- जापान संयंत्र के पास के जल में मछलियों का परीक्षण भी करेगा और परीक्षण के परिणाम कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

IAEA की स्वीकृति

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की सुरक्षा समीक्षा के अनुसार फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन में संग्रहीत उपचारित जल को समुद्र में छोड़ने की जापान की योजना आईएईए सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
- इसमें आगे कहा गया है कि उपचारित जल के निर्वहन से लोगों और पर्यावरण पर नगण्य रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा।

चिंताएँ

- ग्रीनपीस ने कहा कि जल के साथ निकलने वाले ट्रिटियम, कार्बन-14, स्ट्रोंटियम-90 और आयोडीन-129 के रेडियोलॉजिकल और जैविक प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया गया है।
- फुकुशिमा में मछली पकड़ने वाले संघों ने वर्षों से सरकार को जल न छोड़ने का आग्रह किया है, उनका तर्क है कि इससे मत्स्य पालन क्षेत्र प्रभावित होगा।
- चीन ने जापान की योजना को गैरजिम्मेदार, अलोकप्रिय और एकतरफा बताया।
- चीन ने जापानी समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया और चीन को निर्यात किए जाने वाले जापान के खाद्य और कृषि उत्पादों में रेडियोधर्मी संदूषण की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की।

दिल्ली में जी20 शिखर

चर्चा में क्यों?

18वां जी20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

थीम

- भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय 'वसुधैव कुटुंबकम' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है।
- यह वाक्यांश संस्कृत के हितोपदेश से लिया गया है।

जी20 के बारे में

- जी20 या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- 19 देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- इसका गठन 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में 1999 में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था।
- इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है।
- जी20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- जी20 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्यों के बीच बदलती रहती है।
- प्रेसीडेंसी जी20 एजेंडा को एक साथ लाने, इसके कामकाज को व्यवस्थित करने और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए जिम्मेदार है।
- भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रपति पद पर रहेगा।
- भारत के बाद, ब्राजील 2024 में जी20 की अध्यक्षता संभालेगा, उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका।

घोषणा

दूसरे दिन, G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा, जो पूरे वर्ष विभिन्न मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह की बैठकों में चर्चा की गई प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करेगा।

अन्य कदम उठाए गए

- शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत, दिल्ली सरकार ने शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक निकायों को बंद रखने का आदेश दिया है।
- शनिवार और रविवार को काम करने वाले निजी कार्यालयों को बंद रखने के लिए कहा गया है।
- नई दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिष्ठान (दुकानों और बैंकों सहित) इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे।

शिखर सम्मेलन में 'ग्लोबल साउथ'

- भारत लगातार खुद को ष्ग्लोबल साउथ की आवाजष् के रूप में स्थापित कर रहा है और अपनी प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर रख रहा है।
- जनवरी में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मोदी ने कहा था
  - 'विश्व संकट की स्थिति में है' और इस बात पर जोर दिया था कि 'आपकी आवाज भारत की आवाज है' और 'आपकी प्राथमिकताएँ भारत की प्राथमिकताएँ हैं।'
  - 'भारत ने हमेशा अपने विकासात्मक अनुभव को ग्लोबल साउथ के हमारे भाइयों के साथ साझा किया है।'
  - 'चूंकि भारत इस वर्ष अपनी G20 अध्यक्षता शुरू कर रहा है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है।'

केस स्टडी-01

हाल में आपको एक जिले के जिला विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया. उसके बाद आपने पाया कि आपके जिले के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है।

गाँव के बड़े महसूस करते हैं कि अनेक समस्याएँ पैदा हो गयी है क्योंकि लड़कियों को पढाया जा रहा है और वे घर के सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रख रही हैं. उनका विचार यह है कि लड़कियों कि न्यूनतम शिक्षा के साथ जल्द ही शादी कर दी जानी चाहिए. शिक्षा के बाद लड़कियां नौकरी लड़कियां नौकरी के लिए भी स्पर्धा कर रही है, जो परम्परा से लड़कों का अनन्य क्षेत्र रहा है, और पुरुषों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही है।

युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा और रोजगार तथा जीवन निर्वाह के अन्य साधनों के सामान अवसर प्राप्त होने चाहिए. समस्त इलाका वयोवृद्ध और युवाओं के बीच तथा उससे आगे दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुष के बीच विभाजित है. आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में या व्यस्त चौराहों पर भी, इस मुद्दे पर गरमागरम वाद विवाद हो रहा है। एक दिन आप को सुचना मिलती है कि अप्रिय घटना हुई है. कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी की गयी जब वे स्कूल के रस्ते में थी. इस घटना के फलस्वरूप कई सामाजिक समूह के बीच झगड़े हुए और कानून व्यवस्था कि समस्या पैदा हो गयी. गरमागरम वाद विवाद के बाद बड़े बूढोंने लड़कियों को स्कूल जाने कि अनुमति न देने और जो परिवार उनके हुकुम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे सभी परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय लिया है।

a. लड़कियों कि शिक्षा में व्यवधान डाले बिना, लड़कियों कि सुरक्षा को सुरक्षित करने क लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

b. पीढ़ियों के बीच संबंधों में समरसता सुनिचित करने के लिए आप गाँव के वयोवृद्ध कि पित्रसतात्मक अभिवृति का किस प्रकार प्रबंधन का और ढालने का कार्य करेंगे?

उत्तर (a) दिए गए मामला अध्ययन में मैं जिला विकास अधिकारी हूँ. मुझे कानून व्यवस्था बहाल करके लड़कियों के लिए शिक्षा का सामान अवसर सुनिश्चित करना है. इस मामले में लैंगिक समानता, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्रता एवं न्याय जैसे मूल्य निहित हैं।

- सर्वप्रथम में स्थानीय पुलिस थाने में छेड़खानी के दोषियों के विरुद्ध प्रथिमिकी दर्ज कराकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करूँगा. सामूहिक झगड़ों में शामिल विभिन्न समूह के लोगों को पुलिस कि सहायता से निरुद्ध करूँगा एवं जिला अधिकारी से अनुरोध कर के क्षेत्र में धरा 144 लगवाने का प्रयास करूँगा। इससे कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी।
- तत्पश्चात क्षेत्र के सभी महिला विद्यालयों से संपर्क कर के उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराएँगे।
- स्कूल के प्रारम्भ और अवकाश के समय सम्बंधित मार्गों में पुलिस कि गस्त बढ़ा देंगे।
- लड़कियों कि सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी करेंगे और शिकायत मिलने पर तत्काल सहायता सुनिचित करेंगे।
- लड़कियों को मुख्य मार्ग के प्रयोग एवं समूह में आने जाने के लिया प्रेरित करेंगे।
- महिला विद्यालय के प्रबंधन से संपर्क करके, महिला सिपाहियों कि सहायता से लड़कियों को आत्मसुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

इससे लड़कियों कि सुरक्षा सुनिचित हो जाएगी।

उत्तर (b) वयोवृद्ध कि अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए

- विद्यालयों के प्रधानाचार्य से संपर्क करके उन्हें, लड़कियों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने पर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सम्मानित करने के लिए सहमत करेंगे।
- सोशल मीडिया और स्थानीय प्रिंट मीडिया के द्वारा स्थानीय महिलाओं कि उपलब्धियों का प्रचार करेंगे।
- क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं कि सहायता से लैंगिक समानता एवं लड़कियों कि शिक्षा कि जागरूकता अभियान चलाएंगे। नवयुकों, युवतियों और बुजुर्ग महिलाओं के साथ मिलाकर इस आन्दोलन को घर घर पहुँचायेगे. वयोवृद्ध को नैतिक अनुरोध, सामाजिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार एवं कानून का डर दिखा कर लड़कियों कि शिक्षा के लिए सहमत कर लेंगे।
- फिर भी यदि कुछ लोग नहीं मानेंगे तो पुलिस से आवश्यक कार्यवाही के लिए कहेंगे।

केस स्टडी-02

आप एक सरकारी कार्यालय में अपने विभाग के निदेशक के सहायक के रूप में कार्यरत है नेक युवा, उचाकांची, एवं निष्कपट कर्मचारी हैं. जैसा कि आपने अभी पद ग्रहण किया है, आपको सीखने और प्रगति कि आवश्यकता है. भाग्यवश आपका उच्चस्थ बहुत दयालु एवं आपको अपने कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है. वह बहुत बुद्धिमान और पूर्ण जानकार व्यक्ति है, जिससे विभिन्न विभागों का ज्ञान है। संक्षेप में आप अपने बॉस का सम्मान करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को उत्सुक हैं।

जैसा कि आपके साथ बॉस के सम्बन्ध अच्छे है, वह आप पर निर्भर करने लगा है. एक दिन खराब स्वास्थ्य के कारण उसने आपको कुछ आवश्यक कार्य करने के लिए घर बुलाया।आप उसके घर पहुंचे एवं घंटी बजने से पूर्व आपने जोर जोर से चिल्लाने का शोर सुना. आपने कुछ समय प्रतीक्षा की घर में प्रवेश करने पर बॉस ने आपका अभिनन्दन किया तथा कार्य के बारे में बतया। किन्तु आप एक औरत के रोने कि आवाज से निरंतर व्याकुल रहे. अंत में आपने अपने बॉस से पूछा परन्तु उसने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया।

अगले दिन आप कार्यालय में इसके बारे में आगे जानकारी करने को उद्वलित हुए एवं मालूम हुआ कि उसका घर में अपनी पत्नी के साथ व्यवहार बहुत खराब है. वह अपनी पत्नी के साथ मार पीट भी करता है. उसकी पत्नी ठीक से शिक्षित नहीं है तथा अपने पति कि तुलना में एक सरल महिला है। आप देखते हैं आपका बॉस कार्यालय में सरल

व्यक्ति है, परन्तु घर पर वह घरेलू हिंसा में संलिप्त है।

इस स्थित में, आपके सामने निम्नलिखित विकल्प बचे हैं. प्रत्येक विकल्प का परिणामो के साथ विश्लेषण कीजिये.

a. इस बारे सोचना छोड़ दीजिये क्यूंकि यह उसका व्यक्तिगत मामला है।

b. उपयुक्त अधिकारी को मामले को प्रेषित कीजिये।

c. स्थिति के बारे में आपका स्वयं का नवप्रवर्तनकारी दृष्टीकोण।

उत्तर: दिए गए मामला अध्ययन में मैं एक नव नियुक्त युवा कर्मचारी हूं. मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कि जा रही घरेलु हिंसा की समस्या हल करनी है. इस प्रकरण में सहानभूति, करुणा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, जिम्मेदारी, लैंगिक समानता एवं न्याय जैसे मूल्य निहित है.

विकल्पों का परिणाम के साथ विश्लेषण

a. इस बारे सोचना छोड़ दीजिये क्यूंकि यह उसका व्यक्तिगत मामला है।

ऐसा करना अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता करना होगा।

महिला न ही पर्याप्त शिक्षित है और न ही वित्तीय रूप से आत्मानिर्भर है. अत: निरंतर घरेलु हिंसा से हताश हो कर वो भविष्य में आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है। इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी को भी मुश्किलों का सामना करना पद सकता है, और मैं भी हमेशा अपराध बोध से ग्रस्त रहूँगा।

b. उपयुक्त अधिकारी को मामले को प्रेषित कीजिये।

उपयुक्त अधिकारी इस मामले के संज्ञान में आने पर एक विभागीय समित का गठन कर मामले कि जाँच कराएँगे. इससे वरिष्ठ आधिकारी के घरेलु हिंसा में शामिल होने कि पुष्टि हो जाएगी. फलस्वरूप उन्हें विभाग से निलंबित कर दिया जायेगा, एवं स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर उन्हें सजा दिलाई जाएगी।

ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी तो जेल चले जायेंगे पर वास्तव में इसका ज्यादा असर उनके पत्नी पर पड़ेगा. पत्नी पर्याप्त शिक्षित नहीं है और न आत्मनिर्भर है. ऐसे उसके पास वित्तीय सहारा नहीं होगा और सरकारी आवास भी खाली करना होगा. विभाग एक कर्तव्यनिष्ठ और कुशल अधिकारी खो देगा. मेरी व्यक्तिगत हानि होगी क्योंकि मैं एक दयालु जानकार एवं सहायता करने वाला अधिकारी खो दूंगा।

c. स्थिति के बारे में स्वयं का नवप्रवर्तनकारी दृष्टिकोण।

(मेरे अधिकारी एक दयालु एवं समझदार व्यक्ति हैं अत: उन्हें सुधार का एक मौका मिलना चाहिए)

मैं सर्वप्रथम महिला पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से संपर्क करूँगा जिससे इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता है। इस संस्था के विशेषज्ञों कि सहायता से अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं उनके पत्नी को सलाह एवं परामर्श दिलवाऊंगा जो वरिष्ठ अधिकारी को नैतिक अनुरोध और कानूनी परिणामों के आधार पर समझायेंगे।

नैतिक अनुरोध: घर पर होने वाली दैनिक कलह होने नकारात्मक प्रभाव उनकी स्वयं कि कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य पर पड़ेगा. पत्नी में निराशा घर कर जाएगी जिसका प्रभाव बच्चों कि परवरिश एवं संस्कारों पर पड़ेगा. महिला के प्रति हिंसा अशोभनीय कृत्या है. परिवार की खुशी में ही उसकी खुशी है।

कानून का डर: सक्षम अधिकारी से शिकायत होने पर जांच में आसानी से उनका अपराध सिद्ध हो जायेगा. फलस्वरूप उनकी नौकरी जा सकती है और करावास हो सकता है.पेंशन और आनुतोषिक भी जब्त हो सकता है. कारागृह से बहार आने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी।

इस अंतर्कलह के कारण महिला पर्याप्त शिक्षित न होना भी हो सकता है. इसलिए गैर सरकारी संस्था की सहायता से पत्नी को व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला दिला देंगे और पुन: शिक्षा आरम्भ करने को प्रेरित करेंगे. इससे समस्या हल हो सकती है।

यदि फिर भी अधिकारी के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ तो कानून के अनुसार अधिकारी को दंड दिलाएंगे और एन0जी0ओ की सहायता से पत्नी को पुनर्वास एवं आतमनिर्भर बनने में सहायता करेंगे।

केस स्टडी-03

आप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 2019 में 16 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु हुई थी। इससे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण एवं वनों के घटते क्षेत्रफल के प्रति चिंतित हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, एक दिन में 7 करोड़ पौधे लगाकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने सम्बन्धी योजना पर कार्य करने के लिए निर्देश जारी कर दिया। मंत्रालय ने आपको इस योजना की व्यवहारिकता एवं संभाव्यता का अध्ययन करके 3 दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है, जिसे कैबिनेट के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है.

a. इस मामले मे निहित विभिन्न मुद्दों की विवेचना कीजिए।

b. इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियों की उनके गुण और दोषों के साथ विवेचना कीजिए।

उत्तर: दिए गए मामले अध्ययन में मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूं। मुझे एक दिन में 7 करोड़ पौधे लगाने की योजना की व्यवहारिकता एवं संभाव्यता पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। इस मामले में वस्तुनिष्ठता, जिम्मेदारी, जवाबदेहिता, संसाधनों का प्रबंधन एवं प्रकृति के प्रति संवेदना जैसे मूल्य निहित हैं।

नैतिक मुद्दे :

पर्यावरण एवं प्रदूषण अति संवेदनशील मुद्दे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य एवं अस्तित्व से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। सरकार को प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को, विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की इच्छा से जोड़ना सरकार की लापरवाही को ही दर्शाता है। ये दिखाता है कि सरकार केवल प्रचार एवं मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहती है।

ऐसे वृक्षारोपण अभियान के लिए बहुत सी तैयारी एवं वित्त की आवश्यक्ता होती है। बाजार इतने सारे पौधे कम समय में उपलब्ध नहीं कर सकती। ऐसी योजनाओं से, पौधों की गुणवत्ता से समझौता होता है और भ्रष्टाचार के अवसर उपलब्ध होते हैं। हमें पड़ोसी राज्यों से पौधों का आयात करना पड़ता है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत बहुत बढ़ जाती है। दूसरे राज्यों के पौधे, स्थानीय मृदा एवं जलवायु में अच्छे से

पुष्पित एवं पल्लवित भी नहीं हो पाते। इससे जमाखोरी, कालाबाजारी, धोखाधड़ी, मूल्य-वृद्धि जैसे विभिन्न कदाचारों को बढ़ावा मिलता है। कभी-कभी पौधशालाएं पौधों के नाम पर डालों की आपूर्ति कर देती हैं, जो कुछ समय पश्चात सूख जाती हैं। इन सबसे जनता के धन और संसाधनों का दुरूपयोग होता है।

मेरी संस्तुतियाँ :

मैं सरकार को वृक्षा-रोपण अभियान एक सतत् प्रक्रिया के रूप में चलाने की सलाह दूंगा। मेरे अनुसार सरकार को, राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लाक में, वृक्षारोपण अभियान के लिए आधारभूत संरचना विकसित करनी चाहिए। हमें स्थानीय पौधशालाओं से पौधें की नियमित आपूर्ति के लिए अनुबंध करना चाहिए और वृक्षारोपण अभियान को पूरे वर्ष चलाना चाहिए, यद्यपि हम पहले से तैयारी करके मानसून में ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमें वृक्षारोपण अभियान के लिए आवश्यक ज्ञान एवं अनुभव वाले, स्थानीय गैर सरकारी संगठनी एवं स्वयं सहायता समूहों से अनुबंध करना चाहिए और पौधों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। हमें एक प्रक्रिया विकसित करके, वृक्षारोपण के समय कुल धन-राशि का केवल 40 प्रतिशत भुगतान करना चाहिए और शेष राशि, 20 प्रतिशत की तीन वार्षिक किश्तों में दी जानी चाहिए। हमें पौधों को जियों टैग करना चाहिए और सूखे पौधों को विस्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए।

गुण : इससे पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी एवं प्रदूषण कम होगा।

- लोगों को नियमित रूप से रोजगार मिलेगा।
- राज्य पर आर्थिक दबाव कम होगा।
- स्थानीय पौधे आसानी से लग जाएंगे।
- भ्रष्टाचार नियंत्रित होगा।

दोष : हमें आधार-भूत संरचना विकसित करनी होगी लेकिन लंबे समय में यह लाभदायक रहेगा।

केस स्टडी-04

आप नोएडा के जिलाधिकारी हैं। पिछले कुछ सप्ताह में आपको विभिन्न पेट्रोल-पंपों में अनियमितताओं से संबंधित कई शिकायतें मिली हैं। जांच के दौरान आपको पता चलता है कि कई पेट्रोल पंप के मालिकों ने पेट्रोल मापने वाली मशीन में एक इंटीग्रेटेड चिप लगा दी है। इस चिप के कारण मशीन हर बार 5 प्रतिशत पेट्रोल कम भरती है, जबकि मीटर पूर्ण मात्रा दर्शाता है।

आपने शीघ्र ही ईमानदार अधिकारियों का एक दल बना करके, उन्हें औचक छापा मारने, दोषियों को गिरफ्तार करने और चिप वाली मशीनों को जब्त करने के लिए निर्देश दे दिये। जनता ने भी आपके प्रयासों की प्रशंसा की, पर जब उन्हें पेट्रोल के लिए लम्बी कतारो में लगना पड़ा तो उनका उत्साह भंग हो गया। शीघ्र ही पेट्रोल पंप मालिकों ने औचक छापों का विरोध करने के लिए एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया। उन्होंने पूर्ण हड़ताल की धमकी जारी कर दी। इससे जनता भी डर गई। पेट्रोल-पंप मालिकों के समर्थन में नेता भी आप पर दबाव डाल रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के विकल्पों में कुछ निम्नलिखित हो सकते है.

a. पेट्रोल पंपों पर छापों की कार्यवाही रोक देंगे।

b. विभिन्न तेल कंपनियों से सहयोग मांगेंगे।

c. अपने अच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराएंगे, उनसे निर्देश मांगेगे और उसी अनुसार कार्य करेंगे।

सभी विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए और कारणों के साथ सबसे अच्छा सम्भव विकल्प सुझाइए।

उत्तर: दिए गए मामला अध्ययन में मैं नोएडा का जिलाधिकारी हूं जहां मुझे पेट्रोल-पंप मालिकों द्वारा किए जा रहे कदाचार को नियंत्रित करना है। इस मामले में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, जनसेवा के लिए समर्पण एवं न्याय जैसे : मूल्य निहित हैं।

विकल्प:

(a) गुण: इससे संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जनता को राहत मिलेगी। पेट्रोल-पंप मालिक मुझे परस्कृत कर सकते हैं।

दोष: इससे पेट्रोल-पंप मालिक और ज्यादा धोखधड़ी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मीडिया मेरी निंदा करेगी। न्यायालय भी स्पष्टीकरण माग सकता है।

(b) गुण: इससे मुझे सहायता मिलेगी। तेल कंपनियां तकनीकी सहायता दे सकती हैं. इससे पेट्रोल-पंप मालिकों पर सहयोग करने के लिए दबाव बढ़ेगा।

दोष: तेल कंपनियों के कुछ कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते है। इससे हमारी रणनीति की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।

(c) गुण: उच्च अधिकारियों को सूचित करना अच्छा कदम है. जरूरत पड़ने पर वो आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सकते हैं. कोई अन्य व्यक्ति उन्हें गलत सूचना देकर भ्रमित नहीं कर पाएगा।

दोष: मुझे अपने कार्य का ज्ञान है, अत: उच्च-अधिकारियों से निर्देश मांगने एवं उन्हें परेशान करने का की आवश्यक्ता नहीं है। यदि उच्च अधिकारी स्वत: निर्देश देते हैं तो इसके गुणों के आधार पर पालन करूंगा।

मेरी कार्यवाही:

मैं तुरंत 'आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून' (ESMA) लागू कर दूंगा और पेट्रोल-पंप मालिकों को हड़ताल न करने की चेतावनी दूँगा। तत्पश्चात मैं पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एक मीटिंग आयोजित करूंगा, उन्हें संबंधित कानूनों की जानकारी दूँगा और निरीक्षण के दौरान सहयोग करने के लिए निर्देश दूँगा. इसके उपरान्त मैं तेल कंपनियों के प्रबंधन से बात करके उन्हें जब्त की गई मशीनों को शीघ्र विस्थापित करने के लिए सहमत करूंगा जिससे जनता को परेशानी न हो। तत्पश्चात में उच्च अधिकारियों से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराऊंगा और आश्वस्त करूंगा। सार्वजनिक पेट्रोल-पंपों का 24 घंटे संचालन सुनिश्चित करूंगा। पेट्रोल-पंप निरीक्षण के लिए अतिरिक्त दलों का गठन करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा और जनता को सहयोग के लिए उत्साहित करूंगा। मैं इस निरीक्षण प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करूंगा। एक सप्ताह के अंदर सभी पेट्रोल पंप का निरीक्षण पूर्ण करके, दोषयुक्त पेट्रोल पंप के संचालन के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों/मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सामान्य स्थिति बहाल कर दूंगा।

केस स्टडी-05

आप कोलकता के जिलाधिकारी हैं। अभी हाल ही में एक भारतीय दवा कंपनी ने कोरोना का टीका विकसित किया है. इसने 92 प्रतिशत सफलता दर के साथ, परीक्षण के सभी चरणों को उत्तीर्ण कर लिया है. इस टीके की लागत कम है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी सामने नहीं आया है. सरकार ने इसके प्रयोग की स्वीकृति दे दी है। पहले चरण के टीकाकरण के लिए आपके जिले को चुन लिया गया है। सरकार ने प्रथम चरण में केवल बुजुर्गों (जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है) के टीकाकरण के लिए निर्देश दिए है। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने टीके के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में अफवाह फैला दी। विदेशों से सोशल मीडिया में कई छद्म वीडियो चस्पा किए गए, जिनमें दावा किया गया कि ये टीका महत्वपूर्ण मानव अंगों को क्षति पहुंचा सकता है। इससे बुजुर्गो में डर व्याप्त हो गया और उन्होंने टीका लगवाने से मना कर दिया।

(a) आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध है।

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे. उसके कारण भी बताइए।

दिए गए मामले में मैं कोलकाता का जिलाधिकारी हूं। मुझे बुजुर्गों को कोरोना टीका लगवाने के लिए सहमत करना है। इस मामले में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, करुणा और सेवा भावना जैसे मूल्य निहित हैं।

विकल्प (1)- टीकाकरण का अवसर जिले के युवा लोगों को हस्तांतरित कर देंगे।

गुण- अधिकांश युवा शिक्षित होते हैं. वे तर्क का प्रयोग करते हैं। इसलिए उन्हें समझाना आसान होता है. एक बार ये प्रक्रिया आरम्भ कर देंगे तो द्वितीय चरण में बुजुर्ग भी टीकाकरण के लिए सहमत हो जाएंगे।

दोष- सरकार अपने निर्देशों के विपरीत युवाओं को टीका देने की मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर सकती है. कुछ वृद्ध व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है।

विकल्प (2) टीकाकरण का अवसर दूसरे जिले को हस्तांतरित कर दें।

गुण- दूसरे जिले के साथी नागरिकों को लाभ मिलेगा।

दोष- वृद्ध लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। यह अवसर की हानि है। इससे दूसरे जिलों के नागरिकों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

विकल्प (3)- बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए बल-प्रयोग करेंगे।

गुण- इससे बुजुर्ग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हो जायेंगे।

दोष- वृद्ध लोगों के प्रति बल-प्रयोग पूर्णतः अनैतिक होगा. यह टीका न लगवाने की उनकी इच्छा को ही बल प्रदान करेगा. वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

विकल्प (4)-सर्वप्रथम मैं मुख्य सचिव से अनुरोध करूँगा कि वे साइबर सेल को इंटरनेट से भ्रामक वीडियो हटाने के लिए निर्देश दें। तत्पश्चात् मैं टीका बनाने वाली कम्पनी के प्रबंधन से अनुरोध करूँगा कि वे द्वितीय और तृतीय चरण के टीका परीक्षण में शामिल व्यक्तियों की जानकारी (नाम, पता और फोन नम्बर) अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। मैं इनमें से कुछ लोगों से सम्पर्क करके अपने जिले में आमंत्रित करूँगा।

हम इन व्यक्तियों के साथ पूरे जिले में सार्वजनिक बैठक (2 गज की दूरी के साथ) आयोजित करेंगे। जहाँ ये व्यक्ति जनता के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और उनके संदेहों का समाधान करेंगे। हम इन सार्वजनिक बैठकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित कर देंगे. इसके अतिरिक्त मैं प्रत्येक वार्ड और ग्राम सभा में चिकित्सा परामर्शदाताओं की नियुक्ति करूँगा जो घर-घर जाकर बुजुर्ग व्यक्तियों एवं उनके परिवारी जनों को टीका के प्रति आश्वस्त करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया का सहयोग लूँगा और लोगों के संदेहों एवं प्रश्नों के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित करूँगा. ये सारे प्रयास एक सकारात्मक वातावरण बनाएँगे। अन्त में टीकाकरण वाले दिन एक सार्वजनिक समारोह (2 गज की दूरी के साथ) में, मैं सर्वप्रथम स्वयं टीकाकरण कराऊँगा (उच्च अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति से). इससे बुजुर्ग लोगों में आत्मविश्वास आ जाएगा और वे टीकाकरण करा लेंगे।

इससे जनता के सभी संदेह दूर हो जायेंगे और टीकाकरण की प्रक्रिया सफलता के साथ पूर्ण हो जाएगी। बुजुर्ग लोगों को आवश्यक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। मैं इसी विकल्प का चयन करूँगा।

केस स्टडी-06

आप एक जिलाधिकारी हैं और आंध्र प्रदेश के एक दूरस्थ जिले में तैनात हैं। भारत सरकार आपके जिले में एक विशाल-परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है. यह विद्युत ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारिक संरचना विकसित करने में सहायक होगा। यह स्पष्ट है कि इससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा।

परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए आबादी से दूर, बंजर भूमि का प्रयोग किया गया है. यह उच्च स्तर की ऊर्जा-दक्ष तकनीक पर आधारित है. पर्यावरण पर इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा, जबकि ताप विद्युत संयंत्र से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। विकिरण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा-उपाय किए गए हैं।

जैसे ही मीडिया ने इस परमाणु संयंत्र की जानकारी सार्वजनिक की, एक लोकप्रिय गैर सरकारी संगठन ने आपके जिले में धरना-प्रदर्शन आरम्भ कर दिया। इसने परमाणु-विकिरण के सम्बन्ध में अफवाह फैला दी, और इस संयंत्र को पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित कर दिया। इसने पूर्व में परमाणु संयंत्रों में हुए विस्फोटों के वीडियों सोशल मीडिया में प्रसारित कर दिए और सरकार से इस योजना को निरस्त करने की मांग आरंभ कर दी। बहुत से लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, और देखते-देखते ये एक आंदोलन में तब्दील हो गया।

इसी बीच खुफिया संस्थाएं सूचित करती है, कि इस गैर सरकारी संगठन ने भारत में विकास-परियोजनाओं को बाधित करने के लिए, विदेशी सरकारें भारी मात्रा में धन हासिल किया है।

(a) इस प्रकरण में अंतनिर्हित नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए।

(b) अब आप क्या कार्यवाही करेंगे।

उत्तर a : दिए गए मामले के अध्ययन में मैं आंध्र प्रदेश में जिलाधिकारी

हूं. मुझे लोगों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना है. इस मामले में वस्तुनिष्ठता, विश्वास, देशभक्ति और धारणीय विकास जैसे मूल्य निहित हैं।

नैतिक मुद्देः

दिए गए मामले में एक लोकप्रिय गैर-सरकारी संगठन अपने निहित स्वार्थो के लिए, देश के लोकतांत्रिक ढांचे का दुरूपयोग कर रहा है. इसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सुरक्षा-उपायों के बारे में लोगों को भ्रमित करके, जनता और सरकार के मध्य अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है. इस गैर सरकारी संगठन ने जनता को विरोध-प्रदर्शन के लिए भड़का दिया है। जनता स्वयं अपने विकास को रोकने के लिए धरना दे रही है। ये गैर सरकारी संगठन मौलिक अधिकारों (अनु019(1)-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता) एवं विरोध प्रदर्शन के अधिकारों का अपने ही देश के प्रति दुरूपयोग कर रहा है। ये कुछ विकसित देशों की दुष्टता भी दिखता है जो विकासशील देशों को, प्रदूषण एवं भूमंडलीय ऊष्मन रोकने के उनके संघर्ष में न ही आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराते है और न ही वित्तीय सहायता देते हैं, लेकिन इनके विकास को बाधित करने के लिए ऐसे अनैतिक प्रयास अवश्य करते हैं। वास्तव में इन विकसित देशों को डर लगता है कि भारत, अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रयोग यूरेनियम के संवर्धन एवं परमाणु बम बनाने के लिए कर सकता है।

उत्तर b : मेरी कार्यवाहीः

सर्वप्रथम मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, इस गैर सरकारी संगठन के बैंक खातों एवं वित्तीय लेन-देन की जांच कराये। धरना-प्रदर्शन के दौरान व्यापक सुरक्षा-व्यवस्था करूंगा।

तत्पश्चात मैं इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के सहयोग से जनता को उन नवीनतम तकनीकों की जानकारी दूंगा, जिनका प्रयोग करके इस संयंत्र के खतरे को न्यूनतम कर दिया गया है. हम उन्हें पर्यावरण-संरक्षण एवं विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता समझाएंगे. हम उन्हें विकसित देशों (जैसे-फ्रांस) के बारे में जानकारी देंगे जो 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संयंत्र से करते है।

हम परमाणु ऊर्जा संयत्र एवं ताप-विद्युत संयंत्र के तुलनात्मक अध्ययन पर कार्यक्रम प्रसारित कराएंगे। इससे जनता को जीवाश्म ईंधन की तुलना में परमाणु ऊर्जा के लाभों को समझने में सहायता मिलेगी। इसके पश्चात हम परमाणु ऊर्जा संयत्र में अपनाए गए सुरक्षा उपायों एवं वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की राय पर एक वीडियों बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित कर देगें। इससे जनता अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जाएगी। हम उन्हें इससे होने वाले विकास एवं रोजगार की संभावनाओं के बारे में भी बताएंगे। कुछ समय में प्रवर्तन निदेशालय अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगा। इससे जनता, गैर सरकारी संगठन के छुपे उद्देश्य को समझ जाएगी और समस्या पूर्णतयः हल हो जाएगी।

केस स्टडी-07

मध्य प्रदेश में प्याज की अच्छी फसल होने से इसका बाजार मूल्य घटकर 500 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार ने किसानों के हित में प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति क्विंटल घोषित करते हुए, सभी प्याज खरीद केन्द्रों को किसानों से प्याज खरीदने के आदेश जारी कर दिए है।

बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में, भारी अंतर होने के कारण बहुत से दलालों ने, खरीद केन्द्रों के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर ली. ये दलाल, व्यापारियों के गोदामों में स्थित पिछले वर्ष के प्याज को, खरीद केन्द्रों पर विक्रय करने में उनकी सहायता कर रहे हैं।

इंदौर के किसानों को अपना प्याज विक्रय करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे किराये की ट्रालियों में प्याज रखकर, कई दिनों तक लाइन में खड़े रहते हैं, जिससे इनकी लागत बढ़ जाती है। जुलाई का महीना होने से, जलवायु ऊष्ण और आद्र है. बारिश में भीगने और फिर धूप लगने से प्याज अक्सर सड़ जाते है।

हताश होकर किसानों ने राष्ट्रीय महामार्ग पर अपने ट्रैक्टर-ट्राली खड़ा करके इसे अवरूद्ध कर दिया. इससे वाहनों का आवागमन और वस्तुओं का परिवहन, दोनों रूक गया है। इंदौर के नागरिकों को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है।

इस प्रकरण की जानकारी मिलते ही सरकार ने इंदौर के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया और आपको वहां का जिलाधिकारी नियुक्त करते हुए समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देश दिये.

(a) इस प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न नैतिक मुद्दों की विवेचना कीजिए।

(b) अब आप क्या कार्यवाही करेंगे?

दिये गए मामले में मुझे तत्काल इंदौर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के प्याज की खरीद सुनिश्चित करके सामान्य स्थिति बहाल करना है. इस प्रकरण में ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, करुणा और न्याय जैसे मूल्य निहित हैं।

नैतिक मुद्दे

दिए गए मामले में किसानों की दुर्दशा दिखाई गई है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है लेकिन दलाल, खरीद केन्द्र के कर्मचारी और व्यापारी सांठगांठ करके किसानों को ठग रहे हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाये. हरित क्रान्ति, तकनीक के प्रयोग एवं किसानों के कठिन परिश्रम से प्रति हेक्टेयर अनाज के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है. लेकिन किसान अभी भी गरीब हैं. फसलों की अच्छी पैदावार एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनकी सहायता नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों, खर-पतवार नाशक, कीटनाशक एवं मशीनों के प्रयोग से कृषि की लागत बढ़ गई है। खुश और संतुष्ट किसान अर्थव्यवस्था का आधार हैं, लेकिन इन्हें अपनी फसल की कीमत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसे विरोध प्रदर्शन, व्यापार एवं आम नागरिकों के जीवन को भी बाधित करते हैं. यदि इनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया तो आन्दोलन हिंसक हो सकता है।

किसी भी वर्ग की गरीबी, समाज के हर वर्ग की सम्पन्नता के लिए खतरा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है. हमें एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली विकसित करके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना

होगा।

कार्यवाही:

मैं आवश्यक सुरक्षा बल के साथ तुरन्त खरीद केन्द्र पर छापा डालकर वहाँ उपस्थित सभी दलालों एवं व्यापारियों को गिरफ्तार कर लूँगा. हम उनके प्याज और वाहनों को जब्त कर लेंगे. मैं संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में ले लूँगा और जाँच पूरी होने तक के लिए इस ऋतु में खरीदे गए प्याज के भुगतान पर रोक लगा दूँगा। मैं प्याज खरीद के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करूँगा, जिसके अनुसार केवल किसानों से ही उनकी पहचान करने के उपरान्त प्याज खरीदा जाएगा. पिछले वर्ष के प्याज की खरीद प्रतिबंधित कर दूँगा और शीघ्र ही किसानों के प्याज की खरीद आरम्भ करा दूँगा। मैं खरीद केन्द्र के प्रबंधन को टोकन व्यवस्था आरम्भ करने एवं नए काउंटर खोलने के लिए सहमत कर लूँगा. इससे किसानों के धन एवं समय की बचत होगी। नए दिशा-निर्देश में केवल बैंक के जरिए कीमत का भुगतान होगा किसानों और उनके वाहनों का ब्यौरा रखना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात मैं उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करूँगा और इसे किसानों के आरोपों एवं खरीद केन्द्रों के कर्मचारियों की भूमिका की जांच करके पांच दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहूँगा.

तत्पश्चात् मैं किसानों से मिलूँगा और खरीद केन्द्र पर बारिश से सड़ गई प्याज की फसल के लिए हर्जाने की घोषणा करूँगा. मैं उन्हें अपने कार्यालय का फोन नम्बर देकर भविष्य में भी प्रशासन के सहयोग के प्रति आश्वस्त करूँगा। इससे प्रशासन में उनका विश्वास बहाल हो जाएगा. अत: मैं उन्हें आसानी से धरना समाप्त करने और खरीद केन्द्र जाकर प्याज विक्रय करने के लिए सहमत कर लूँगा. उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलते ही मैं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करूँगा। इससे किसानों को न्याय मिल जायेगा और भविष्य के लिए एक सबक हो जाएगा।

केस स्टडी-08

आपको हाल ही में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। आप देखते है कि श्रमिक बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे है। ये मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से आए हुए प्रवासी मजदूर है. इनमें से अधिकांश श्रमिक जहाजों को तोड़ने का काम करते है. इन्हें न ही प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही सुरक्षा-उपकरण. इन्हें पीने के लिए शुद्ध जल भी उपलब्ध नहीं होता. ये अक्सर हानिकारक रसायनों (जैसे एस्बेस्टस) के सम्पर्क में आते हैं और विभिन्न बीमारियों जैसे : त्वचा कैंसर, फेफडों के कैंसर, टीबी इत्यादि का शिकार हो जाते है. कई बार ये जहाजों से गिर जाते है और इनके हाथ-पैर टूट जाते हैं।

जहाज तोड़ने के कार्य में संलग्न विभिन्न इकाइयां, सरकार को भारी कर (जैसे: कस्टम शुल्क 15 प्रतिशत एवं उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत) चुकाती हैं, लेकिन मजदूरों को सरकार से आवश्यक सहायता नहीं मिल पाती जब आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इन समस्याओं की चर्चा करते हैं तो वो नजर अंदाज करने के लिए कहते हैं, पर आपकी अंतरात्मा को यह स्वीकार नहीं है.

(a) आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध है?

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे. उसके कारण भी बताइए।

दिए गए मामला अध्ययन में, मैं गुजरात, मैरी टाइम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूं, जहां मुझे श्रमिकों की विभिन्न समस्याएं हल करनी है. इस मामले में जिम्मेदारी, जवाबदेहिता, करूणा, सेवा भावना एवं न्याय जैसे मूल्य निहित है।

विकल्प:

1. श्रमिकों की समस्या को नजरअंदाज कर दें।

गुण: अतिरिक्त प्रयास करने में लगने वाले समय और ऊर्जा की बचत होगी।

दोष : श्रमिक परेशान होते रहेंगे तथा मुझे अपराध बोध होगा।

2. श्रमिकों से निजी व्यय करके, नौकरी से पहले प्रशिक्षण लेने, और सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए कहेंगे।

गुण : इससे श्रमिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने एवं दुर्घटना कम करने में सहायता मिलेगी.

दोष : इससे श्रमिकों की आय पर अतिरिक्त भार पड़ेगा तथा हो सकता है वो इसे वहन न कर पाएं।

3. मैरी टाइम बोर्ड से किसी अन्य विभाग में हस्तांतरण करा लें।

गुण : मैं अपराध बोध से मुक्त हो सकता हूं।

दोष : यह कायरतापूर्ण कार्य होगा। इससे मजदूरों की समस्या हल नहीं होगी।

4. एक गैर सरकारी संगठन की सहायता से मैं मजदूरों के मध्य एक सर्वेक्षण करूंगा, उनके प्रतिनिधियों से बात करूंगा और उनकी समस्याओं की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाऊंगा। इसके साथ मैं सम्बन्धित श्रम कानूनों की सूची, सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्धित निर्णय, और आवश्यक सुधारों के लिए अपनी संस्तुति संलग्न करूंगा. इसकी एक-एक प्रति मैं अपने विभाग के सचिव एवं कैबिनेट मंत्री को भेज दूंगा। सरकार को आवश्यक सुधार करने में समय लगा सकता है इसलिए मैं श्रमिकों के कल्याण में कार्यरत किसी अनुभवी एवं लोकप्रिय गैर सरकारी संगठन से संपर्क करूंगा। मैं इसे मैरी टाइम बोर्ड को आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी देने की व्यवस्था करने के लिए कहुंगा। इसके पश्चात मैं विभिन्न मालवाहक/यात्री-जहाज कंपनियों और देश में कार्यरत अन्य कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क करूंगा। हम उन्हें अपनी पहल के बारे में सूचित करेंगे, और निगमों के सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से, इस गैर सरकारी संगठन को वित्त प्रदान करने के लिए सहमत करेंगे. इस धन से हम सभी श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देगें और उन्हें पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयाप्त संख्या में वाटर-कूलर लगाएंगे। तत्पश्चात मैं सभी इकाइयों के प्रबंधकों के साथ मीटिंग करके उन्हें, मजदूरों को सुरक्षा-उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सहमत कर लुंगा, क्योंकि इससे मजदूरों का निष्पादन बढ़ेगा, जिसका लाभ इन इकाइयों को मिलेगा। इसके उपरांत मैं पात्र मजदूरों को 'आयुष्मान भारत योजना' के बारे में शिक्षित करके उन्हें अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करूंगा. इससे उन्हें बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल जाएगी। सरकार भी शीघ्र ही मेरी रिपोर्ट पर कार्य करेगी, जिससे समस्या हमेंशा के लिए हल हो जाएगी।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. फ्लडवॉच मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके माध्यम से उपयोगकर्ता पूरे देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. यह एप्लिकेशन 24 नदी घाटियों में फैले 1543 में से 328 बाढ़ निगरानी बिंदुओं के आधार पर पूर्वानुमान लगाएगा।
3. इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A. 1 और 2
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क, ब्याज दरों के खुलासे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा।
2. इससे ऋण खाते की ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।
3. इसके अंतर्गत विनियमित संस्थाएं (REs) अपने नीतिगत ढांचे में उचित संशोधन कर सकती हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1,2 व 3
D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है।
2. यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसमें दिए गए मॉडल के बेस वेरिएंट का परीक्षण किया जाएगा।
3. इस परीक्षण में कार के प्रदर्शन के आधार पर, वाहन को वयस्क यात्रियों (AOP) और बच्चों के बैठने वालों (COP) के लिए 0-5 के पैमाने पर स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों की सहायता से सही कथन का चुनाव करें-

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 1 और 3

4. उद्गम (UDGAM) पोर्टल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनता के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में उनकी जमा राशि की खोज में मदद करने के लिए विकसित किया गया है।
2. इसकी घोषणा 6 अप्रैल, 2023 को एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल के रूप में की गई थी।
3. इस पोर्टल को रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (REBIT), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (IFTAS) और बैंकों के सहयोग से विकसित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 1 और 3

5. 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' को प्रदान किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्रमशः गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए आलिया भट्ट और कृति सेनन को प्रदान किया गया।
2. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 'पुष्पा' के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया।
3. सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार 'द कश्मीर फाइल्स' के लिए अभिनेत्री पल्लवी जोशी को प्रदान किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) के मसौदा दस्तावेज के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दस्तावेज के अनुसार कक्षा 9 और 10 के छात्रों को अब अनिवार्य रूप से दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा।
2. इसमें कहा गया है कि कक्षा 12 में छात्रों का मूल्यांकन अधिकतम सात विषयों पर किया जाएगा।
3. राज्य सरकारों और संबंधित स्कूल बोर्डों को R1, R2 और R3 भाषा को तय करने की स्वतंत्रता दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 2 और 3
D. कोई नहीं

7. हाल ही में यूजीसी ने पांडुलिपियों के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पांडुलिपि विज्ञान में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए एक समिति गठित होगी।
2. इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं, पांडुलिपियों में दर्शन, विज्ञान, साहित्य, धर्म और विविध विषयों को भी शामिल किया गया है।
3. पांडुलिपि विज्ञान हस्तलिखित दस्तावेजों के माध्यम से समाजशात्र का अध्ययन है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 2
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

8. हाल ही में नैनीताल के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक पक्षी सर्वेक्षण के दौरान पक्षी प्रजातियों की गणना गयी। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके अंतर्गत दो गंभीर रूप से लुप्तप्राय, चार संवेदनशील और दो लुप्तप्राय प्रजातियों सहित लगभग 275 पक्षी प्रजातियों की गणना की गई।
2. इस सर्वेक्षण के दौरान शोधकर्ताओं ने चार लुप्तप्राय प्रजातियों सहित पलास, फिश ईगल तथा मिस्र के गिद्ध की भी गिनती की है।
3. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय मानी जाने वाली दो प्रजातियों अर्थात् सफेद दुम वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध को भी इस सर्वेक्षण में उल्लेखित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

9. कुवी और देसिया पुस्तकों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने भुवनेश्वर में कुवी और देसिया पुस्तकें लॉन्च कीं।
2. यह ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, डाक विभाग और एनसीईआरटी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है।
3. कुवी और देसिया पुस्तकें उत्तर प्रदेश के आदिवासी समुदाय को एक मजबूत एवं शैक्षिक नींव प्रदान करेंगी तथा सांस्कृतिक, भाषाई विरासत और पहचान को संरक्षित करेंगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1 और 2 D. कोई नहीं

10. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है।
2. इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था।
3. कॉर्बेट नेशनल पार्क कुल 520.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमे नदी बेल्ट, दलदली अवसाद, घास के मैदान और एक बड़ी झील भी शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1 और 2 D. सभी

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोलंबो के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए श्रीलंका की गोटावाया राजपक्षीय की सरकार ने संयुक्त रूप से भारत-जापान के साथ समझौता किया था।
2. यह सहयोग कार्यक्रम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, पाथफाइंडर, नेटस्ट्रेट व भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित किया गया।
3. श्रीलंका भारत के फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन परियोजना के साथ-साथ पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक हित में अहम महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
4. ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना में श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण का पूर्ण स्वामित्व है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 3 और 4 D. 2, 3 और 4

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुलिना चैनल रोमानिया के अंतर्गत आता है।
2. रोमानिया नाटो का सदस्य है।
3. डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत निकलती है।
4. यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है।

A. केवल 1 B. केवल 2 और 3
C. 1, 2, 3 और 4 D. इनमें से कोई नहीं

13. भारत और सूरीनाम सरकारों के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित एमओयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह समझौता ज्ञापन चिकित्सा विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित किया गया है।
2. यह सूरीनाम में दवाओं के मानकों की पुस्तक के रूप में इंडियन फार्माकोपिया को अनुमति देता है।

3. भारतीय फार्माकोपिया को पहले से ही अफगानिस्तान, घाना, नेपाल और मॉरीशस द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है।

4. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को भारतीय फार्माकोपिया को प्रकाशित और अद्यतन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दिए गए कथनों में से कौन सा/कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 3 B. केवल 2
C. केवल 1 D. केवल 4

14. अल्जाइमर रोग से संबंधित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

2. ऐसा माना जाता है कि यह मस्तिष्क में अमाइलॉइड प्रोटीन के असामान्य निर्माण के कारण होता है।

3. इस बीमारी के निदान के लिए एमआरआई और बायोमार्कर टेस्ट जैसे इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं।

4. अमेरिकी कंपनियों ने इसके इलाज के लिए डोनानेमैब और एडुकानुमाब जैसी दवाएं सफलतापूर्वक विकसित की हैं।

दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 2 B. केवल 3
C. केवल 1 D. ऊपर के सभी

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महाद्वीपीय शेल्फ पर पहला अंतरराष्ट्रीय कानून 1958 में आया।

2. नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बाधित होने से यूरोप ऊर्जा आपूर्ति के लिए अन्य विकल्पों पर ध्यान दे रहा है।

3. उत्तरी सागर डोवर जलसंधि व इंग्लिश चैनल द्वारा जोड़ा क्षेत्र है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है।

A. सिर्फ 1 B. 1 और 2
C. 2 और 3 D. 1, 2 और 3

16. निम्नलिखित में से सही कथन की विचार कीजिए:

1. भारत, समोआ के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला दूसरा देश है।

2. समोआ पोलिनेशिया क्षेत्र के अंतर्गत एक द्वीपीय देश है।

3. भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के अंतर्गत कुल 14 देश हैं जिसकी शुरुआत भारत में 2014 में किया था।

4. समोआ वर्ष 2023 के चोगम शासनाध्यक्षों के बैठक की मेजबानी करने जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है।

A. 1 और 2 B. 2 और 3
C. 3 और 4 D. सभी

17. हवाई द्वीप की प्रमुख भौगोलिक और भूवैज्ञानिक विशेषताएँ क्या हैं?

1. मौना केआ, द्वीप के ज्वालामुखियों में से एक, हवाई राज्य का उच्चतम बिंदु है।

2. हवाई द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।

इनमें से कौन सा कथन सत्य है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सितंबर, 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना सौर मिशन, आदित्य L1 लॉन्च किया।

2. L1 पृथ्वी-सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल में पांच बिंदुओं में से एक है, जहां दो-पिंड प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्रों का निर्माण करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

19. निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. INS विंध्यगिरि का नाम केरल की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है

2. यह 'प्रोजेक्ट 17 अल्फा' के तहत नौसेना के लिए बनाए जा रहे सात जहाजों में से छठा जहाज है।

3. प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ जहाज 2019 में नीलगिरि था।

कौन सा कथन सही है

A. 1 और 2 B. 2 और 3
C. 1 और 3 D. 1, 2 और 3

20. वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के कारक एजेंट के रूप में SARS-CoV-2 की पहचान कैसे की?

1. पारंपरिक माइक्रोबायोलॉजी विधियों का उपयोग करके।

2. मेटाजेनोम सीक्वेंसिंग का प्रयास करके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों 1 और 2 D. न तो 1 और न ही 2

21. हाल ही में चर्चा में रहा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड के बारे में विचार करें:

1. इसका गठन आर.बी.आई. द्वारा किया गया है।

2. इसे 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले में जाँच करने का अधिकार प्रदान किया गया।

3. इसमें एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होंगे।

उपर्युक्त में से कौन सा / से सही है ?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2
C. केवल 2 और 3 D. केवल 1 और 3

22. कोयला मंत्रालय द्वारा प्रमोट किया गया रेल-समुद्र-रेल (RSR) परिवहन पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. कोयल परिवहन से कार्बन इमिशन को बढ़ाने के लिए.
2. भारत में कोयले का उत्पादन 7.7% से कम करने के लिए.

उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सच नहीं है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों 1 और 2 D. न तो 1 और न ही 2

23. बूढ़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था?

A. उषा मेहता B. कनकलता बरुआ
C. एनी बेसेंट D. मातंगिनी हाजरा

24. भारत के आर्कटिक वैज्ञानिक मिशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईएनडीएआरसी आर्कटिक जलवायु और मानसून पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2014 में तैनात पहली पानी के नीचे स्थित वेधशाला है।
2. भारतीय आर्कटिक अनुसंधान बेस, हिमाद्री स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है।
3. भारत आर्कटिक परिषद का सदस्य है और स्वालबार्ड संधि -1920 का हस्ताक्षरकर्ता भी है।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में 'भारत और आर्कटिक: सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण' नामक एक आर्कटिक नीति का अनावरण किया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है-

A. 1, 2 और 3
B. 2 और 4
C. 3 और 4
D. 1, 2, 3, और 4

25. श्वसन सिंकेटियल वायरस (आरएसवी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें खांसी, बुखार आदि जैसे लक्षण शामिल हैं।
2. यह डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है।
3. आरएसवी संक्रमण को रोकने के लिए एक एंटीवायरल दवा, जिसे पालिविजुमाब कहा जाता है, उपलब्ध है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 3 B. केवल 1, 2, 3
C. केवल 1 और 2 D. केवल 2 और 3

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ।
2. इस अभ्यास में भारत, रूस, चीन तथा वियतनाम की नौसेनाओं ने भाग लिया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/कौन से सत्य नहीं है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों 1 और 2 D. न तो 1 और 2

27. आसियान समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

1. आसियान का आदर्श वाक्य 'मुक्त और खुला भारत-प्रशांत' (Free and Open Indo-Pacific) है।
2. आसियान देशों की सामूहिक आबादी 65 0 मिलियन से अधिक है और 2022 तक संयुक्त जीडीपी $3.2 ट्रिलियन है।
3. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड बैंकाक घोषणा-1967 के संस्थापक सदस्य हैं।
4. आसियान के मौलिक सिद्धांतों में बल का उपयोग या खतरे का त्याग शामिल नहीं है।

सही कोड का चयन करें-

A. केवल 2 B. केवल 3
C. केवल 1 D. कोई नहीं

28. हाल ही में चर्चा में रही जीई-सरसों (जेनेटिक इंजीनियर्ड-सरसों) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जीई-सरसों से सम्बंधित शोध जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के तहत नेशनल इंस्टीटड्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (एनआईपीजीआर) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।
2. जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है क्योंकि इससे विभिन्न जैव सुरक्षा खतरे और कीटनाशक और शाकनाशी प्रतिरोध बढ़ने की संभावना है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. कोई नहीं

उत्तर

1. C	5. D	9. C	13. A	17. A	21. B	25. A
2. C	6. C	10. D	14. B	18. C	22. D	26. A
3. C	7. B	11. D	15. D	19. B	23. D	27. A
4. C	8. B	12. C	16. D	20. A	24. C	28. C

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Admission Open Now

UDAAN
A journey to success

IAS/IPS
as a career
AFTER 12th

3 YEARS PROGRAMME

Tapping the potential of young students right after schooling through two way communication, counselling & holistic development

New Batch Starts
28th September, 2023
3:00pm-5:00pm

Aliganj (Lucknow)
A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow
Ph : 7570009014, 9506256789

Gomti Nagar (Lucknow)
CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow **Ph : 7234000501, 7234000502**

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

VINAY SINGH
(FOUNDER)

New Batch Starts

सामान्य अध्ययन

द्वारा

विनय सर

18th September, 2023

8:30am | 6:00pm

पहले क्लास फिर विश्वास

Admission Open

A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow

9506256789, 7570009002

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744